ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

वर्ष : 49 | अक्तूबर 2005 | मूल्य : 7 रुपये

बीपीओ परिदृश्य 2010 : किरण कार्णिक

सूचना सुरक्षा

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

आउटकम बजट

झरोखा जम्मू-कश्मीर का

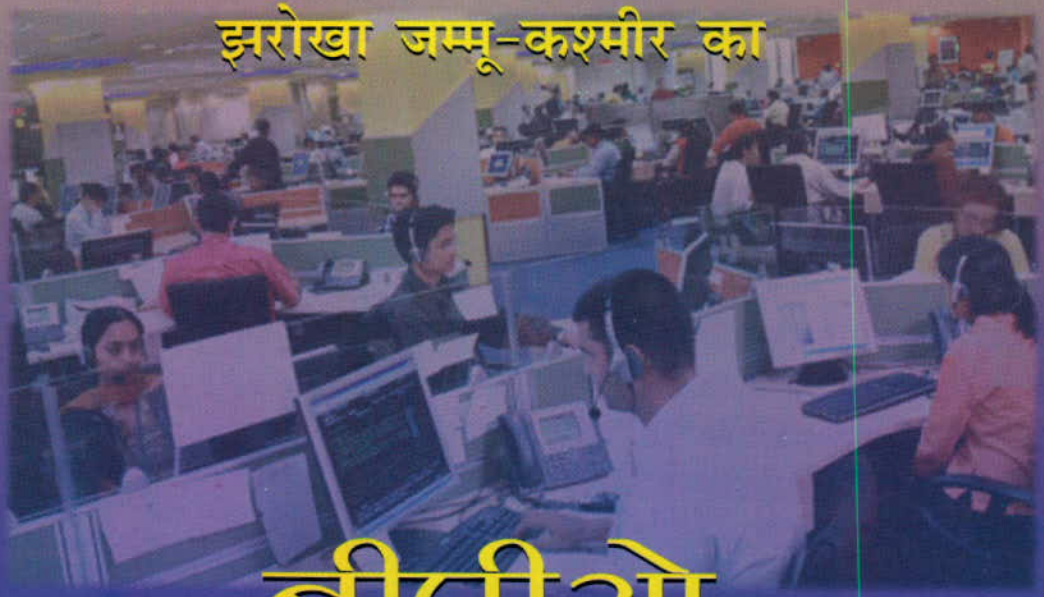

बीपीओ

टिकोमा अर्जेंटिया

योजना

वर्ष : 49 अंक 7 अक्तूबर 2005 आश्विन-कार्तिक, शक संवत 1927 कुल पृष्ठ : 68

प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

संपादक
विश्व नाथ त्रिपाठी

सहायक संपादक
राकेशरेणु

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण - **मुकुल चक्रवर्ती**

इस अंक में

संपादकीय	-	3
भारत की सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा - बीपीओ परिदृश्य 2010	किरण कार्णिक	5
नैसकॉम : 2009 तक सेवा क्षेत्र में एक करोड़ नौकरियां	-	7
आउटसोर्सिंग - अवधारणा और आयाम	उमेश चंद्र अग्रवाल	11
संख्या शक्ति है हमारी	हरीश बिजूर	17
आउटसोर्सिंग और भारत-अमरीका व्यापारिक संबंध	बदर आलम इकबाल	21
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	-	25
बीपीओ उद्योग में पारदर्शी नेतृत्व	डैन संधू	27
आउटकम बजट क्या है	-	29
भारतीय आईटी कंपनी को बड़ा ठेका	-	30
सूचना-सुरक्षा एवं अनुपालन	सुनील मेहता	31
2010 तक लगभग 35,000 अमरीकी कानूनी कार्य बाहर से कराए जाएंगे	-	33
न्यूनतम मजदूरी को अलंघ्य माना जाना चाहिए	सिद्धार्थ वरदराजन	35
जम्मू-कश्मीर : पर्यटन उद्योग	-	37
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	46
शोधयात्रा : किशमिश छंटाई की मशीन	-	51
अनुकरणीय पहल : आयुर्वेद गांव वल्कि	सव्यसाची मल्लिक	53
उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में जीवन बीमा	रवीन्द्र सिंह	54
सुनामी : पुनर्वास	-	58
मंथन : सृजनात्मकता	मनोज गैरोला 'मनु'	63
स्वास्थ्य चर्चा : शहद के गुण बेहद	मंजू पाठक	65
नये प्रकाशन : प्रगतिशील नारी	शमशेर अहमद खान	68

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर **'निदेशक, प्रकाशन विभाग'** के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु. **द्विवार्षिक :** 135 रु.; **त्रैवार्षिक :** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश :** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

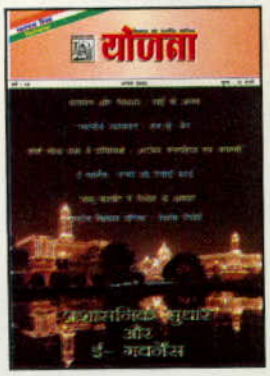

आपकी राय

अधिकारियों को दंडित भी करें

प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस पर केंद्रित इस अंक में कई महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक लेख पढ़ने को मिले। भारतीय प्रशासनिक सेवकों की सेवा में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए जिससे लोकसेवक तत्परतापूर्वक कार्य करें और राष्ट्र निर्माण की चिंता करें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्राय: विधायकों या सांसदों से शिकायत होती है किंतु योजनाओं में की जाने वाली गड़बड़ियां किसी भी नेता द्वारा नहीं की जाती। योजनाओं के कार्यान्वयन में ढिलाई अधिकारियों द्वारा ही की जाती है। विभिन्न स्तरों पर फैला हुआ भ्रष्टाचार का जाल इन्हीं प्रशासकों की करतूत है। उन्हें एक बार चयन के बाद कोई परीक्षा नहीं देनी होती तथा उन्हें अपदस्थ किए जाने का भी भय नहीं रहता। सरकार को पहल कर अच्छे सेवकों को पुरस्कृत करने के साथ गलत कार्यों में लिप्त पाए गए सेवकों को दंडित करने का भी प्रावधान करना चाहिए। ऐसा करके देश में सुशासन लाया जा सकता है। 'योजना' का यह अंक अत्यंत उपयुक्त लगा।

अमित कुमार द्विवेदी
लखनऊ

चयन ही नहीं है योग्यता का मानक

'योजना' के स्वतंत्रता दिवस विशेषांक में वाई. के. अलघ का आलेख 'प्रशासन और विकास' पढ़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश के विकास में प्रशासनिक अधिकारी की महती भूमिका रहती है क्योंकि वास्तविक राष्ट्र-निर्माता तो ब्यूरोक्रेट होते हैं। विधायिका तो बस मुहर लगाती है। अगर कोई देश पिछड़ा है तो निश्चय ही कह सकते हैं कि अमुक देश में योग्य प्रशासनिक अधिकारियों का अभाव है। किसी भी देश का कायाकल्प तभी होगा जब विधायिका और कार्यपालिका तारतम्य के साथ काम करेगी। विडंबना यह है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेट और विधायिका में 36 का आंकड़ा है। सरकार की प्रशासनिक नीति में निरर्थक दखलंदाजी के कारण आज तक हमारा देश विकसित नहीं हुआ है। जो अधिकारी मंत्रियों की चरण वंदना करते हैं उन्हें जिला और प्रमंडल का भार दे दिया जाता है और जो ईमानदारीपूर्वक कार्य करते हैं उनके पर कतर दिए जाते हैं। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोई भी देश अगर बदहाल है तो उसका मुख्य कारण गैरमेधावी अफसरशाही है। कोई व्यक्ति आईएएस व अन्य राज्य सेवा में उत्तीर्ण होता है तो यह बात हम दावे से नहीं कह सकते कि वह प्रशासनिक कार्य को अच्छी तरह से चलाएगा। परीक्षा में पास होने और प्रशासन कार्य के लिए दो अलग-अलग योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जहां परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है वहीं प्रशासन चलाना असाधारण प्रशासनिक क्षमता और कूटनीति की खोज करता है। इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि अकबर जैसे बादशाह ने अपना साम्राज्य बखूबी चलाया तो रणजीत सिंह अल्पायु में ही सिंहासीन होने के बावजूद श्रेष्ठ शासक के रूप में उभरे। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनमें उच्च प्रशासनिक योग्यता कूट-कूट कर भरी थी। सूबे के विकास में सरकार की भूमिका अहम होती है। देश की समस्त राज्य सरकारों को चाहिए कि कम से कम विकास के मामले में राजनीति न करें।

शक्तिरमण कुमार प्रसाद
पटना

प्रेरक अंक

'योजना' का आजादी अंक पढ़ने का अवसर मिला। इस बार के विशेष संयोजन के वास्ते चुनी गई एक-एक रचना विशेष संग्रहनीय है। सभी सरकारें अपने वतन की खुशहाली के लिए प्रयास करती हैं लेकिन जहां सरकार चलाने का दायित्व ऐसे कंधों पर हो जो प्रशासन के विभिन्न आयामों का अनुभव हासिल कर अपना स्वागत योग्य योगदान कर चुके हों तो सरकार की सफलता और आसान हो जाती है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री दमदार व्यक्ति हैं जिनके सर्वत्र सम्मान मिलता है। वे अपने प्रयासों और दूरदृष्टि से देश की तरक्की की राह में कितना आगे बढ़ पाते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन की जरूरत, सरकार में अभिनव सोच की जरूरत, शोधयात्रा आदि भी स्वागत योग्य हैं।

छैलबिहारी शर्मा 'इंद्र'
छाता (मथुरा)

एक से बढ़कर एक

'योजना' में 'मंथन' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित प्रत्येक लेख बेहद ज्ञानदायी एवं व्यावहारिक हुआ करते हैं। क्रमश: मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त माह में 'शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य', 'परिवर्तनशील बनिए' 'चरित्रवान बनिए', 'वैज्ञानिक और मौलिक चिंतन को प्राथमिकता दें', 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिलाती है सफलता' इत्यादि शीर्षक अतिशय सारगर्भित एवं चिंतनपरक रहे हैं। उपर्युक्त समस्त शीर्षक प्रशंसनीय हैं। अगस्त में प्रकाशित आलेख 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिलाती है सफलता' विजय प्रकाश श्रीवास्तव के दीर्घकालिक जीवन अनुभवों का एक ऐसा तथ्यपरक संकलन है जो सफलता प्राप्ति का अनुपम मार्ग उद्भासित करता है। इन लेखों की ज्ञानदायी क्षमता अत्यधिक होती है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भावी लेख भी और अधिक परिष्कृत, प्रभावशाली, सारगर्भित एवं मानसिक विकास के उत्प्रेरक होंगे।

अनुपम पी.एस. पाण्डेय
सुलतानपुर (उ.प्र.)

संपादकीय

सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवायें (आईटीईएस) और बीपीओ अब विकास गाथा बन गए हैं। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों के संघ (नैसकॉम) के अनुसार, आईटीईएस-बीपीओ निर्यात ने वर्ष 2004-05 के दौरान 44.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 5.2 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया। भारत के कुल आईटीईएस- बीपीओ निर्यात के दो-तिहाई हिस्से के साथ अमरीका अभी भी प्रमुख बाजार बना हुआ है। इसमें पश्चिमी यूरोप, खासकर इंग्लैंड की 20 प्रतिशत की भागीदारी है। 35 प्रतिशत कर्मचारी-आधार के साथ ग्राहक तथा समर्थन सेवा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा बनी हुई है। वित्त प्रशासन तथा अंतर्वस्तु विकास इसके अगले तीन बड़े भाग हैं।

आने वाले दिनों में ज्ञान अथवा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बड़े पैमाने पर उभरने वाला है। इसमें स्वास्थ्य रक्षा, दवायें, जैव प्रौद्योगिकी, कानूनी सेवायें, बौद्धिक संपदा अनुसंधान आदि शामिल हैं। लेकिन बीपीओ-आईटीईएस उद्योग अभी भी अपने आरंभिक चरण में है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

हाल ही में इस उद्योग को महत्वपूर्ण तथ्यों के लीक होने की घटनाओं के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। अभी भारत में पूर्णतया सुरक्षित डेटा संरक्षण कानून नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को ई-कॉमर्स को संभव बनाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन यह डेटा सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं साबित हो पा रहा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता में आंकड़ा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का निबटान कर पाने के लिए उचित प्रावधानों का अभाव है। आंकड़ों की चोरी का मामला हैकिंग की तुलना में अधिक गंभीर है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए भारत को संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराना होगा। अभी बीपीओ क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के अतीत की जांच के लिए हमारे पास किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा अंक प्रणाली नहीं है।

वर्तमान में भारतीय बीपीओ क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष के आरंभ में आईटीईएस-बीपीओ रणनीतिक सम्मेलन में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2007 तक इस क्षेत्र में काम तीन गुना बढ़ जाएगा और तब 2.5 से 3 लाख प्रशिक्षित लोगों की कमी हो सकती है। इसलिए तत्काल मूल्यांकन एवं प्रमाणन कार्यक्रमों की योजना बनाना जरूरी है। इस संदर्भ में बीपीओ उम्मीदवारों के लिए जांच परीक्षा आयोजित करने की नैसकॉम की घोषणा उत्साहवर्धक है। इस जांच परीक्षा का लक्ष्य प्रशिक्षण योग्य कार्यबल को नियुक्ति योग्य कार्यबल में बदलना होगा। हमारे निगम क्षेत्र को कर्मचारी-प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना होगा। तीसरे पक्ष की मदद से कर्मचारियों के अतीत की जांच का काम भी आरंभ किया जाना चाहिए। बीपीओ क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अपेक्षित कौशल की जांच को निर्धारित करना तथा इस क्षेत्र द्वारा चयनित/नियुक्त लोगों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण-प्रविधि का विकास भी जरूरी है।

बीपीओ का अभिप्राय केवल आंकड़ा प्रक्रमण अथवा कॉल सेंटर ही नहीं है। हमें प्राथमिक बीपीओ, अर्थात भर्ती करने वाली फर्मों, मानव संसाधन परामर्शदाताओं, प्रशिक्षण, परिवहन, भोजन आदि की मदद पहुंचाने वाली समूची प्रणाली को समग्रता में देखना होगा। इन सभी सहायक क्षेत्रों का स्वास्थ्य बीपीओ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

अधिक तनाव, पाली में काम, काम की लंबी अवधि आदि इस क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी समस्यायें हैं जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में व्यवधान उपस्थित कर सकती हैं। इस सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक सोचे जाने की जरूरत है। ❑

नामांकन जारी

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:

* Prelims
* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains & Prelims
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

(पूर्णतः संशोधित एवं परिमार्जित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-

MAINS + PRE. - 3500/-

डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

***UPSC** के साथ **UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS** की भी तैयारी*

नया सत्र : दिल्ली - 9 नवंबर ★ इलाहाबाद - 2 अक्टूबर, 2005

-: लोक प्रशासन :-

Mains के साथ-साथ Pre. के लिये भी बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Cell.: 9810651005, 09335117608

Sanjay Singh
Regional Director (Allahabad)
Cell. : 9839746184

Shashi Bhushan
Director
Cell. : 9871359750

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9

Phone : 27655134, 39544250. Cell.: 9810651005 • e-mail : atullohiya@rediffmail.com

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

YH/10/5/01

भारत की सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा - बीपीओ परिदृश्य 2010

❍ किरण कार्णिक

भारत की सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा - आईटीईएस-बीपीओ उद्योग, देश के कुल आईसीटी उद्योग में उच्च संभावनाओं वाला ऊंचे विकास का क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2004-05 में आईटी-आईटीईएस उद्योग के कुल राजस्व में 20 प्रतिशत का योगदान किया है।

इस अवधि में उच्चतर विशेषज्ञता स्तर, ज्यादा गहराई और प्रतियोगिता की ओर कदम बढ़ाते हुए इस उद्योग ने अपने विकास के तीसरे चरण में प्रवेश किया। सभी ने इस उद्योग में परिपक्वता और विकास के लक्षण देखे हैं। आईटीईएस-बीपीओ कंपनियों ने पिछले दो वर्षों में अपने ग्राहकों के साथ दीर्घावधि करार किए हैं, सेवा के क्षेत्र में विस्तार किया है, पैमाने तय किए हैं, मूल्य निर्धारण के अपने आदर्श विकसित किए हैं और ह्रास जैसे परेशान करने वाले मुद्दों का दृढ़ता से सामना किया है।

अनेक एम एंड ए गतिविधियों के फलस्वरूप दूसरे देशों से आउटसोर्सिंग कराने के उद्देश्य को मजबूती मिली है, जिससे उद्योग और भी सुगठित हुआ है। इसने विश्व की अनेक प्रमुख आईटी और गैर-आईटी कंपनियों को भारत के आईटीईएस-बीपीओ बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु तैयार करने में मदद की है।

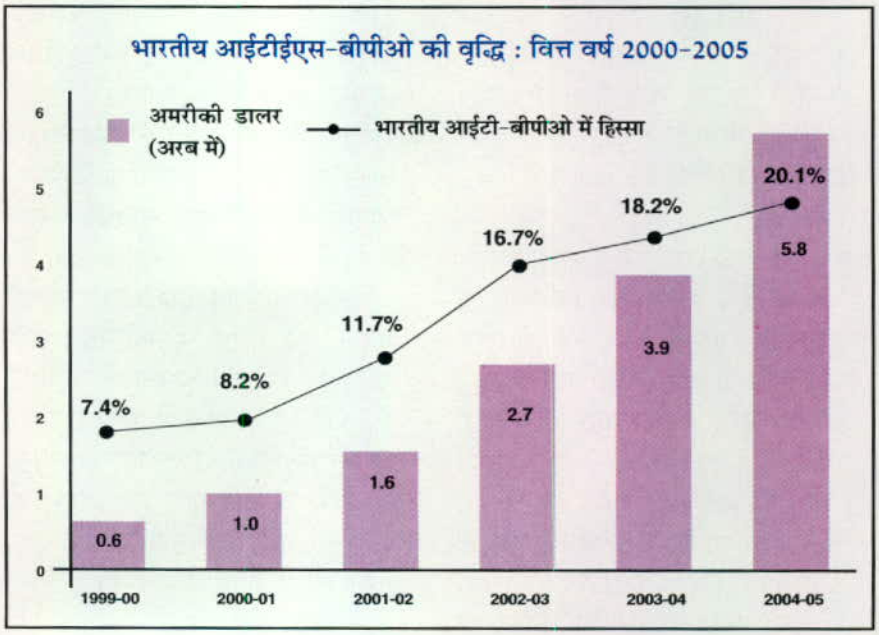

चित्र (क)

बड़ी अपेक्षाएं

आईसीटी उद्योग द्वारा वर्ष 2004-05 में अर्जित राजस्व में करीब 60 प्रतिशत भाग आईटी सेवा उद्योग का रहा है। इसके बावजूद, तेजी से बढ़ रहे आईटीईएस-बीपीओ बाजार से भविष्य में भारत के लिए विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

इसके अनेक कारण हैं

- भारत के आईटीईएस-बीपीओ बाजार में रिकार्ड वृद्धि हो रही है (अक्सर यह 50 प्रतिशत वार्षिक से भी अधिक होता है)। वर्ष 2004-05 के दौरान इस उद्योग ने लगभग 5 अरब 80 करोड़ डालर का राजस्व अर्जित कर 44.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- उद्योग ने 2000-05 की अवधि की तुलना में इस चरण में कुल मिलाकर 56.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दिखाई है, जो किसी भी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र से अधिक है।
- भारतीय आईटीईएस-बीपीओ उद्योग देश में रोजगार के अवसर सृजित करने वाले सबसे बड़े उद्योगों में गिना जाता है। अकेले 2004-05 में ही उद्योग में 95 हजार नयी नौकरियां सृजित हुईं। इसे मिलाकर वर्ष के दौरान 3 लाख 48 हजार लोग इस क्षेत्र में सेवारत थे।
- नैसकॉम-मैकिन्से के आकलन के अनुसार 2008-09 तक इस उद्योग में प्रोफेशनलों के लिए दस लाख से भी अधिक सेवा अवसर सृजित होंगे।
- अनेक प्रमुख गैर-आईटी व्यावसायिक सेवा फर्मों ने भारत में, खासकर अनुसंधान और विश्लेषण कार्यों में सहायता के क्षेत्र में, अपने आईटीईएस-बीपीओ केंद्र स्थापित

किए हैं। इस क्षेत्र में पहले-पहल आने वालों में मैकिन्से एंड कं, डेलॉइट कंसल्टिंग, ई. एंड वाई., रायटर्स जैसी नामी-गिरामी कंपनियां शामिल हैं।

- अधिक से अधिक संगठनों द्वारा भारत में आईटीईएस-बीपीओ कारोबार शुरू करने के साथ ही विश्व की अनेक विशालकाय आईटी और गैर-आईटी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं।
- भारत में जो कंपनियां पहले से ही कार्यरत हैं, वे भी ऊपर उठ रही हैं और अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। देश में काम कर रही प्राय: सभी बहुराष्ट्रीय आईटीईएस-बीपीओ कंपनियों ने या तो अपने वर्तमान सेवा केंद्रों में सीटों की संख्या बढ़ाई है, या अतिरिक्त बीपीओ केंद्र खोलने में निवेश किया है।
- भारत के आईटी उद्योग में भी आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र का व्यापक विविधीकरण हुआ है। लगभग सभी बड़ी भारतीय आईटी-सेवा कंपनियों ने आईटीईएस-बीपीओ बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की है और ग्राहकों को मिश्रित और समेकित सेवा का विकल्प पेश किया है।
- वित्तीय/बैंकिंग और स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्थाओं जैसे विशिष्ट कार्यक्षेत्र में दक्ष, प्रमुख गैर-आईटी संगठन भी आईटीईएस-बीपीओ बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इससे उद्योग को मूल्य-शृंखला में ऊपर उठने और नये-नये क्षेत्रों में उन्नत सेवा का अवसर सुलभ कराने में मदद मिली है।
- भारतीय और प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थन के अलावा देश की सरकार भी आईटीईएस-बीपीओ को खूब बढ़ावा दे रही है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि देश का नियामक वातावरण उद्योग के विकास के अनुकूल बना रहने के साथ विदेशी निवेश के लिए भी आकर्षक बना रहे।
- विशिष्ट और उच्च तकनीकी कौशल वाले आईटी सेवा क्षेत्र की तुलना में आईटीईएस-बीपीओ बाजार में मानव संसाधन विकास सरल होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुशल और उच्च प्रशिक्षित लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। आईटीईएस- बीपीओ उद्योग भारत के विशाल अंग्रेजी भाषी स्नातकों के भंडार से लोगों को आसानी से चुनकर उनको वांछित प्रशिक्षण देकर उपयोगी बना सकता है। जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए उद्योग सेवानिवृत्त लोगों को भी काम पर रख सकता है।

विश्व की प्रमुख व्यापार आसूचना फर्मों और नैसकॉम के आईटीईएस-बीपीओ उद्योग के अपने विश्लेषण के अनुसार, आने वाले समय में यह उद्योग और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और नयी ऊंचाइयां हासिल करेगा।

भारत के आईटीईएस-बीपीओ उद्योग की प्रमुख हस्तियों और विचारक गुरुओं का विश्वास है कि वर्ष 2010 तक यह उद्योग पारंपरिक रूप से सुदृढ़ आईटी सेवा उद्योग से प्राप्त होने राजस्व की बराबरी हासिल कर लेगा। इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों और प्रतिष्ठित परामर्शदात्री फर्मों के अलावा भारत सरकार भी आईटीईएस-बीपीओ उद्योग की सुदृढ़ता और समृद्धि के बारे में सोच रही है। वर्ष 2010 तक निर्यात और घरेलू बाजार में इसकी जबरदस्त हिस्सेदारी होगी।

वर्तमान आशा इस तथ्य पर आधारित है कि आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र भी उसी दिशा में बढ़ता प्रतीत होता है जिस ओर पिछले वर्षों में आईटी सेवा बाजार बढ़ रहा था। यह क्षेत्र भी उसी की तरह कारोबार पद्धतियां और आदर्श अपना कर सफलता हासिल करने में जुटा हुआ है।

उच्च अवसरों वाले बाजार पर दस्तक

आईटी सेवा उद्योग की भांति आईटीईएस-बीपीओ उद्योग भी मुख्यत: अमरीकी बाजार में ही जोर-आजमाइश कर रहा है। क्योंकि अमरीका का बाजार ही ऐसा बाजार है जहां

तालिका

प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय आईटीईएस-बीपीओ निर्यात

वित्त वर्ष 2003-05 (अनुमान)

सेवा क्षेत्र	वित्त वर्ष 2002-03		वित्त वर्ष 2003-04		वित्त वर्ष 2004-05	
10 लाख अमरीकी डालर	कर्मचारी*	राजस्व**	कर्मचारी*	राजस्व**	कर्मचारी*	राजस्व**
ग्राहक सेवा	66,400	830.0	96,000	1,200.0	122,000	1,500.0
भुगतान सेवायें	12,000	230.0	21,000	43.0	30,000	620.0
वित्त	25,500	540.0	41,000	835.0	64,000	1,300.0
प्रशासन	26,000	325.0	40,000	540.0	57,000	840.0
मानव संसाधन	2,100	45.0	4,500	75.0	10,000	165.0
विषयवस्तु विकास	48,000	510.0	51,000	555.0	65,000	670.0
योग	**180,000**	**2,480**	**253,500**	**3,630**	**348,000**	**5,095**

स्रोत : नैसकॉम

नैसकॉम : 2009 तक सेवा क्षेत्र में एक करोड़ नौकरियां

नैसकॉम का कहना है कि सेवा क्षेत्र में भारतीयों को 2009 तक एक करोड़ नौकरियां उपलब्ध होंगी। 20वीं सदी के अंत में सूचना प्रौद्योगिकी में आए चढ़ाव की तरह 21वीं सदी सेवा क्षेत्र की होगी।

इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक सरकार को कई सेवा क्षेत्रों को उदार बनाने की जरूरत है। दूसरे, भारत को राजनयिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए समुद्रपारीय बाजार में भारतीयों के लिए जगह बनवानी चाहिए, वीजा नियम उदार बनवाने चाहिए और जिंस व्यापार की तरह भारतीय जनशक्ति के लिए भी नौकरियों में हिस्सा सुनिश्चित करना चाहिए तथा इसी प्रक्रिया में भारत में पूंजी निवेश प्राप्त करना चाहिए।

ज्ञान उद्योग को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नक्शे पर लाने के उद्देश्य से सेवा क्षेत्र में अग्रणी रहे देशों के संघ ने सेवा क्षेत्र की ताकतों से हाथ मिला लिया है। अंतरराष्ट्रीय सेवा गठबंधन में भारत (नैसकॉम) आस्ट्रेलियन सर्विसेज राउंडटेबल, चिलियन सर्विसेज कोअलिशन आफ एक्सपोर्टर्स, यूरोपियन सर्विसेज फोरम, जापान सर्विस नेटवर्क और यूएस कोअलिशन आफ सर्विस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इन्होंने हाल के जेनेवा के विश्व व्यापार संगठन अधिवेशन के समय प्रमुख देशों के राजदूतों के बीच जम कर अपना पक्ष रखा।

उनका मुख्य मुद्दा इस प्रकार है - दोहा वार्ता तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सेवाओं को भी खेती की तरह न माना जाए।

नैसकॉम के उपाध्यक्ष सुनील मेहता ने हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय को एक मसौदा प्रस्तुत किया है जो गाट्स को भारत के प्रस्ताव के बारे में है। हाल ही में सेवाओं पर जोर बढ़ रहा है क्योंकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यह बढ़ता जा रहा है।

लेकिन इसका कारण भारत का नया आत्मविश्वास जाहिर होता है। अपने स्वरूप में नैसकॉम ने सेवाओं को पहले बहुपक्षीय क्षेत्र से अलग रखा था। उसे द्विपक्षीय समझौतों तक सीमित रखा गया था। अब इसका स्वरूप और क्षेत्र बढ़ रहा है जिसका मतलब है कि विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर बातचीत करते समय इसका इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में किया जा सकता है। अगर भारत ने इस उदीयमान क्षेत्र का महत्व न समझा तो खतरा यह है कि इससे अन्य देशों को व्यापार वार्ताओं के समय भारत के मुकाबले एक अच्छा मुद्दा मिल जाएगा। असलियत यह है कि अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में सेवायें भारत का एक विशेष मुद्दा है।

जहां जोर सूचना प्रौद्योगिकी वाली सेवाओं पर रहा है, वहीं मेजबानी, दृश्य-श्रव्य और वितरण जैसे कुछ अन्य क्षेत्र भी संभावनापूर्ण हैं। नैसकॉम के श्री मेहता का कहना है कि पहला कदम यह होगा कि भारत पहले आंतरिक रूप से इस क्षेत्र को प्रतिबंध मुक्त करे।

एनीमेशन क्षेत्र में जहां एक तरफ बहुराष्ट्रीय निगमों की धाक है, वहीं नैसकॉम का अनुमान है कि एनीमेशन उत्पादन सेवाओं के जरिये भारत ने 2004 में करीब 20-30 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एनीमेशन उद्योग काफी ज्यादा विकास की ओर उन्मुख है। ❑

(स्रोत: एजेंसियां और समाचारपत्र)

के तकनीकी क्षेत्र में प्राय: सभी कंपनियों के लिये सबसे बड़ा मैदान उपलब्ध है। आईटीईएस-बीपीओ उद्योग ने अपने समस्त निर्यात राजस्व का दो-तिहाई भाग केवल अमरीकी बाजार से ही प्राप्त किया है। अन्य बाजार जो भारतीय आईटीईएस-बीपीओ उद्योग के राडार में छाए रहे उनमें इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप के देश प्रमुख हैं। इन देशों से कुल निर्यात राजस्व का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ।

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय आईटीईएस-बीपीओ संगठन इस तरह का कार्यबल तैयार कर रहा है, जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी कुशलता का दावा कर रहा है। यूरोप और एशिया प्रशांत के बाजारों की उच्च संभावनाओं वाले किंतु अब तक अछूते क्षेत्रों में अपनी पैठ जमाने के लिए ये कंपनियां अब स्पैनिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, मंदारिन और कैंटोनीज़ (चीनी) भाषाओं के जानकार युवाओं को भी नियुक्त कर रही हैं।

नये सेवा क्षेत्रों का पता लगाना

आजकल भारतीय आईटीईएस-बीपीओ कंपनियां, नयी सेवा लाइनों की खोज में जुटी हैं, भले ही वे बिल्कुल नवजात अवस्था में हों, और ग्राहकों की देखभाल और सहायता सेवाओं के मंचों से आगे बढ़ रही हैं। यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत है।

आज, ग्राहक की देखभाल और सहायता सेवायें आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र की सबसे बड़ी सेवायें हैं। इस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का कुल 38 प्रतिशत इसी सेवा प्रदाय में लगा है। साथ ही, इस उद्योग की समस्त आय में से एक तिहाई राजस्व इसी सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। परंतु अब नयी-नयी सेवाओं के क्षेत्र भी क्षितिज पर दिखाई देने लगे हैं, जिनसे अच्छा राजस्व प्राप्त होने के संकेत हैं।

वित्त (राजस्व योगदान 23 प्रतिशत), प्रशासन (राजस्व योगदान 14.9 प्रतिशत) और विषयवस्तु विकास (15 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 2010 तक इन क्षेत्रों में और भी बेहतर प्रदर्शन होगा।

उद्योग के लिये यह बड़े प्रोत्साहन की बात है कि अनेक खिलाड़ी अपने आउटसोर्सिंग कार्य का विस्तार कर रहे हैं। वे अब ग्राहक विश्लेषण और सीआरएम, मानव संसाधन आउटसोर्सिंग, विधिक लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन), वित्तीय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (इक्विटी अनुसंधान सहायता), धन प्रबंधन और प्रशासन, जोखिम का पूर्वाकलन, बीमा संबंधी विश्लेषण, वस्तुओं की प्रोसेसिंग और ऋण संग्रहण एवं उगाही जैसे नये-नये क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहे हैं।

आईटीईएस-बीपीओ उद्योग धीरे-धीरे अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। अब

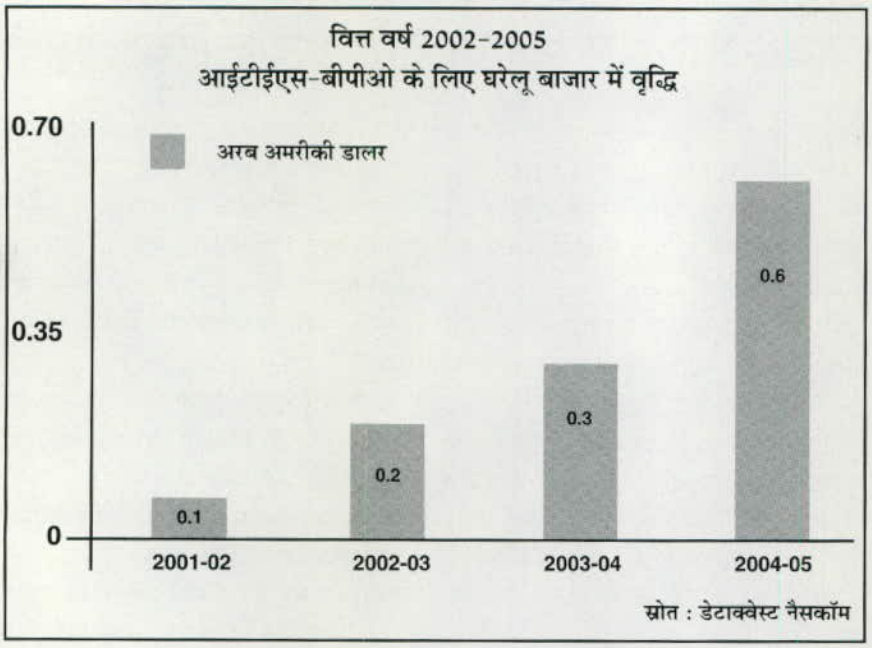

चित्र (ख)

यह ज्ञान अर्थात नालेज की प्रोसेस आउट रिसोर्सिंग (केपीओ) के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में उच्चतर स्तर की अनुसंधान और विश्लेषण आधारित सेवा की दरकार है, चाहे वह पारंपरिक सेवा क्षेत्र से जुड़ी हो या फिर नये व्यापार वाले क्षेत्र से ही क्यों न हो। आईटीईएस-बीपीओ के कारोबार में आई कुछ प्रारंभिक और प्रमुख कंपनियों ने केपीओ के अंतर्गत पहले ही स्वास्थ्य रक्षा, औषधि निर्माण और बायो-टेक्नालाजी, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, वाहन और विमान निर्माता कंपनियों में डिजाइन और विकास कार्य तथा मनोरंजन के क्षेत्र में एनीमेशन और ग्राफिक्स जैसे क्षेत्रों पर अपनी नजर गड़ा रखी है।

पारंपरिक और नये क्षेत्रों में मजबूती

यद्यपि आईटीईएस-बीपीओ उद्योग मुख्य रूप से वित्तीय सेवा के क्षेत्र में ही जोर दे रहा है। कई प्रमुख खिलाड़ी दूरसंचार, स्वास्थ्य रक्षा और विमान सेवा के क्षेत्र में भी अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने में लगे हैं। वित्तीय सेवा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारतीय आईटीईएस-बीपीओ कंपनियों ने सर्वाधिक सफलता प्राप्त की है। कई सेवा प्रदाता तो साधारण लेखांकन, बिलिंग और भुगतान सेवा से आगे बढ़कर अधिक ऊंचे मूल्य वाले क्षेत्रों जैसे, इक्विटी अनुसंधान और निवेश अनुसंधान सहायता, वित्तीय आंकड़ों की छानबीन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग, बीमा के दावों संबंधी कार्यवाही, जोखिम का पूर्वाकलन और बीमा मूल्यांकन (एक्चूरियल) सहायता क्षेत्र में सेवा प्रदान करने लगे हैं।

जहां तक स्वास्थ्य रक्षा, दूरसंचार और विमान सेवा क्षेत्रों का संबंध है, वे एक उभरते हुए बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय आईटीईएस-बीपीओ उद्योग ने पहले से ही इस तथ्य का संज्ञान ले रखा है और आगे बढ़ कर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारतीय आईटीईएस-बीपीओ कंपनियां वर्तमान में इन क्षेत्रों में, ग्राहक सहायता, तकनीकी सहायता, डेस्क सपोर्ट, समुद्रपारीय इंजीनियरी और अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रही हैं।

तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार

भारतीय आईटीईएस-बीपीओ के बारे में विश्लेषकों के इतने अधिक आशावान होने के पीछे तथ्य यह है कि ये सेवायें धीरे-धीरे भारत के घरेलू क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। स्थानीय भारतीय कंपनियों से आईटीईएस- बीपीओ सेवाओं की मांग में अचानक आई वृद्धि ने विक्रेताओं के लिए अवसरों का ढेर लगा दिया है। नैसकॉम अनुसंधान के अनुसार, आईटीईएस-बीपीओ

नैसकॉम पहल आदर्श रूप से अंतर्संबंधित हैं

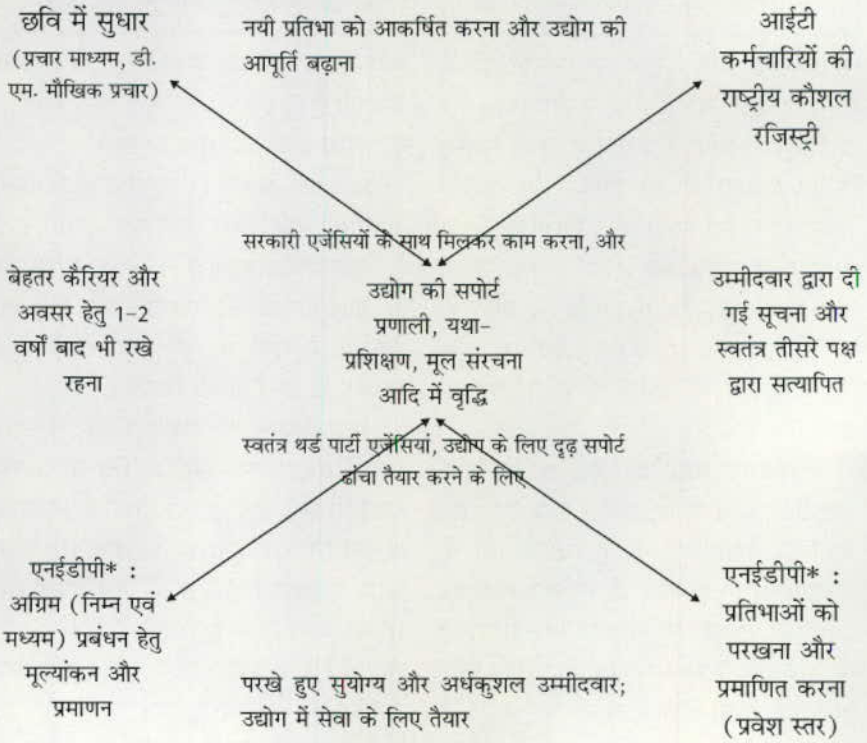

*एनईडीपी : नैसकॉस इक्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम

उद्योग ने वर्ष 2004-05 के दौरान घरेलू भारतीय बाजार से 60 करोड़ अमरीकी डालर से भी अधिक का राजस्व कमाया।

बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा) क्षेत्रों के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र के ग्राहकों ने घरेलू बाजार में आईटीईएस-बीपीओ कंपनियों की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान किया है।

ग्राहक-केंद्रित बीएफएसआई बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा और दूरसंचार कंपनियों ने कड़ी प्रतियोगिता से संघर्ष करते हुए आईटीईएस-बीपीओ सेवा प्रदाताओं का सहारा लिया जिन्होंने उनके ग्राहकों के संतोष और सीआरएम वचनबद्धताओं को संभाला। दूरसंचार और बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा कंपनियों ने आईटीईएस-बीपीओ विक्रेताओं की सेवाओं के आधार पर अपने ग्राहकों को 24 घंटे टेलीफोन पर मदद (सूचना) और बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई।

इस क्षेत्र में जो अन्य सकारात्मक बात हुई, वह यह कि वर्ष 2004-05 के दौरान, आईटीईएस-बीपीओ की घरेलू मांग, शुरुआती दौर की खास तरह की काल-सेंटर सेवाओं के क्षेत्र से हट कर कुछ दूसरी ओर बढ़ी। अनेक प्रमुख आईटीईएस-बीपीओ खिलाड़ियों आवाज मुक्त कार्य में वृद्धि दर्ज की। यह घरेलू बाजार में उद्योग के बढ़ते अनुभव और विशेषज्ञता का प्रतीक है।

नैसकॉम आईटीईएस-बीपीओ पहल : सही दिशा में कदम

बढ़ते श्रम लागत और मांग में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रतिभाओं की उपलब्धता पर पड़ते दबाव के कारण कुछ पर्यवेक्षक भारत में होने वाले कारोबार से लाभ के प्रति सवाल उठाने लगे हैं। इसके बावजूद भारतीय आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग आईटीईएस-बीपीओ उद्योग के लिए विश्व का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

देश में काम कर रही प्रमुख देशी और विदेशी कंपनियों से हाल ही में मिले प्रमाणों से पता चलता है कि प्रबंधन दक्षता, परिवर्तन दर को रोकने के लिए अग्रिम बाजार से चतुराई पूर्वक सुरक्षा, पुनरोपयोगी घटकों का इस्तेमाल कर कार्य दक्षता में सुधार और उनका बेहतर उपयोग, मितव्ययिता के उन्नत मानदंड अपना कर निश्चित लागत को कम करने से स्पर्धात्मकता बनाए रखी जा सकती है।

अन्य देशों की तुलना में भारत के सुदीर्घ नेतृत्व के पीछे विशाल और निरंतर बढ़ती हुई सुयोग्य अंग्रेजी भाषी जनशक्ति; विश्वस्तरीय मानकों के अनुसरण पर बल, सूचना की सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से अपनाना, दूरसंचार व्यवस्था का स्तर ऊंचा उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर और लागत के अनुसार लाना, बुनियादी ढांचे को सुधारने और नीतियों के विकास पर जोर और इस उद्योग के विकास में सहायक प्रभावी नियामक व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत कारण हैं।

नैसकॉम ने उद्योग के सक्रिय सहयोग से एक ऐसा मूलभूत ढांचा तैयार किया है, जो जोखिम और मंदी जैसे मुद्दों को नकारने में उद्योग की पूरी मदद करेगा। मानव संसाधन और सूचना सुरक्षा के मामलों में यह व्यवस्था खास लाभदायी होगी। चित्र (क) दर्शाता है कि यह ढांचा किसा प्रकार एक-दूसरे से और संबंधित उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है।

नैसकॉम आईटीईएस-बीपीओ फोरम का गठन : मानव संसाधन रणनीति समूह

एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और बंगलौर में मानव संसाधन और आईटीईएस-बीपीओ उद्योग के व्यापार प्रमुखों को एक साथ लाने के लिए नैसकॉम ने एक बैठक आयोजित की, जिससे लघु अवधि के लाभों और दीर्घकालीन रणनीति की योजना बनाने की समस्याओं को मित्रतापूर्ण वातावरण में हल किया जा सके। जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका सारांश नीचे प्रस्तुत है :

- नियुक्तियों के मामले में आचार-संहिता (पूर्णतया उद्योग के खिलाड़ियों पर निर्भर)
- सदस्यों के बीच अर्थपूर्ण आंकड़ों का आदान-प्रदान
- मानव संसाधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यव्यवहार का आदान-प्रदान
- आईटी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पंजी तैयार करना
- उद्योग की प्रमुख हस्तियों की मीडिया से बातचीत की पहल करना और शिक्षण संस्थाओं से करार करना
- ह्रास नियंत्रण अभ्यास
- स्वास्थ्य और बचाव संबंधी सर्वश्रेष्ठ उपायों का आदान प्रदान।

उद्योग की छवि में सुधार: मुद्दे और चुनौतियां

- निर्यात व्यापार में तेज वृद्धि के विरोधाभासी दबाव और वृद्धि के मुकाबले के लिए क्षमताओं के सृजन का तीक्ष्ण दबाव।
- द्रुतगामी वेतन वृद्धि और अपने प्रतियोगियों के यहां से उनके कर्मचारियों को तोड़कर अपने यहां लाना।
- संभावी भर्तियां समग्र स्नातक पूल का मुश्किल से 20 प्रतिशत ही होती हैं; उनमें से अधिकतर लोग उद्योग को लघु-अवधि का कैरियर देने वाले के रूप में ही देखते हैं। एक तरह से, इसकी द्रुतगामी वृद्धि के कारण इसकी तुलना डॉट कॉम सेक्टर से की जाती है और माना जाता है कि इसका डूबना या नष्ट होना निश्चित है। इसके अलावा ज्यादातर रात में काम करने के कारण अधिकांश कर्मचारी 2-3 वर्षों से अधिक काम नहीं कर पाते।
- मीडिया में अनेक नकारात्मक कहानियां और मौखिक प्रचार, स्वास्थ्य पर प्रभाव, तनाव, सामाजिक जीवन और अनैतिक व्यवहार के बारे में लोगों में मिथ्या धारणा है। इससे अभिभावकों, गुरुओं, शिक्षकों जैसे मत-निर्माताओं के बीच इस उद्योग में कैरियर के अवसरों के बारे में नकारात्मक धारणा बनती है।
- कुछ विज्ञापनों में भर्ती के लिए उद्योग को 'युवा, मौजमस्ती और लाभप्रद' रूप में पेश किया जाता है। इससे संभवत: कैरियर के प्रति गंभीर व्यक्तियों का हतोत्साहन होता है।

प्लेसमेंट एजेंट अथवा योग्य कर्मियों की तलाश करने वाले पेशेवर लोग, वेतन और भर्ती के बारे में ऊंचे-ऊंचे दावे करते हैं, ताकि एक कंपनी के उम्मीदवार को लोभ दिखाकर उसे दूसरी कंपनी में लाया जा सके। ❑

(लेखक नैसकॉम के अध्यक्ष हैं)

PUBLIC ADMINISTRATION

ताकि मुख्य परीक्षा में गलतियां न हों
कैसे लिखें सुव्यवस्थित उत्तर

MAINS CUM PRE BATCH - 2006

★ क्या अच्छा अभिशासन (Good Governance) और लोक तंत्र (Democracy) एक-दूसरे के विरोधाभासी (Contradictory) हैं (UPSC-2004), यदि हाँ तो कैसे? अच्छे अभिशासन के घटक क्या हैं - राज्य (State), बाजार (Market) तथा नागरिक समाज (Civil Society), लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है - उत्तरदायी शासन (Accountable Governance), अच्छा अभिशासन एकीकृत अभिशासन पर बल देता है तथा बाजार व नागरिक समाज को शासन की व्यापक प्रक्रिया में समाहित करता है। लेकिन बाजार (Market) व नागरिक समाज (NGO's) का उत्तरदायित्व (Accountability) कैसे सुनिश्चित हो यह स्पष्ट नहीं करता।

(भारतीय संबिधान का अनुच्छेद 13 राज्य का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।)

पुनः लोकतंत्र से आशय है स्वशासन (Self rule) जिसमें अपने लिए अभिशासन का स्वरूप सुनिश्चित करना भी समावेशित हैं, जबकि अच्छा अभिशासन विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है, जिसका उल्लेख विश्व बैंक द्वारा पहली बार सन् 1989 में तथा दूसरी बार सन् 1992 में किया गया तथा इस संकल्पना को विकास मूलतः तृतीय विश्व के "अति ऋणीकृत देशों {HIPCs-Highly Indebted Poor Countries} के सन्दर्भ में ऋण प्राप्त करने की पूर्वशर्त के रूप में किया गया।

(HIPCs - को विश्व बैंक के प्रख्यात अर्थशास्त्री William Easterly नें विफल राज्यों (Failed States) की संज्ञा दी है क्यों कि विश्व बैंक 1950 से अब तक तीन बार Toronto, Trinidad & Neples Rounds इनके ऋण माफ कर चुका है)

अतः अधिकतर राजनीतिक विश्लेषक अच्छे अभिशासन की संकल्पना को लोक तांत्रिक राष्ट्रों की संप्रभुता (Sovereignty) पर आक्षेप के रूप में मानते हैं।

(पूरा उत्तर लिखने के लिए विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1989 व 1992 में दी गई विमाओं का विश्लेषण करना आवश्यक होगा)

★ क्या सूचना का अधिकार (Right-to-Information) को शासन का अधिकार (Right-to-Governance) का पर्याय माना जाना चाहिए? क्या सूचना का अधिकार भारत में मौन न्यायिक क्रांति का अग्रदूत बन सकता है (Mains-2004). निश्चित रूप से- यदि सूचना के अधिकार को अन्य सहवर्ती संकल्पनाओं - नव सामाजिक अधिकार सिद्धान्त (New Social Right Theory) तथा सामाजिक क्रिया याचिकावाद (Social Action Litigation) से जोड़कर विश्लेषित किया जाय तो यह समाज के उस वर्ग का भी सशक्तिकरण कर सकता है जो दशकों से भारतीय लोकतंत्र के सीमान्त पर जीने को अभिशप्त रहा है।

(Case Studies के लिए देखें योजना पत्रिका के आगामी अंक)

★ क्या तुलनात्मक लोक प्रशासन (CPA) व अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन (International Administration) परस्पर संबधित संकल्पनायें हैं। (UPSC-2004), क्या विगत एक दशक में इन दोनों उपविधाओं (Sub-Field) का समेकन (Convergence) हुआ है, जैसा कि Ferrel Heady अपनी नवीनतम कृति "Issues-in-Comprative & International Administration (1992)" में रेखांकित करते हैं। विश्व स्तर पर इस दिशा में प्रयासरत संस्था {The Section of International & Comparative Administration - SICA} के उद्देश्य क्या हैं? क्या भूमण्डलीकरण व नवलोकप्रबंधन ने तुलनात्मक अध्यनों का स्वरूप बदल दिया है, जैसा कि G.E. Caden & Neomi Caden अपनी नवीनतम कृति "Towards the Future of Comparative Public Administration (2000)" में रेखांकित करते हैं, क्या अब तुलनात्मक लोक प्रसाशन को नया नाम दे दिया जाना चाहिए जिसकी आवश्यक्ता Ali Farazmand अपनी कृति "The New World Order & Global Public Administration (1999)" में दर्शाते है।

मौलिक विश्लेषण के लिए संकल्पनाओं की पूर्ण समझ व अधतन जानकारी आवश्यक है।

★ क्या विकास प्रशासन का समकालीन प्रतिमान (सशक्तिकरण प्रतिमान - Empowerment Approach) (UPSC-2004) - सतत्ता के सामान्य सिद्धांत General Theory of Sustainability से अभिप्रेरित हैं जैसा कि R. Flint & M. Danner अपनी कृति "The Nexus of Sustainability & Social Equity (2001)" में दर्शाते हैं तथा जिसका प्रतिबिंबन UNDP के Millennium Project (2002) तथा Millennium Development Goals (MDGs) में भी होता है।

सशक्तिकरण की विमाऐं - आर्थिक सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सहभागिता व उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक जीविता (Cultural vitality), संस्थागत प्रभावशीलता, समेकित प्रयास व अनुकूलित प्रबंधन (Adaptive Managment)

(60 अंक के प्रश्न में इन विमाओं का संक्षिप्त विश्लेशण आवश्यक होगा)

सटीक विश्लेषण के लिए लोक प्रशासन में संकल्पनाओं को अन्तर्सम्बन्धित करके समझना आवश्यक है।

FREE INTRO CLASS

हिन्दी माध्यम में - 24 और 25 अक्टूबर 2005 - प्रातः 9.30 बजे
IN ENGLISH MED- 24 & 25 Aug. 2005, - 5.00 P.M. (Evening)

UNIYAL'S IAS 2703, Dr. Mukherjee Nagar, Bandh, Near Sarvodaya Bal Vidyalaya, Delhi-9 (M) : 9818906330

By : S.N.Uniyal **Personally contact : 9818906330**

YH/10/5/16

आउटसोर्सिंग - अवधारणा और आयाम

○ उमेश चंद्र अग्रवाल

वर्तमान में, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में, आउटसोर्सिंग ने एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्राप्त कर लिया है। विशेषकर विकसित देश, जहां मजदूरी की दरें तुलनात्मक रूप से अधिक हैं, विकासशील देशों से आईटी सॉफ्टवेयर तथा अन्य विविध सेवाएं आउटसोर्सिंग के जरिये प्राप्त करने लगे हैं जिससे उन्हें खासा आर्थिक लाभ होता है

आउटसोर्सिंग, जो आम बोलचाल की भाषा में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के लिए प्रयुक्त किया जाता है, का तात्पर्य किसी बाहरी स्रोत से ठेके पर वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करने की एक आधुनिक तकनीकी प्रणाली से है। वास्तविक अर्थों में किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सुनिश्चित मानदंडों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रियाओं का प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी कार्य ठेके पर बाहरी प्रदाताओं से कराना ही आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के विस्तार का एक आधुनिक रूप है। आउटसोर्सिंग में एक तरफ जहां कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में मामूली-सी कमी आती है, वहीं सेवाओं के परिचालन व्यय में अच्छी-खासी कमी आती है। इसी कारण वर्तमान समय में यह कार्य तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में, विशेष रूप से सूचना तकनीकी के मामले में, आउटसोर्सिंग ने एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्राप्त कर लिया है। विशेषकर विकसित देश, जहां मजदूरी की दरें तुलनात्मक रूप से अधिक हैं, विकासशील देशों से आई.टी. साफ्टवेयर तथा अन्य विविध सेवाएं आउटसोर्सिंग के जरिये प्राप्त करने लगे हैं जिससे उन्हें खासा आर्थिक लाभ होता है। इसी कारण वर्तमान में अमरीका की विभिन्न व्यावसायिक फर्में भारत, चीन, इंडोनेशिया जैसे अनेक विकासशील देशों से ये सेवाएं प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से काफी इच्छुक रही हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही अनेक अमरीकी और यूरोपीय संघ की फर्में नियमित रूप से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की फर्मों को ठेके देने में अग्रसर रही हैं।

आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया की कार्य प्रणाली बहुत सरल और स्पष्ट है। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी डाक्टर को अपने मरीज की जांच करने के बाद मरीज के रोगों के निदान और उपचार आदि से संबंधित पूरी रिपोर्ट बनवानी हो या फिर किसी कंपनी को अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञप्तियां अथवा कोई प्रचार सामग्री आदि बनवानी हों, तो वे इन कार्यों को कम समय में और कम खर्च पर किसी बाहरी स्रोत से करवाने के लिए आउटसोर्सिंग की सहायता लेते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन पूंजी प्रधान देशों को तो कम खर्चे में निर्धारित कार्य हो जाने के कारण लाभ होता ही है, साथ ही भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले गरीब और शिक्षित बेरोजगारी की अधिकता वाले देशों को भी रोजगार के समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। आउटसोर्सिंग संबंधी कार्यों में लगे हुए

नवयुवक और नवयुवतियों को वेतन भी अच्छा मिलता है। इसमें सेवा की निरंतरता सामान्यतया बनी ही रहती है। वर्तमान में बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत सभी कार्य हमारे देश के कुशल एवं योग्य प्रोफेशनल्स के द्वारा बड़े पैमाने पर कराए जा रहे हैं। ये सभी कार्य कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स एवं अन्य आधुनिक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से न्यूनतम समय और कम खर्च में हो जाते हैं। इससे आवागमन और परिवहन आदि में होने वाली समय की बर्बादी, प्रदूषण, प्रतीक्षा करने जैसी अन्य अनेकों परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है।

आउटसोर्सिंग की पृष्ठभूमि

आउटसोर्सिंग की पृष्ठभूमि पर गौर करने से पता चलता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में यह कार्यपद्धति काफी पुरानी है। हालांकि वर्तमान में इसके प्रयोग के तरीके में अभूतपूर्व परिवर्तन जरूर आया है। पहले के समय में जो आउटसोर्सिंग होता था, वह वस्तुपरक होता था जबकि अब यह सेवापरक होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अमरीका की एक प्रसिद्ध आटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटरर्स पहले भी अपनी कार के कुछ पुर्जे भारत में बनवा रही थी। इसी प्रकार कई विदेशी टेलीविजन कंपनियां पिक्चर ट्यूब के कुछ हिस्से भारत में बनवाती रही हैं और इस तरह के अनेकों कार्य काफी लंबे अरसे से विश्व के अनेक भागों में अनेकों कंपनियों द्वारा कराए जाते रहे हैं। यह एक प्रकार से वस्तुओं की आउटसोर्सिंग ही है जिसमें बाहरी स्रोतों या देशों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कराया जाता रहा है। लेकिन आजकल वस्तुओं के निर्माण के स्थान पर बड़े पैमाने पर सेवाओं की आउटसोर्सिंग होने लगी है। इन दोनों प्रकार की आउटसोर्सिंग में काफी बड़ा अंतर है। सेवाओं की आउटसोर्सिंग एक आधुनिक संकल्पना है जो अब से लगभग 5 वर्ष पूर्व से ही शुरू हुई है। यह शुरुआत पहले छोटे स्तर पर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के तौर पर प्रारंभ हुई। इसके सफल प्रयोग से उत्साहित होकर ही विकसित देशों ने इसे बड़े पैमाने पर दूसरे कई क्षेत्रों में शुरू करने का निर्णय लिया और आज यह बड़ी तेजी से विकसित और विकासशील देशों में अपने कदम बढ़ाती जा रही है। वस्तुत: माल बनाने, माल पैक करने व ट्रांसपोर्ट करने में जितना समय लगता है और जितना खर्च पड़ता है, उसकी तुलना में सेवाओं की आउटसोर्सिंग में समय और खर्च दोनों ही कम पड़ते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में इसके प्रयोग की प्रक्रिया को यदि देखें तो पता चलता है कि इसके अंतर्गत ई-मेल से मरीज तथा डाक्टर के बीच तत्काल बातचीत हो जाती है। मरीज अपनी समस्या अपने कंप्यूटर पर लिखता है, वह डाक्टर के कंप्यूटर पर तुरंत पहुंच जाती है। डाक्टर जो समाधान देता है वह मरीज के कंप्यूटर पर तुरंत उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार के विचार-विमर्श और सूचनाओं के आदान-प्रदान का खर्च बहुत मामूली-सा आता है। वर्ष के प्रत्येक दिन और चौबीस घंटे प्रतिदिन के ई-मेल का औसत खर्च प्रतिमाह मात्र 1,000 रुपये के करीब पड़ता है जो डाक्टर की कंसल्टेशन फीस की तुलना में बहुत कम है।

पिछले पचास सालों में अमरीका कम वेतन वाले साधारण ब्लू-कालर रोजगारों को अनेक विकासशील देशों को निर्यात करता आ रहा है। जैसे अमरीका द्वारा कपड़ों की उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से विकासशील देशों को हस्तांतरित कराया जा चुका है परंतु इसका विशेष दुष्प्रभाव वहां के रोजगार पर नहीं पड़ा है। चूंकि आजकल कंप्यूटर, बायोटेकनीक एवं इंटरनेट जैसे नये क्षेत्रों में उससे भी अच्छे रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। अत: अमरीकी जनता को अपने आप में यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि उसे ब्लू-कालर रोजगारों को बाहर जाने देना चाहिए और शिक्षा आदि में सुधार करके व्हाइट-कालर रोजगारों को पकड़ने में चुस्ती दिखानी चाहिए। पिछले तीस वर्षों में अमरीका की यह रणनीति लगभग सफल ही रही है परंतु अब यह कुछ-कुछ फेल हो रही है। चूंकि उच्च श्रेणी के व्हाइट-कालर रोजगार भी इस आउटसोर्सिंग के जरिये अनेक विकाशसील देशों को विशेष रूप से भारत को स्थानांतरित हो रहे हैं। इसी संदर्भ में 5 मार्च, 2004 को अमरीकी सीनेट ने अमरीकी नौकरियां बाहर स्थानांतरित करने पर रोक लगाने के लिए एक बिल भी पास किया है। इस बिल के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर अमरीकी ठेकेदार उन नौकरियों को बाहर स्थानांतरित नहीं कर सकेंगे जिन्हें पहले संघीय कर्मचारी किया करते थे और अब सरकार उनका निजीकरण कर रही है। इसके मुताबिक ठेकेदार उन नौकरियों को भी बाहर नहीं भेज पाएंगे जहां संघीय सरकार वस्तुओं और सेवाओं के लिए संविदा करती है अथवा जहां राज्य सरकारें सरकारी धन से किसी काम के लिए संविदा करती है। हालांकि इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि अमरीकी कंपनियां अपने कार्यों को संपादित करने के लिए आउटसोर्सिंग नहीं अपना सकेंगी तो उन कंपनियों के लिए बाजार में टिक पाना मुश्किल होगा। अत: आउटसोर्सिंग के लिए हो रहे विरोध के बावजूद अमरीकी व्यवसाय आउटसोर्सिंग के लिए मजबूर दिखाई देते हैं। भारत उनकी इस परिस्थिति का काफी सीमा तक लाभ उठा सकता है और वह ग्लोबलाइजेशन के इस खेल में विजयी भी हो सकता है। अत: हमें गंभीरतापूर्वक सोच-विचार कर इस दिशा में आगे की रणनीति तय करनी चाहिए।

आउटसोर्सिंग के भारतीय-अमरीकी संदर्भ

इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि भारत श्रमप्रधान देश है। यहां मजदूरों की पूर्ति मांग की तुलना में अधिक है। यहां जीवनयापन का खर्च भी कम है अत: सस्ते श्रम की उपलब्धता यहां की एक अहम विशेषता है। भारत में जिस साधारण तकनीकी योग्यता प्राप्त सामान्य श्रमिक को प्रतिदिन औसतन 200 रुपये का वेतन मिलता है, अमरीका में वह लगभग 3600 रुपये प्रतिदिन बैठता है जिसके कारण श्रमिकों के ऊंचे वेतन अमरीका के उत्पादों की कीमत बढ़ा देते हैं। इससे अमरीका में व्यावसायिक कंपनियों का मुनाफा घटता है। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्द्धा होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके बाजार से बाहर होने की संभावना

बनती है। दवा कंपनियों के व्यवसाय से संबंधित एक उदाहरण के जरिए इसे समझना चाहें तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे यदि रैनबैक्सी दवा कंपनी अपने एक श्रमिक को 200 रुपये प्रतिदिन वेतन देती है और ग्लैक्सो कंपनी अपने श्रमिक को यदि 3600 रुपये प्रतिदिन वेतन देती है तो निश्चित ही ग्लैक्सो कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाला माल महंगा पड़ेगा और एक न एक दिन उसे बाजार में हार माननी ही पड़ेगी। इस परिस्थिति से मुकाबला करने का ग्लैक्सो के पास एक ही उपाय है कि वह ग्लैक्सो में कार्यरत अपने अमरीकी श्रमिकों के वेतन घटाए। चूंकि अमरीका में श्रमिकों के पारिश्रमिक सरकार द्वारा निर्धारित हैं अत: ग्लैक्सो कंपनी के लिए उन्हें कम करना नामुमकीन है। अत: दूसरे तरीके के रूप में ग्लैक्सो कंपनी का उन देशों की ओर अग्रसर होना ही एक मात्र विकल्प होगा जहां श्रमिकों के वेतन कम हैं। इसलिए ही तमाम अमरीकी कंपनियां अपने द्वारा संपादित किए जाने वाले कुछ कार्यों को भारत जैसे श्रम प्रधान देशों के पढ़े-लिखे नौजवानों को आउटसोर्सिंग के जरिए हस्तांरित कर रही है। इसके लिए इन विकासशील देशों में अमरीकी तथा कई यूरोपीय कंपनियों के काल सेंटरों को स्थापित किया जा रहा है।

इस प्रकार आउटसोर्सिंग की नई पद्धति के जरिए आजकल अमरीका में अपने ग्राहकों के सवाल के उत्तर देने के लिए विभिन्न कंपनियों के द्वारा गुड़गांव एवं बंगलौर के काल सेंटरों में अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले नवयुवकों और नवयुतियों को बड़े पैमाने पर काम पर लगाया जा रहा है। सेटेलाइट तकनीक के विकास से अमरीका से बंगलौर के फोन पर खर्च कम पड़ता है और भारत में सस्ते श्रमिकों के उपयोग से अमेरीकी कंपनियों को अधिक बचत होती है। आधुनिक तकनीकी विकास के इस युग में आज लगभग सभी देशों में और सभी शहरों में इंटरनेट जैसी संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यातायात के साधन भी तुलनात्मक रूप से तीव्रतर, सर्वसुलभ और सस्ते हुए हैं। कंप्यूटर शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देकर इन अवसरों का लाभ उठाना आज संभव हो गया है। अपने देश के विशेष संदर्भ में यदि देखा जाए तो इसके दो विशेष लाभ हैं, एक तो इससे हमारे यहां बेरोजगारी घटेगी, और दूसरे यहां नई तकनीक विकसित होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। अब तो इन नई तकनीकों को बनाने के कार्य की भी आउटसोर्सिंग होने लगी है। जैसे-कपास की नई प्रजातियों को विकसित करने में लगी एक मशहूर अमरीकी कंपनी 'मानसैटो' के लिए कपास की नई प्रजातियों को भारत में बनाना सस्ता पड़ रहा है। इस कार्य को अमरीकी कंपनी द्वारा भारत में कराने पर भारत के वैज्ञानिकों को नई प्रजातियां बनाने की तकनीक का ज्ञान भी उपलब्ध हो रहा है। अगले चक्र में वे इस कार्य को स्वयं भी कर सकते हैं। हमें ऐसे अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इनका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आज अनेक क्षेत्रों में नयी संभावनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिनका आउटसोर्सिंग सेवाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। जैसे - अमरीकी मरीज ई-मेल के माध्यम से भारतीय डाक्टरों से सलाह ले सकते हैं। अमरीकी मनोरोगी आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारत के मनोचिकित्सक से अपना उपचार करा सकते हैं। इसी प्रकार अमरीका की बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के दावों के निबटारे के कार्य को भारतीय अधिकारियों द्वारा करा सकते हैं। अमरीकी डाक्टर अपने मरीजों की बीमारियों का निदान तथा उपचार के लिए उन्हें दी गई दवाओं आदि का रिकार्ड भारतीय लोगों से लिखा सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय क्लर्कों से कंपनी के एकाउंट लिखवाने का काम, पुस्तकों के अनुवाद, संपादन एवं पुनर्लेखन का कार्य भी करवाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य पहले से ही भारत में बड़े पैमाने पर संपादित किया जा रहा है।

आउटसोर्सिंग पर वर्तमान विवाद

वर्तमान वैश्वीकरण की होड़ में प्रत्येक देश एवं प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान आगे निकलना चाहता है। उनके लिए आउटसोर्सिंग एक ऐसा हथियार है, जिसकी सहायता से आधुनिक तकनीक एवं प्रबंधन के जरिए उनके द्वारा प्रतिस्पर्धा कायम की जा सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब कंपनी के खर्चों में कटौती हो और यह सब हो सकता है कर्मचारियों की छंटनी की कीमत पर। पश्चिमी देशों में श्रम महंगा होने के कारण वहां से लाखों रोजगार भारत जैसे जनसंख्या बहुलता वाले एशियाई देशों में स्थानांतरित हो रहे हैं क्योंकि यहां श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है। पिछले दिनों अमरीका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने अपने काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे यहां से करवाने का निर्णय लिया था और इस निर्णय का कार्यान्वयन भी बड़े स्तर पर किया जाने लगा। इसके चलते उन देशों को कुशल श्रमिकों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इस संबंध में अमरीका में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अगले 6-7 वर्षों में वर्तमान परिस्थितियों के चलते अमरीका को 2 ट्रिलियन डालर का नुकसान तथा 56 लाख कर्मचारियों का अभाव होगा। इस अभाव की पूर्ति 32 लाख कर्मचारियों के आयात, 11 लाख कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति तथा 13 लाख कर्मचारियों का कार्य आउटसोर्सिंग द्वारा करवाकर की जाएगी। भारत इस क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत अभाव की पूर्ति करेगा। यही कारण है कि अमरीका में कुछ लोग आउटसोर्सिंग का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इस माध्यम से की गई बचत द्वारा नयी-नयी परियोजनाएं शुरू होंगी तथा अन्य नयी-नयी नौकरियों की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ यह भी एक सचाई है कि अमरीका की 15 प्रतिशत नौकरियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के देशों में जा रही हैं। इससे जुड़े आर्थिक पहलू का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि अमरीका में पूर्णकालिक रोजगार पर औसत लागत 42,927 डालर तथा भारत में यह लागत मात्र 6,129 डालर ही आती है। बाहर अपनी शाखा स्थापित करने पर अमरीकी कंपनी का यह

औसत खर्च कुल 58,598 डालर तथा भारतीय कंपनी को आउटसोर्सिंग का ठेका देने का यह औसत खर्च मात्र 11,854 डालर आता है। अपने खर्च को घटाने के लिए अमरीकी कंपनियां आउटसोर्सिंग को तेजी से अपना रही हैं ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्द्धी भी बनी रहें।

उल्लेखनीय है कि हमारे यहां वर्तमान में रोजगार के भीषण संकट से गुजर रहे बेरोजगारों के लिए आशा की एक किरण के रूप में यह व्यवसाय उभरकर सामने आया है लेकिन अमरीका जैसे विकसित देशों में स्थानीय स्तर पर विवाद का मुद्दा बन गया है क्योंकि इसके माध्यम से वहां की नौकरियां भारत और चीन जैसे विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। आउटसोर्सिंग पर अमरीका के फ्लोरिडा शहर में 23 से 25 जनवरी, 2004 के बीच विश्व सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें आउटसोर्सिंग के संबंध में गहनता से विचार-विमर्श किया गया। एक अनुमान के अनुसार अमरीका से प्रतिवर्ष दो लाख नौकरियां भारत तथा चीन जैसे एशियाई देशों में आ रही हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के मामले में भारत रूस तथा चीन से आगे है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में प्रतिवर्ष 75 हजार आईटी स्नातक तैयार होते हैं। इस प्रकार भारत दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी मानव संसाधन से युक्त देश है। आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने में चीन और जापान के सामने अंग्रेजी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है जो हमारे लिए नहीं है। यह हमारे लिए एक और सकारात्मक पहलू है।

इस संबंध में मूल प्रश्न जो भारत और अन्य विकसित देशों में उठाया गया है वह यह कि वहां वैश्वीकरण के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की गतिविधि पर लगाए गए सभी अवरोधक हटा दिए जाने चाहिए। वहां जब कभी भी वैश्विक प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप उनके हित प्रभावित होते हैं, वे अपने हितों की रक्षा के लिए या तो भारी मात्रा में सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं या वे अन्य प्रकार के अवरोधक जैसे श्रम-मानकों, पेटेंट-अधिकार आदि को खड़ा कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्ववाद का स्थान राष्ट्रवाद ले लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना सही होगा कि अमरीका की सीनेट द्वारा पास किए जाने वाला आउटसोर्सिंग कंपनी बिल विश्व व्यापार संगठन की भावना और वैश्वीकरण के लक्ष्यों के विरुद्ध है। इस प्रकार के विधेयकों के पारित होने से भारतीय कंपनियों को अमरीका की सरकार से विभिन्न परियोजनाओं तथा अनेक कार्यों को प्राप्त करने का एक बड़ा भारी अवसर बंद हो जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष प्रौद्योगिकी पर करोड़ों डालर खर्च करता है। अत: भारत जैसे विकासशील देशों को इसका कड़ा विरोध करना ही चाहिए।

आउटसोर्सिंग से भारत में संभावनाएं

भारत में आउटसोर्सिंग के कारण काल सेंटरों की वृद्धि से आम शिक्षित-प्रशिक्षित भारतीयों को निकट भविष्य में नौकरियों की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। आज विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ-साथ आईटी के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारतीयों की छवि कुशल पेशेवर की बन रही है। इस क्षेत्र में भारत की बढ़त के जो कारण गिनाए जा रहे हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण भारत सरकार की इस दिशा में अनुकूल नीतियां

IAS (वैकल्पिक विषय एवं सामान्य अध्ययन) PCS
J अर्थशास्त्र N
R द्वारा E
F आनन्द शुक्ला T
★ JRF/NETका अलग बैच
★ सम्पूर्ण नोट्स
★ मॉडल पेपर द्वारा अभ्यास
★ छात्रावास सुविधा उपलब्ध
★ पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध
बैच प्रारम्भ नामांकन जारी
आनन्द एकेडमी
13/3, बन्द रोड, इलाहाबाद । फोन : 0532-2465265, 9415254465
YH/10/5/10

अनेकों कारणों में से एक है। भारत सरकार और उसकी आईटी समर्पित नीतियां तथा नास्काम, सरकार और कंपनियों के बीच अच्छा तालमेल अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। देश में आईटी के क्षेत्र में शोध और विकास के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना अब और भी अधिक आवश्यक हो गया है क्योंकि आज जहां विकसित देश अपने यहां कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं वहीं भारत की आईटी कंपनियां अभी तक का अपना सबसे बड़ा भर्ती अभियान चलाए हुए हैं। इस समय भारत को आउटसोर्सिंग का केंद्र बिंदु बनाने का अभियान अपने चरमोत्कर्ष की ओर है। भारत की अनेक आईटी कंपनियां आज अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में बेहतर कार्य और प्रतिफल देने के कारण प्रसिद्ध हो रही हैं। वे वहां बड़े पैमाने पर ठेके पर काम लेकर उसे भारत स्थित अपनी शाखाओं या अन्य कंपनियों से पुन: ठेके पर करवाती हैं और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं। आज की स्थिति यह है कि न केवल सेवाओं की दृष्टि से, बल्कि उत्पादन की भी दृष्टि से आउटसोर्सिंग के लिए देश में उपयुक्त वातावरण बनता जा रहा है। सेवाओं की आउटसोर्सिंग में विकसित तथा संपन्न देश हमारे यहां अपना काम कम कीमत पर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से करवाते हैं। इस प्रक्रिया में विकसित देशों की तुलना में आउटसोर्सिंग करने वाले देशों द्वारा काम लगभग 1/6 लागत पर और जल्दी भी हो जाता है। इस कारण विकसित देशों में नौकरियों में कटौती तथा जिन देशों द्वारा यह कार्य किया जाता है, वहां नौकरियों की उपलब्धता में स्वाभाविक वृद्धि हो जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है उसका लाभ हमें मिलना शुरू हो गया है। हमारे यहां न केवल विकसित देशों की कंपनियां वरन भारतीय आईटी क्षेत्र की कंपनियां भी देश में नौकरियों की वृद्धि की व्यापक घोषणाएं कर रही हैं। इसी कारण से काल सेंटरों का धंधा आज देश के प्रमुख महानगरों में भलीभांति फल-फूल रहा है और आगे इसमें अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन के क्षेत्र में हमारे यहां दिनोंदिन हो रही प्रगति के कारण भी आज आउटसोर्सिंग के लिए भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में इस मुद्दे पर मुख्य मुकाबला भारत और चीन के मध्य नजर आ रहा है लेकिन इस क्षेत्र में हम चीन को पछाड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। भारत की इस क्षेत्र में बढ़त का प्रमुख कारण यहां अंग्रेजी जानने-समझने और बोलने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या है। इसी कारण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं एवं सेवाओं के बाजार का अनुमान सन् 2009 तक 142 अरब डालर तक व्यक्त किया जा रहा है। आज फार्चून 500 कंपनियां भारतीय आईटी कंपनियों के साथ काम कर रही हैं। सन् 02004-05 तक लगभग 80 प्रतिशत अमेरीकी कंपनियां आउटसोर्सिंग का कार्य विदेशी कंपनियां से ही कराएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन तथा अमरीका की बड़ी-बड़ी कंपनियां या तो भारतीय कंपनियों से आउटसोर्सिंग के लिए अनुबंध कर चुकी हैं या करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। ऐसी स्थितियों में यदि अमरीका जैसे विकसित देश अपने यहां आउटसोर्सिंग रोकने के लिए कानून को बनाकर सख्ती से इस्तेमाल करेंगे तो यह भारत जैसे विकासशील देशों के साथ तो नाइंसाफी होगी ही, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके अनेकों दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इस तथ्य को इस प्रकार देखा जाना चाहिए कि आज अगर अमरीका सरकारी कामों की आउटसोर्सिंग के बारे में ऐतराज करता है तो कल वह ऐसा अपने पूरे व्यापार के बारे में कर सकता है और ऐसा ही ब्रिटेन तथा अन्य देश भी करेंगे ही, जो मुक्त व्यापार के वर्तमान दर्शन के बिल्कुल विपरीत होगा। इसलिए आज इसे हर कीमत पर रोकने की जरूरत है।

वास्तविकता यह है कि अमरीका ग्लोबलाइजेशन या मुक्त व्यापार के नाम पर सिर्फ अपना फायदा चाहता है जिसे किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह की आर्थिक नीतियां अभी दुनिया में चल रही हैं उसमें किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं रह गया है कि वह बाहरी महारत या कौशल अथवा पूंजी के लिए अपने दरवाजे बंद कर ले लेकिन इसी के बीच सभी देश एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस कार्य में अमरीका भी अपनी तरह से लगा हुआ है और भारत भी। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े-लिखे तथा अच्छी अंग्रेजी बोलने और लिखने वाले लोगों की भारत में अच्छी-खासी संख्या होने तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उनकी कुशलता होने के कारण स्वाभाविक है कि भारत के एक छोटे वर्ग को ही सही, कुछ लाभ अवश्य हो रहा है। ऐसा ही लाभ अमरीका के उन व्यावसायिक घरानों को भी हो रहा है जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें भारत में अमरीका की तुलना में कम वेतन पर कुशल और स्तरीय कर्मचारी मिल रहे हैं जिससे अमेरीकी कंपनियों की आमदनी भी बढ़ रही है और अपने उत्पादों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धी बनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यथार्थ यह है कि आउटसोर्सिंग एक सच्चाई है, कई पक्षों के लिए लाभकारी है और व्यावहारिक है अत: इसे रोका नहीं जा सकता। इस संबंध में अमरीका का यह सोचना कि अमरीका से भारत में आउटसोर्सिंग होगी तो अमरीका में कुछ बेरोजगारी बढ़ेगी, कुछ सीमा तक सही है, लेकिन यथार्थ यह भी है कि इससे अमेरीकी कंपनियों की आमदनी भी तो बढ़ेगी। इस बढ़ी हुई आमदनी से वे लोग वहां नई कंपनियों अथवा नए उपक्रमों को स्थापित कर सकते हैं जिनमें काफी बेरोजगारों को समाहित किया जा सकता है। अमरीका की आउटसोर्सिंग विरोधी मुहिम के खिलाफ भारत को एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समीकरण बनाना जरूरी हो गया है जिससे गरीब देश विरोधी अपनी चाल में अमरीका सफल न हो सके। इस दिशा में अमरीका पर समुचित दबाव बनाने के लिए भारत सरकार, यहां के प्रमुख राजनीतिक दलों और मीडिया को भी अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ❑

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश में संयुक्त निदेशक हैं)

राहुल रंजन महिवाल 49 वां
IAS

कृष्ण कु. निराला 110 वां
IAS

सा.अ. में कुल प्राप्तांक-360
प्रथम पत्र-174, द्वितीय पत्र 186

संतोष करनानी 171 वां

Certainly General Studies has contributed to a greater extent to my success. Because of the proper guidance by Srivastava Sir particularly in developing writing skills, I have secured **358** marks in G.S. This includes **148** in Paper I and **210** in Paper 2

पूनम 95 वां | मनोज कु. शर्मा 121 वां | आनन्द कुमार 237 वां

तृप्ति गुप्ता 254 वां | परमादित्य 255 वां | यामिनी 296 वां

अजय कु. केशरी 297 वां | सचिन बादशाह 300 वां | विजय कुमार 303 वां

राम बाबू 304 वां | मजहर अकरम 309 वां | लव कुमार 311 वां

यशवन्त कुमार 356 वां | सीता राम मीणा 398 वां | संजीव कु. बेसरा 416 वां

DISCOVERY IAS/PCS

का नया कीर्तिमान 19 सफलताओं के साथ, जिसमें राहुल रंजन महिवाल और सामान्य अध्ययन में कुल 360 अंक प्राप्त करने वाले कृष्ण कुमार निराला, 358 अंक प्राप्त करने वाले सन्तोष कु. करनानी शामिल हैं। साथ ही C.S.E. 2004 में शामिल हमारे संस्थान के अभ्यर्थियों का सा० अध्ययन में प्राप्तांक 282, 297, 310, 322, 331, 336, 336, 348, 353, 358, 360 रहा है। जो 'हमारी सुधार आधारित विकास कार्यक्रम' (R.B.D.P.) की लक्षित एवं तार्किक रणनीति की सफलता को प्रमाणित करता है।

P.T./P.T.-cum-MAINS-2006

सामान्य अध्ययन

-सी.बी.पी. श्रीवास्तव, अनिल केशरी एवं अन्य

नये सत्र का कार्यक्रम

प्रारंभिक/प्रा.+मुख्य परीक्षा की कक्षा प्रारंभ - अक्टूबर प्रथम सप्ताह
प्रारंभिक/प्रा.+मुख्य परीक्षा की कक्षा प्रारंभ - नवम्बर द्वितीय सप्ताह

''सुधार आधारित विकास कार्यक्रम'' द्वारा संचालित कक्षा की रूपरेखा-

प्रारंभिक परीक्षा

- पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों की आधारिक जानकारी तथा तथ्यों के साथ अवधारणाओं के विकास के लिए कक्षा का संचालन जिससे कथन-कारण और व्यवहारिक प्रश्नों का हल संभव।
- प्रतिदिन विगत वर्षों में पूछे गये प्रश्नों के आधार पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा एवं उनका संकलन।
- प्रति सप्ताहांत खंड विशिष्ट जांच परीक्षा जो विषय के व्यवहारिक, अवधारणात्मक तथा सूक्ष्म तथ्यों वाले प्रश्न पर आधारित।
- समसामयिक प्रश्नों के हल के लिए प्रतिदिन समचार पत्रों में प्रकाशित घटनाक्रमों पर चर्चा एवं उनका संकलन। अवधारणा के साथ तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री। साथ ही भारत संदर्भ ग्रंथ, आर्थिक समीक्षा, विभिन्न सरकारी रिपोर्टों का संक्षिप्त प्रतिरूप तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित विशिष्ट अध्ययन सामग्री।

मुख्य परीक्षा

- कक्षा क्रमशः तथ्यात्मक-विश्लेषण एवं पूर्णतः विश्लेषणात्मक ताकि प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप उत्तर लेखन संभव हो सके।
- ''फाइल मेन्टिनेन्स सिस्टम'' द्वारा लेखन शैली का चरणबद्ध विकास-
  - प्रत्येक अध्याय की संकल्पना का विकास।
  - विगत वर्षों में पूछे गए तथा संभावित प्रश्नों का उत्तर प्रारूप।
  - प्रतिदिन प्रश्नोत्तर लेखन (20 शब्द, 125/150 तथा 250 शब्द)।
  - मूल्यांकन एवं सुधारात्मक सुझाव।
  - पूर्णतः संशोधित एवं परिमार्जित अध्ययन सामग्री।

नामांकन प्रारंभ

इतिहास	→ डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा → डॉ. लाल बहादुर वर्मा एवं प्राचीन भारत के विशेषज्ञ
लोक प्रशासन	→ दिवाकर गुप्ता
भूगोल	→ अनिल केशरी
हिन्दी साहित्य	→ अजय अनुराग
ENGLISH Comp.	→ ALOK KUMAR

DISCOVERY

...Discover your mettle

Contact us at: 30906050, 9313058532

B-14 (Basement), Comm. Cop. Mukherjee Nagar, Delhi-9

YH/10/5/17

संख्या शक्ति है हमारी

○ हरीश बिजूर

बीपीओ एक कम कीमत वाले विशेषज्ञ कौशल का उपक्रम है। भारत अपर्याप्त रूप से शिक्षित टेलीफोन आपरेटरों की एक फौज खड़ी कर रहा है। जब तक काम मिल रहा है, तब तक अच्छा है, आगे ईश्वर बचाए

सदियों से भारत बल और बुद्धि का निर्यात करता रहा है। हमारी संख्या अनेक अर्थों में हमारी सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध होती रही है। हालांकि इसका महत्व हम अनेक वर्षों तक समझ पाने में नाकाम रहे। हम अपने ही बनाए प्रतिमानों में जीते रहे। एक ऐसा प्रतिमान, जो आजादी के प्रारंभिक दशकों में हमारे राष्ट्र को परेशान करने वाले छोटे-छोटे मुद्दों में ही मस्त रहा।

यह प्रतिमान सरल और सीधा-सादा था। यह तात्कालिक आवश्यकताओं से निर्देशित और निर्मित प्रतिमान था। शुरू से हमारी जनसंख्या काफी अधिक थी। इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे संसाधन अपर्याप्त थे। उस पर तर्क यह कि साल दर साल बढ़ने वाली हमारी जनसंख्या हमें और भी चिंता में डाल रही थी। पानी को छोड़कर हमारे पास हर चीज का अभाव था। खाने की कमी थी, दवाओं और बढ़ती आबादी की जरूरत की सभी चीजों का अभाव था।

परंतु अब समय बदल गया है। यह समय है फिर से रेखा खींचने का और उस प्रतिमान को वहां तक ले जाने का, जिनमें हम काम करते हैं। यह समय हमारी बढ़ती जनसंख्या पर खुशी मनाने और उसकी मंगल कामना का है। समय है, हमारी बढ़ती आबादी की संपदा की क्षमताओं का पता लगाने के लिए निर्णायक क्षणों का।

यह समय विश्व की जनसंख्या के लिए भी निर्णायक क्षणों का है। यह समय भविष्य की ओर देखने तथा आने वाले वर्षों और दशकों में प्रभाव जमाने वाले देशों के जन-धन पर भी नजर डालने का है। आइए, सबसे पहले देखें कि जाने-माने जनसांख्यिकीविद ए.आर. नंदा इस बारे में क्या कहते हैं।

श्री नंदा के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत पूरे संसार में सबसे अधिक कामगारों का सबसे अधिक युवा राष्ट्र बन जाएगा। वर्ष 2020 तक 15 से 59 वर्ष तक की आयु के कामकाजी लोगों की संख्या बढ़कर 82 करोड़ हो जाएगी। अभी यह संख्या 40 करोड़ 20 लाख है।

शुरुआत में इसी संख्या को लेते हैं। इसका सरल-सा अर्थ है कि 2020 तक भारत की कामकाजी जनशक्ति में अतिरेक हो जाएगा। भारत के संदर्भ में इस समय जिन योजनाओं पर काम चल रहा है, उनको देखते हुए लगता नहीं कि देश में इन सब लोगों के लिए काम उपलब्ध होगा। चिंता का विषय है न?

परंतु हकीकत में नहीं। हमें आकर्षित करने वाले वाणिज्यिक विश्व की जन-धन की पूर्व सूचना पर हम नजर डालें तो पता चलेगा कि इस मामले में अमरीका में सबसे ज्यादा कमी रहेगी। वहां करीब 1 करोड़ 70 लाख काम करने योग्य लोगों की कमी रहने की आशा है। चीन में 1 करोड़ और जापान में 90 लाख लोगों की मांग होगी। यहां तक कि रूस में भी देश के वाणिज्य को चलाने के लिए आवश्यक 60 लाख लोगों की कमी रहेगी।

विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति पर आधारित इस पूर्व सूचना के अनुसार केवल भारत ही ऐसा देश है जहां अतिरिक्त लोग उपलब्ध रहेंगे। अतः यह स्वाभाविक ही है कि यह अतिरिक्त जनशक्ति इन जनाभाव वाले देशों की ओर खिंचती जाएगी और सभी जगह व्यापार और वाणिज्य के उपक्रम चलाएगी। उदाहरण के तौर पर ऊपर वर्णित इन चार देशों में ही कामकाजी आयुवर्ग के 4 करोड़ 20 लाख लोगों को तैयार बाजार मिलेगा।

जन निर्यात का इतिहास

जन निर्यात के बारे में भारत का एक इतिहास रहा है। हमने बाल (श्रम) से शुरू किया था, और अब बुद्धि पर आ गए हैं। जन निर्यात के हमारे पहले के वर्षों पर जरा गौर से नजर डालिए। सौभाग्य से हमेशा से हमारे यहां लोगों की कमी नहीं रही। इतने लोग कि हर एक को देने के लिए पर्याप्त काम नहीं होता। सबसे पहले हमारा जन निर्यात का सिलसिला तब शुरू हुआ जब पूर्व और पश्चिम के देशों में खेती के लिए भेजे जाने वाले श्रमिकों का क्रम समाप्त होने को था। जरा उन आबादियों पर नजर डालिए जिन्होंने श्रीलंका को अपना आधार बनाया। वे अफ्रीका के दुर्गम क्षेत्रों के अलावा सिंगापुर और मलेशिया के बागानों में भी रम गए।

अतिरिक्त श्रमिकों वाले देश से श्रमिकों के अभाव वाले देश में लोगों के निर्यात का

यह प्रारंभिक उदाहरण था। ये वे देश थे जहां रबड़, इमारती लकड़ी और कॉफी आदि के बागानों का प्रतिकूल वातावरण लोगों को हतोत्साहित करता था।

समय बदल गया है। हमारे पास निर्यात के लिए अभी भी काफी लोग हैं। मध्य-पूर्व जैसे नवधनाढ्य देशों और तेजी से बढ़ रही हांगकांग और सिंगापुर की अर्थव्यवस्थाओं से सस्ते श्रम की बढ़ती मांग इसी समय आई। अब हमने कुशल श्रमिकों का निर्यात किया। हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े थे। जिन कारीगरों का हमने निर्यात किया, वे थे राजमिस्त्री, बढ़ई और कसाई जैसे लोग।

समय बदलता रहा। चारों तरफ लोगों की मांग के अनुरूप हम अपने को तैयार करते रहे। अब उच्चतर कौशल की मांग थी। हम (जन) शक्ति से बुद्धि (ज्ञान) शक्ति की ओर बढ़ रहे थे। डाक्टरों की मांग थी। हमने यहां उनको पढ़ा-लिखा कर निर्यात कर दिया। यह सरकार के इच्छा या कहने से नहीं किया गया। यह उन लोगों की निजी इच्छा की बदौलत हुआ जिन्हें आर्थिक रूप से आकर्षक संभावनाओं की तलाश थी। हमने जिस प्रकार अमरीका में अपने इंजीनियर भेजे, उसी तरह इंग्लैंड में अपने डाक्टर भेजे। भारत से वास्तुकार और अनेक विद्याओं के वैज्ञानिक गए और अनेक देशों में वाणिज्यिक उपक्रमों में अपने काम से छा गए।

हम आगे बढ़ते रहे। हम तब तक सीढ़ियां चढ़ते रहे जब तक कि सबसे ऊपर नहीं पहुंच गए। यहां से डाक्टर, इंजीनियर और शिक्षक (सभी प्रकार की शिक्षा गुरु) जहां-जहां गए, सभी जगह उन्होंने ऊंचा स्थान प्राप्त किया।

आज हम पूरा चक्र काट चुके हैं। हम अब भी लोगों का निर्यात करते हैं परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रवृत्ति थोड़ी पीछे की ओर खिसकी है। आज हम जो निर्यात कर रहे हैं संभवत: वह ऊपर से नीचे आ रहा है। कई मायनों में तो सीढ़ी उलट गई लगती है। वे लोग, जिन्हें हम निर्यात करते हैं, वास्तव में इसी देश में रहते हैं, परंतु काम वे भारत की सीमा से परे अन्य देश के उपक्रम के लिए करते हैं। जिसे आज हम बीपीओ क्रांति कहते हैं, वह विस्तृत रूप में इसी प्रवृत्ति को कहते हैं। इसी में आज हम जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।

वर्ष 2005 बीपीओ की खुली चुनौती का वर्ष है। इस आलेख में मैं सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश करते हुए अपने देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों और मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। यह ऐसा युग है, जिसमें भारत अपने अतिरिक्त जन संसाधन के बलबूते समाधान की प्रभावी भूमिका में है। बीपीओ इसी तरह का क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जिसमें उत्तरोत्तर भारतीय अपनी संख्या बल और शिक्षा के स्तर के सहारे छाते जा रहे हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा यह संचित बल इतना आकर्षक भी हो सकता है।

बीपीओ क्रांति

बीपीओ क्रांति के भारत में आने से अंदरूनी और बाहरी, दोनों ही तरह की नयी चुनौतियां सामने आ रही हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव (क्या इन तीनों को मिलाकर नहीं देखना चाहिए?) बंगलौर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और कोलकाता जैसे महानगरों में चल रही गतिविधियां अब साफ-साफ दिखाई दे रही हैं। यह बहुत स्पष्ट है। बीपीओ को शुरुआती दौर में अपनाने वाले ये नगर, समृद्धि के वे टापू हैं, जो भारतीय परिदृश्य में सजे हुए अंगूठे की तरह अलग से ही दिखाई देते हैं।

एक ऐसी अर्थव्यवस्था में, जिसने हाल के समय में सेवा क्षेत्र को सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देखा है, आईटी जनित सेवा क्षेत्र का योगदान काफी तेज है। हर समय सृजित होने वाले नये-नये कार्यों की दिलचस्प संख्या और हमारी ओर निहारते दिलचस्प मुद्दों के साथ यह उपलब्धि और भी रोचक बन जाती है।

और जब अमरीका और इंग्लैंड में आउटसोर्सिंग के बारे में शोरगुल कुछ थम-सा गया है, इस उद्योग और इसमें काम कर रहे लोगों के लिए कई चुनौतियां सामने आई हैं। इनमें से कुछ चुनौतियों पर नजर डालते हैं।

बीपीओ का पूर्णतया विदेशी और अलग व्यापार

बीपीओ उद्योग अपने क्रिया-कलाप के कारण इस देश के लिए पूर्णतया बहिर्मुखी है। शब्दश: वह सब कार्य व्यापार जो डोमलर या गुड़गांव के केंद्र से, या और कहीं से किया जाता है, एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें विदेशी उच्चारण शैली की प्रमुख भूमिका होती है। भारत बिल्कुल भी केंद्र में नहीं आता। आईटी जनित सेवा और कुछ नहीं केवल एक सस्ते श्रम वाले स्थान से बाहरी लोगों की सेवा करना मात्र है। किसी भी बीपीओ केंद्र में जाइए, अंग्रेजी का उच्चारण कुछ विदेशी-सा लगेगा। पोशाक भी विदेशी प्रभाव से मुक्त नहीं है। देश के बीपीओ कार्यालयों को एक प्रकार से सेवा प्राप्त करने वाले विदेशी भूमि की क्षेत्रीय चौकियां भी कहा जा सकता है। बीपीओ कारोबार कठिन हो गया है। वह कारोबार जो पूर्णरूप से निर्यात बाजार पर केंद्रित है, एक ऐसा कारोबार है जो निम्न तकनीक के बीपीओ जैसे 'जिंस' के क्षेत्र में घटते-बढ़ते अंतरराष्ट्रीय वातावरण की दवा पर निर्भर है। इस क्षेत्र में पहले आने वालों की सफलता से लोगों के मुंह में पानी आ गया है, और वे भी वही करना चाहते है। सच में बीपीओ एक 'जिंस' बन चुका है।

दाम कम लागत ज्यादा हो रही है

इस क्षेत्र में कारोबार का पहला संकेत मिलते ही बीपीओ के क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले उद्यमियों ने बड़े आकर्षक कीमतों पर व्यवसाय हासिल किया। जैसे-जैसे दिन गुजरते गए और जैसे भारत में ही स्पर्धा बढ़ी, कीमतों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया।

यदि इसमें वियतनाम, चीन, मारिशस, श्रीलंका और नामीबिया जैसे देशों को जोड़ दिया जाए, जहां से स्पर्धा के स्वर उभर कर सामने आ रहे हैं तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। वियतनाम तो पूरी तरह से भारतीय बीपीओ अनुभव की नकल करने में लगा है। व्यापार तो आ रहा है पर कम कीमत पर। जो पहले मिला करता था, उससे काफी कम।

दूसरी ओर, प्राप्त व्यापार की सर्विसिंग पर

भी कीमतों का दबाव अपना प्रभाव दिखा रहा है। शुरुआती दिनों में हेडसेट पहनकर मॉनीटर के सामने बैठने वाले लोगों को चार हजार रुपये तक ही मिलते थे। आज, उसी काम के लिए 12 हजार रुपये मिलते हैं। इस क्षेत्र में वेतन में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है।

निश्चित ही लाभ का दबाव अपना खेल दिखा रहा है। इस खेल में लगे उपक्रमों की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल व्यापार की संख्या (मात्रा) प्राप्त करने पर ध्यान दे रहे हैं और लाभ-प्रवृत्ति को नजर अंदाज कर रहे हैं। कई खिलाड़ी तो लगता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चुने जाने की लालसा में आसपास खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मूल्यांकन ऊंचा होता जाता है और कॉल सेंटरों में थके हुए कर्मचारियों को रोककर रखने की समस्या बनी रहती है।

क्या आगे मंदी के आसार हैं?

साइक्स ने नौकरियों में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी है। क्या यह शुरुआत है? क्या यह एक बुलबुला है?

सामाजिक कोलाहल

यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बीपीओ व्यापार शायद ही कोई परवाह करता हो। भारत में तो निश्चित ही नहीं करता।

संपत्ति सृजन होना चाहिए। पैसा बनाया जाना चाहिए। लक्ष्य आर्थिक समृद्धि का ही होना चाहिए। और यह सब मध्यमकालीन और दीर्घकालीन सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किए जाने की जरूरत है। बीपीओ क्षेत्र को ध्यान से देखिए इस मामले में यह निश्चित ही एक कोलाहल भरा क्षेत्र है।

बीपीओ का क्षेत्र पूरी तरह से पाश्चात्य है। पुराने भारत में, एक शिक्षित व्यक्ति का पुत्र और पुत्री पढ़ने की आकांक्षा करते थे। भारत के शहरी क्षेत्र के घरों में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा का स्थान सबसे ऊंचा रहा है। अर्द्धशहरी क्षेत्रों और कस्बों में तो लड़कों के लिए तो निश्चित ही इसकी महत्ता अत्यधिक रही है। शिक्षा (विद्या) की देवी सरस्वती की इस देश में उपासना की जाती है। आज स्थिति कुछ भिन्न है। 18-19 साल के सभी युवा बीपीओ में काम चाहते हैं। हारमोनों के दबाव के कारण युवाओं पर अपने पैसे स्वयं कमाने की धुन रहती है। आजकल विश्वविद्यालय जाने के पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देना एक विकल्प के रूप में मौजूद है। बीपीओ कम उम्र में अच्छे पैसे कमाने का अवसर देता है। वह भी बिना किसी डिग्री के।

मेरा यकीन है कि भारत की युवा पीढ़ी अब कम शिक्षित होती जाएगी। हम यहां अमरीकी नमूने की नकल करने जा रहे है। शहरों के युवा लोगों में शिक्षा की इच्छा कम होती जा रही है। जब आवश्यक डिग्रियों के बिना कमाई के अवसर नहीं थे, उस समय शायद गलती से शिक्षा की जरूरत थी और लोग पढ़े। आज ऐसा नहीं होगा।

आज हम पूरा चक्र काट चुके हैं। हम अब भी लोगों का निर्यात करते हैं परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रवृत्ति थोड़ी पीछे की ओर खिसकी है। आज हम जो निर्यात कर रहे हैं संभवतः वह ऊपर से नीचे आ रहा है। कई मायनों में तो सीढ़ी उलट गई लगती है। वे लोग, जिन्हें हम निर्यात करते हैं, वास्तव में इसी देश में रहते हैं, परंतु काम वे भारत की सीमा से परे अन्य देश के उपक्रम के लिए करते हैं। जिसे आज हम बीपीओ क्रांति कहते हैं, वह विस्तृत रूप में इसी प्रवृत्ति को कहते हैं। इसी में आज हम जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं

बीपीओ कम कीमत का विशेषज्ञ कौशल वाला एक उपक्रम है। भारत में अपर्याप्त रूप से शिक्षित टेलीफोन आपरेटरों की फौज तैयार हो रही है। जब तक कारोबार मिल रहा है, तब तक सब ठीक है। आगे ईश्वर न करे। यदि, और जब भी यह रुका, तो कोलाहल मच जाएगा। केवल एक ही कौशल वाले खासकर विदेशी उच्चारण बोलने वाले अपर्याप्त रूप से शिक्षित इन 20 लाख टेलीफोन आपरेटरों का इस देश में हम क्या करेंगे? और उसके ऊपर तुर्रा यह कि लोग अनुचित रूप से उच्च मासिक आय के आदी हो चुके हैं।

इसमें आने वाले समय की दुविधा या आज की ही दुविधा को और जोड़ दें। युवा पीढ़ी बहुत कम उम्र में ही एक भड़काऊ जीवनशैली जी रही है। जल्द ही ज्यादा मिलने वाली आमदनी और व्यक्ति की आजादी के कारण ऐसा हो रहा है। इसमें रात में काम करने का समय, उबाऊ काम की उकताहट और दो विपरीत लिंगों का मौज-मस्ती के वातावरण में सामीप्य भी जोड़ें, तो सोचे कि स्थिति क्या होगी?

कार्यस्थल में यौन प्रताड़ना अब पुरानी बात हो गई है। अब किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता। आजकल सब कुछ सहमति से होता है। यौन अनुभव, पहले की अपेक्षा जल्दी ही हो जाता है और सामीप्य कम आयु में ही सुलभ होने लगा है। कोई सूर्य राममूर्ति अब 'सू' कहलाता है और अडवार के संपत कृष्णन अब आसानी से 'सैम' बन जाते हैं।

बीपीओ हब (केंद्र) की ओर जाने वाली सड़कें भी नर्क के समान होती हैं, खासकर जब खुद चलकर जाना हो तो। टोयोटा-कक्वालिस क्रांति यहां भी पर्दापण कर चुकी है। ड्राइवरों की भी मांग बढ़ गई है। अधिकांश ड्राइवर दिन और रात में 18-18 घंटे काम करते हैं। लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं। सभी ओर समृद्धि जो आ चुकी है!

बीपीओ टापू के बाहर रहने वाले लोग इस क्षेत्र से चिढ़ते हैं और मजाक उड़ाते हैं। आज बीपीओ टाइप के व्यक्ति को आप देखते ही पहचान लेंगे।

सामाजिक चुनौतियां बनी हुई हैं। आगे और भी चुनौतियां हैं। लेकिन अभी केवल इतना ही। तब तक समृद्धि को हावी होने दें। ❑

(लेखक निजी क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय परामर्शदात्री संस्था, हरीश बिजूर कंसल्ट्स इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं)

IAS दर्शन अनुसंधान केन्द्र की पहल PCS

"मीमांसा"

"The Future will depend on what U do Now."

दर्शनशास्त्र

सर्वाधिक सुरक्षित एवं अंकदायी विकल्प

द्वारा

श्वेता सत्यम्

कक्षा कार्यक्रम :- हिन्दी माध्यम में

- Foundation Course (For Mains) - 2 November
- Integrated Course (Pre Cum Mains) 9 November
- Correspondence Course (Pre Cum Mains) (2500 और 2000 का ड्राफ्ट श्वेता सत्यम् के नाम से भेजें)

निःशुल्क दिशानिर्देश सत्र प्रारंभ - 2 नवम्बर 2005, प्रातः 10 बजे

मित्रों,

दर्शनशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के लिए विशेषीकृत एवं समर्पित संस्थान के रूप में ''मीमांसा'' ने अपने तीन दिशा निर्देश सत्र (मुख्य परीक्षा 2005) के माध्यम से अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज की है।

आप सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि IAS मुख्य परीक्षा में ''दर्शनशास्त्र'' अपने संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा सीधे और सरल प्रकृति के प्रश्नों के कारण छात्रों के बीच द्वितीय विकल्प के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है।अतः इस विषय में 350+ अंकों की प्राप्ति सहजता से संभव है।

परंतु, इसके लिए विषयवस्तु की स्पष्ट एवं आधारभूत समझ के साथ-साथ सही, सटीक और तर्कसंगत दृष्टिकोण तथा प्रस्तुतिकरण एवं बिन्दुओं की प्राथमिकता तय करने की कला अपेक्षित है।

''मीमांसा'' का एकमात्र उद्देश्य आपकी अंतिम सफलता (IAS) को सुनिश्चित करना है। अतः इसके लिए ''मीमांसा'' अध्ययन व अध्यापन की एक नवीन किंतु तर्कसंगत व सटीक दृष्टिकोण तथा रणनीति को प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को सरलतमरूप में विभिन्न खंडों में विभाजित कर उसकी आधारभूत समझ का विकास तथा तत्पश्चात् प्रत्येक खंड से संबंधित उन आधारों अथवा दृष्टिकोण पर रणनीतिक चर्चा जिससे आप प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो सकें। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की सकारात्मक व रचनात्मक गतिविधियां जिससे आपकी आंतरिक क्षमता व प्रतिभा को विकसित किया जा सके।

सम्प्रति, हम आपको, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ''मीमांसा'' के ईमानदार प्रयासों से सम्बद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

शुभकामनाओं सहित

श्वेता सत्यम्

स्नेह, सुझाव, परामर्श और समाधान।

Address : A-5, Raj Tower, Near, Batra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. Mob. : 9868458076

YH/10/5/15

आउटसोर्सिंग और भारत-अमरीका व्यापारिक संबंध

❍ बदर आलम इकबाल

आज आउटसोर्सिंग के सापेक्षिक गुणों और अवगुणों के बारे में बहस की कोई कमी नहीं है। परंतु एक चीज निश्चित है, अगले कुछ वर्षों तक आउटसोर्सिंग में वृद्धि जारी रहेगी

आउटसोर्सिंग वर्ष 2004 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय बन कर उभरा है। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के गत चुनाव में भी यह एक संवेदनशील विषय बना हुआ था। अभी भी यह सबसे अधिक विवादग्रस्त और बहस का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग से अमरीका में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। यह एक सच्चाई है कि आउटसोर्सिंग के कारण अमरीका में बेरोजगारी बढ़ी है। परंतु वर्तमान वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य में ऐसा होना अवश्यंभावी है। विश्व भर में गलाकाट स्पर्धा का दबाव बना हुआ है। इससे बचने का अमरीकी फर्मों के पास कोई विकल्प नहीं है। व्यापार आज एक युद्ध का रूप ले चुका है और इससे लड़ना ही है। स्पर्धा का मुकाबला हम लागत के आधार पर रणनीति बना कर ही कर सकते हैं। सभी के लिए लागत ही मुख्य विषयवस्तु है - विश्व की कंपनियों के लिए भी और खासकर अमरीकी कंपनियों के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अमरीकी कंपनियों ने व्यावसायिक कार्यों की आउटसोर्सिंग के लिए रणनीतियां अपनाई हैं। अमरीकी कंपनियों के लिए भारत आउटसोर्सिंग का सबसे उपयुक्त स्थान सिद्ध हुआ है। भारत में कुशल और सस्ते श्रम के साथ अंग्रेजी बढ़िया ढंग से बोलने-समझने वालों की संख्या काफी है। भारत के नियमों और कानूनों को लागू करना भी अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, यथा - चीन से अधिक सरल है।

आउटसोर्सिंग परिणामों पर आधारित होता है। ग्राहक अपने अपेक्षित परिणाम को परिभाषित करता है और विक्रेता उसका साधन मुहैया कराता है। एक बार विश्वास और भरोसा बन जाए तो पूरी टीम सभी की भलाई के लिए एक सही भागीदारी बना सकती है। जैसे-जैसे अधिकाधिक संगठन आउटसोर्सिंग वाले आदर्श को अपनाने लगेंगे, विकल्प और प्रक्रियाओं में सुधार होगा और यह यात्रा और सुगम होती जाएगी।

आउटसोर्सिंग (बीपीओ) में व्यापार संपन्न कराने वाली प्रक्रियाओं और उनकी क्रियात्मक इकाइयों को बड़ी बारीकी से देखना और उसके बाद सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकर इन क्रियाओं को आउटसोर्स करना शामिल होता है। दावा प्रबंधन, मानव-संसाधन, वित्त और अनुपालन जैसे कार्य बाहर से कराए जा सकते हैं। आउटसोर्सिंग प्रदाता इन कार्यों को मान्य सेवा मानकों और गारंटी लागत के अनुसार अपनी स्वयं की प्रणालियों पर लागू करता है। अक्सर देखा गया है कि वे अधिकारी जो प्राय: आउटसोर्स किए जाने वाले व्यापार से जुड़े नहीं होते, वे ही बीपीओ के बारे में समझौते के लिए बातचीत करते हैं। आपकी कंपनी वांछित सेवा स्तर और लागत लाभ पा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मानव-संसाधन, वित्त अथवा आउटसोर्स की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं के अधिकारियों को आउटसोर्सिंग समझौते के विवरणों का भलीभांति ज्ञान हो, जिससे करार पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले वे उस पर अपना प्रभाव डाल सकें। अधोलिखित पांच नियमों के आधार पर सफल संबंधों के लिए आवश्यक कार्य पद्धति और संरचना तैयार की जा सकती है। यद्यपि मेरी विशेषज्ञता तो मानव-संसाधनों की आउटसोर्सिंग के बारे में है, लेकिन ये नियम किसी भी आउटसोर्स कराने वाले व्यक्ति के लिए सही लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

आउटसोर्सिंग व्यापार के लिए पांच बुनियादी नियम हैं और भारत से आउटसोर्सिंग कराते समय अमरीकी कंपनियां इनका पालन करती हैं :

- आउटसोर्सिंग समझौता सही होना चाहिए।
- शीघ्र प्रारंभ न करने वाले प्रबंधन को बदल दें।
- संक्रमण ठीक ढंग से होना चाहिए।
- ग्राहक प्रबंधक से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें।
- इस पर विजय पाइए, यह एक नया और बेहतर संसार है।

आउटसोर्सिंग परिदृश्य

आउटसोर्सिंग उद्योग दिन-प्रतिदिन ताकतवर होता जा रहा है। तकनीकी समर्थन और वित्तीय सेवाओं ने भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग को प्रभावित किया है। अब अन्य नये-नये क्षेत्र उभरकर सामने आ रहे हैं। आशा है, ये नये क्षेत्र इस उद्योग को और भी कई गुना आगे बढ़ाएंगे। गार्टनर के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002 में सेवा आउटसोर्स उद्योग कुल एक खरब डालर का आंका गया था। वर्ष 2007 तक यह आंकड़ा 1 खरब 73 अरब डालर तक पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2003-04 में भारतीय कंपनियों ने 3 अरब 50 करोड़ डालर का राजस्व अर्जित किया, जो विश्व बाजार के दो प्रतिशत के बराबर रहा। इसलिए इस क्षेत्र में वृद्धि के बेहतर अवसर हैं।

भारत की स्थिति क्या है?

नैसकॉम के सर्वेक्षण पूरे विश्व में वर्ष 2002 में प्रौद्योगिकी जनित सेवा-बीपीओ उद्योग, का कुल मूल्य 7 खरब 73 अरब डालर का था और विश्वव्यापी इंटरनेशनल डेटा कार्पोरेशन के अनुसार 2005-06 की अवधि के दौरान इसके कुल मिलाकर नौ प्रतिशत की वार्षिक दर (सीएजीआर) से बढ़ने की आशा है। नैसकॉम ने भारत में आईटी जनित सेवा-बीपीओ उद्योग की विकास संभावनाओं के प्रमुख संकेतकों की सूची बनाई है। वर्ष 2003-04 के दौरान आईटी जनित सेवा-बीपीओ उद्योग में इसके पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था। आईटी जनित सेवा-बीपीओ उद्योग में बेरोजगारों के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हुए हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान इस क्षेत्र में 74 हजार 4 सौ अतिरिक्त लोगों के लिए कार्य अवसर सृजित हुए। मार्च 2004 तक इस क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या 2 लाख 45 हजार 5 सौ तक पहुंच गई थी। नैसकॉम और मैकिन्स से एंड कंपनी द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 2008 तक इस क्षेत्र में करीब 11 लाख भारतीयों को रोजगार मिलने की आशा है। बाजार के अध्ययन से स्पष्ट है कि कार्य सृजन (रोजगार के अवसर) के मामले में आईटी जनित सेवा-बीपीओ उद्योग 50 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

भारत विश्वशक्ति कैसे बना?

ई-वैल्यूसर्व नामक एक व्यापार सूचना और अनुसंधान फर्म ने वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक इंस्टीच्यूट के लिए किए गए एक अध्ययन में बताया है कि भारत को आउटसोर्सिंग के लिए पसंदीदा स्थान बनाने में भारतीय मूल के प्रोफेशनलों, वेंचर कैपिटलिस्टों (केवल प्रस्तावों के आधार पर पूंजी लगाने वाले) और उद्यमियों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इस अध्ययन के अनुसार, हालांकि कुछ कम लागत में काम करने वाले देश भी धीरे-धीरे भारत के समकक्ष आने के प्रयास में हैं, परंतु आउटसोर्सिंग के मामले में यह उपमहाद्वीप विश्व में, खासकर अमरीका, कनाडा और इंग्लैंड में भारतवंशियों के बढ़ते प्रभाव और विशेषता के कारण अपनी बढ़त बनाए रखेगा।

भारत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बात यह जाती है कि भारतवंशियों की संगठित नेटवर्किंग और संरक्षण में आउटसोर्सिंग व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है।

अध्ययन के अनुसार, 1960 के दशक में अमरीका जाने वाले इंजीनियरों में से अनेक 1990 के दशक के आते या तो उद्यमी बन गए थे या बड़ी और मध्यम आकार की वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियों में वरिष्ठ कार्यकारी बन चुके थे। इनमें से अधिकांश प्रोफेशनलों ने भारत में अपनी कंपनियां शुरू की, जबकि कुछ अन्य ने अपनी कंपनियों को भारतीय आईटी प्रोफेशनलों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे भारतीय प्रतिभाओं को जानने के अधिक अवसर मिले और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत वंशियों की शक्ति और प्रभाव में और भी वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ, 1999 के अंत तक सिलिकॉन वैली में काम करने वाले आईटी प्रोफेशनलों में से भारतीयों की संख्या 24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

अध्ययन से यह भी पता चला कि अमरीका के कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट, खासकर भारतीय मूल के लोग उन कंपनियों में धन लगा रहे हैं, जिनका अंतिम छोर भारत में है। इससे अनुसंधान एवं विकास की लागत में उनको काफी बचत हुई। मार्च तक अमरीका स्थित 150 से भी अधिक उन कंपनियों की जिन्होंने अपना व्यवसाय वहां शुरू किया, कुछ न कुछ गतिविधियां भारत में भी चल रही थीं। उसी अध्ययन के अनुसार मार्च 2006 तक इस संख्या के दुगना हो जाने का अनुमान है। व्यवसाय प्रारंभ करने वाली नयी कंपनियों के लिए अन्यत्र अनुसंधान और विकास की सुविधा का होना एक महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाती है, क्योंकि आजकल इन कंपनियों को पहले की अपेक्षा इस मद में अधिक धनराशि नहीं मिल पा रही है। किसी भी कार्य को भारत या अन्य किसी आउटसोर्सिंग गंतव्य को ले जाने में इस बात का महत्व ज्यादा होता है कि खास कर्मचारी कहां से आते हैं। उच्च पदों पर बैठे, निर्णायक भूमिका निभाने वाले कार्यकारी अधिकारी अपने मूल स्थान की ओर जाने का प्रयास करते हैं। एक भारतीय विशेषज्ञ के अनुसार, 'इसके बावजूद इस तरह के फैसले अंततोगत्वा व्यापारिक आधार पर लिए जाते हैं।'

अध्ययन का निष्कर्ष था कि इंटरनेट क्षेत्र और नयी सहस्राब्दी के प्रारंभ में कुशल श्रम के मामले में अचानक आई मांग ने भारतीय इंजीनियरों और तकनीशयनों को भारतवंशियों की किसी भूमिका के बगैर वैश्विक आईटी उद्योग की ओर आकर्षित किया। यह ऐसे हुआ कि भारतवंशियों ने भारत के आईटी उद्योग को शुरू करने में सहयोग दिया और भारत में जब तक इस क्षेत्र में तेजी आई तब तक भारत दूसरे देशों से काम कराने के मामले में एक संभावित विकल्प बन चुका था। हालांकि प्रवासी भारतीयों का विचार है कि भारतवंशियों ने आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती मांग के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। आईटी उद्योग में भारत को विश्वस्तरीय शक्ति बनाने में उनके योगदान को वे ज्यादा महत्व नहीं देते। इसके विपरीत, वे देश जिनके

लोग प्रवासियों के रूप में उतनी प्रभावी भूमिका में नहीं हैं, पीछे से पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों को इस तेजी में अपनी भूमिका अदा करने का मौका नहीं मिला। हमें लगता है कि भारतवंशियों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है। हालांकि प्रवासियों का मानना है कि भारतवंशियों की भूमिका, आउटसोर्सिंग उद्योग में यकायक तेजी लाने में, एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में रही है, कई लोग आईटी उद्योग में भारत की विश्व शक्ति की भूमिका को हल्के रूप में लेते हैं।

अमरीकी फर्मों के लिए अवसरों का देश

आज आउटसोर्सिंग के सापेक्षिक गुणों अथवा अवगुणों के बारे में बहस की कोई कमी नहीं है। एक चीज अवश्य निश्चित है: वह यह कि आउटसोर्सिंग अगले अनेक वर्षों तक बढ़ती ही रहेगी। वर्ष 2001 से तकरीबन 5 लाख आईटी नौकरियां अमरीकियों के हाथ से निकल गई हैं। इनमें से अधिकांश विदेशों में आउटसोर्सिंग के कारण गई हैं। कारपोरेट जगत का चूहे जैसा अचर्चित व्यवहार आने वाले वर्षों में भी वृद्धि को ईंधन प्रदान करता रहेगा। जब जीई द पॉट, सिटी बैंक, जीएमांया, प्राक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां कुछ करती हैं तो दूसरे उनको गौर से देखते हैं और कई उनका अनुगमन करते हैं।

अमरीका-भारत व्यापार संबंधों पर प्रभाव

अभी हाल ही में अमरीका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने कहा था कि "अमरीकी कंपनियों द्वारा अमरीकी कर्मचारियों का स्थान लेने के लिए विदेशों से कर्मचारियों को नौकरी देना 21 शताब्दी की हकीकत है। लेकिन भारत को अमरीकी काम के अवसरों में आई गिरावट को रोकने के लिए कुछ और करना होगा, और उसे अपना बाजार अमरीकी माल (सामानों) के लिए खोलना चाहिए। अमरीका से भारत जाने वाली नौकरियां दो लाख से ज्यादा नहीं हैं, परंतु अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव वर्ष में यह एक विवादास्पद विषय बन गया था। इस वर्ष वैसे भी कार्य अवसरों में वृद्धि नगण्य ही रही है।"

अमरीकी फर्मों द्वारा भारत से आउटसोर्सिंग कराने का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत को इससे अधिक लाभ होगा। यह भारत के कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करेगा और प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा। लेकिन दूसरी ओर वर्तमान अवसरों के तहत विदेशी निवेश सीमित मात्रा में ही हो सकता है, क्योंकि इन परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाएं नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त वास्तविक संपत्ति (रियल इस्टेट) का क्षेत्र अभी भी अधिकांशत: प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां अमरीकी फर्मों के लिए निवेश हेतु अधिक और लाभदायक अवसर हो सकते हैं। राष्ट्रपति बुश की निर्वाचन में सफलता, भारत से आउटसोर्सिंग के बारे में बेहतर समझदारी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

अमरीकी फर्मों द्वारा भारत से आउटसोर्सिंग कराने का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत को इससे अधिक लाभ होगा। यह भारत के कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करेगा और प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा। लेकिन दूसरी ओर वर्तमान अवसरों के तहत विदेशी निवेश सीमित मात्रा में ही हो सकता है, क्योंकि इन परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाएं नहीं माना जाता

जब विदेशी भागीदारी के लिए निवेश का मामला इतना सुदृढ़ हो, तो भारत इस तरह के लाभदायी बाजार में विदेशी निवेशकों को आने की अनुमति कैसे दे सकता है? इसके अनेक कारण हैं: पहला, विदेशी भागीदारी संस्कृति का विकास होगा और दूसरे, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होने का वातावरण बनेगा। (भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने की अनिवार्य शर्त)। तीसरे, स्थानीय उद्योग का स्तर ऊंचा उठेगा। चौथे, धन (वित्त) की उपलब्धता से बड़ी और बेहतर परियोजनाएं विकसित होंगी।

अमरीका की 500 सबसे तेजी से बढ़ रही कंपनियों में से एक भारत से आउटसोर्सिंग पर आधारित है। 'टेक बुक्स प्रकाशन' प्रौद्योगिकी की समस्याओं के समाधान के व्यवसाय से जुड़ी है, भले ही वे किसी भी क्षेत्र – मीडिया, ऑनलाइन और बेतार से संबंधित हों। कंपनी, प्रकाशन घरों की उनकी प्रकाशन की सामग्री के विकास, डिजाइन और ले-आउट को पूरी तरह से आउटसोर्स कर उनकी मदद करती है। दूसरे देश के व्यापार आदर्श का उपयोग करते हुए वह भारत में काम कराकर अपने ग्राहकों को कम लागत पर समाधान पेश करती है। कंपनी का व्यवसाय मुख्य रूप से अमरीकी और यूरोपीय बाजारों में केंद्रित है और उसके अधिकांश ग्राहक प्रकाशन उद्योग से संबंधित हैं।

आउटसोर्सिंग का विरोध

यह एक उदीयमान उद्योग है और "आउटसोर्सिंग एक ऐसी ट्रेन है, जो स्टेशन छोड़ चुकी है।" लेकिन विकसित देशों में आउटसोर्सिंग का विरोध राजनीतिक तौर पर जरूरी है। इसके बावजूद बीपीओ आर्थिक कारणों से जारी रहने वाला है। मैंने राजनीतिज्ञों से पूछा कि क्या वे अपने व्यापार की आउटसोर्सिंग के जरिये प्रचालन लागत में 30 प्रतिशत की बचत करना नहीं चाहेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, "जरूर चाहेंगे, पर हम राजनीतिज्ञ भी हैं और यह भी जानते हैं कि आउटसोर्सिंग का विरोध करने से वोट भी मिलेंगे।" आउटसोर्सिंग यदि गलत हो रही है तो उससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आप अपनी प्रतिभाओं का विकास, उनको कार्य अनुभव का अनिवार्य और व्यापक अवसर दिये बिना कैसे कर पाएंगे, खासकर जब इन अवसरों को अन्यत्र भेजा जा रहा है? मुझे लगता है कि अमरीकी फमो ं के लिए आउटसोर्सिंग की यात्रा पर बढ़ते समय कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। यदि ये समस्याएं

आती हैं, तो इनका समाधान परस्पर बातचीत से ही होना चाहिए, जिससे आने वालों वर्षों में अमरीका और भारत के व्यावहारिक संबंधों पर कोई असर न पड़े। चुनौती भरे विश्व परिदृश्य में आउटसोर्सिंग आज एक आवश्यकता बन चुकी है। भारत और अमरीका अपवाद नहीं हैं।

विवादास्पद विषय

भारत के कराधान अधिकारियों के बाद भारतीय बीपीओ फर्मों पर निशाना साधने की बारी अब अमरीकी वित्तीय नियामकों की है। अमरीका के मुद्रा महापरीक्षक द्वारा अगले वर्ष से लेखा परीक्षा किए जाने की प्रत्याशा में भारतीय बीपीओ कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निजी इकाइयां अपने अमरीकी प्रतिरूपों से इन लेखा परीक्षाओं की बारीकियों के बारे में जानकारी लेने में जोर-शोर से लगी हुई हैं।

हालांकि इन लेखा परीक्षाओं में क्या शामिल होगा, इसके बारे में बीपीओ कंपनियों ने पुष्टि की है कि उन्हें उन नियमों-शर्तों के बारे में जानकारी है, और इनका सामना करने के लिए अपने भारतीय प्रचालन को तैयार कर रहे हैं। मुख्य लक्ष्य वे कंपनियां होंगी जिनकी वित्तीय सेवायें आउटसोर्स होती हैं, खासकर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां। मुद्रा महापरीक्षक कार्यालय (आफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ दि करेंसी - ओसीसी) अमरीका में बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित, सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से चलाने के लिए उन पर नजर रखता है। यह लेखापरीक्षण अगले वर्ष से शुरू होने की आशा है। संभावना है कि वे लोग न केवल नियमों के अनुपालन की जांच करेंगे, बल्कि प्रणालियों, प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंधन और गोपनीयता की धाराओं के अनुसरण की भी जांच कर सकते हैं। अर्न्सट एंड यंग के भागीदार राम अग्रवाल का कहना है कि इस बारे में सफलतापूर्वक शुरुआत करने के लिए हमारी बातचीत एक अमरीकी कंपनी से जारी है। ई एंड वाय पहले से ही भारत में अनेक बीपीओ इकाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण की समीक्षा करता आ रहा है।

अमरीकी फर्मों के आउटसोर्सिंग के विवादास्पद विषय पर चर्चा के लिए अमरीका की रणनीति अनुसंधान संस्थान (स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीच्यूट) 19 जनवरी, 2005 को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिनमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाएगा:

- वैश्विक सोर्सिंग के जरिये आपके संगठन का पूर्णरूपेण परिवर्तन।
- निजी (नियंत्रित) केंद्र तैयार करने के पीछे की रणनीति को समझना।
- अन्य देशीय रणनीति विकसित करना और तीसरे पक्ष से सोर्सिंग कराने संबंधी मानचित्र तैयार करना।
- बड़े-बड़े आउटसोर्सिंग देशों का मूल्यांकन।
- नये नियामक वातावरण में वैश्वीकरण।
- अन्य देशीय (आफशोर) आउटसोर्सिंग से वैश्वीकरण की ओर प्रयास करना।
- वर्तमान वैश्विक परिचालनों के स्वास्थ्य (उनकी सुदृढ़ता) की जांच करना।
- परिणामचालित आउटसोर्सिंग के लाभों और खतरों में संतुलन स्थापित करना। ❑

(लेखक संयुक्त राज्य अमरीका के आरेंजनबर्ग (एस. सी.)के क्लेफिन बिजनेस स्कूल में फुलब्राइट अतिथि प्राध्यापक हैं)

IAS-06/ PCS (PT M)
Sub. :- G.S.- Expert Team
सामाजशास्त्र- महेश प्रसाद, लोक प्रशासन- डा० संजय कुमार
इतिहास- डा० एम० रहमान, मानवशास्त्र- डा० आर० के० सिंह
LAW, GEO., LSW by Experts
विशेष बैच CDPO | गृहविज्ञान, बालविकास,अर्थशास्त्र,पोषण
★ नियमित टेस्ट सिरीज ★ प्रश्नोत्तर लेखन पर विशेष बल
★ अध्ययन की अद्यतन उपागम ★ नियमित Quiz एवं विश्लेषण ★ कम्प्युटराइज्ड अध्ययन- सामग्री
निःशुल्क कार्यशाला : 14 & 15 Oct.
Patna west | Patna East
Civil Services Academy
Maa Baghwati Complex Boring Road Chouraha, Patna-1 Mob.: 9835232515
The Academy
3rd. Floor, Kulharia Complex, Ashok Rajpath, Patna-4, Mob. : 9835460440
YH/10/5/19

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

क्या सूचना सुरक्षा की दृष्टि से इसकी समीक्षा जरूरी है? यह है क्या?

हाल ही में एक भारतीय वेब-मार्केटिंग फर्म द्वारा ब्रिटेन के ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचना अवैध तरीके से किसी अन्य को दिए जाने को लेकर उठे विवाद के बाद प्रधानमंत्री ने साइबर कानूनों में संशोधन की बात कही है ताकि ऐसे किसी अवैध हस्तांतरण को दंडनीय अपराध माना जाए और सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। डा. मनमोहन सिंह ने सूचना टेक्नोलॉजी विभाग और इस उद्योग के एसोसिएशन नैसकाम से कहा है कि वे सभी स्वत्वधारकों से सलाह-मशविरा करें और वर्तमान कानूनों में संशोधन के सुझाव दें।

सूचना टेक्नालाजी अधिनियम, 2000 की समीक्षा पर विशेषज्ञ समिति ने आंकड़ों की चोरी और अश्लीलता रोकने के लिए कड़े दण्डात्मक उपायों का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों का यह भी उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा प्रदाता, साइबर कैफे आदि बिचौलियों को नाहक परेशान किए जाने से बचाया जा सके और उन्हें वैसी स्थिति का सामना फिर न करना पड़े जैसा कि पिछली बार हुआ था।

हाल ही की एमएमएस पोर्न और बी.पी.ओ. हैकिंग की घटनाओं के बाद समिति ने वीडियो पोर्न और चाइल्डपोर्न जैसी दो अलग एनटिटीज कायम की हैं और दोनों के लिए अधिक दंड की व्यवस्था है।

समिति ने सुझाव दिया है कि डिजिटल हस्ताक्षर के अलावा इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर भी मंजूर किए जाएं। इनसे ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर भी मंजूर किए जाएं। इनसे ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक डाक्यूमेंट भेजने वाले को पहचानने में आसानी होगी। प्रस्तावों के अनुसार 'हैकिंग' को अपराध सूची से निकाल दिया गया है अर्थात अनुच्छेद 66 को नए रूप में पढ़ा जाए और 'हैकिंग' तथा 'हैकर' शब्द काट दिए जाएं।

समिति ने अश्लीलता पर गंभीर रवैया अपनाया है। किसी व्यक्ति का उसकी जानकारी बिना फोटो लेना और उसकी सहमति बिना कहीं भेजना निजता का उल्लंघन माना जाएगा। इलेक्ट्रानिक अश्लीलता की व्यवस्थाओं में भी संशोधन प्रस्तावित है ताकि इन्हें भारतीय दंड संहिता के अनुरूप बनाया जा सके और दोनों अनुच्छेद बाल-अश्लीलता और वीडियो कामुकता को शामिल करें। अधिक सजा की भी सिफारिश की गई है।

हाल के बीपीओ घोटाले, ई-थेफ्ट और ई-जालसाजी के बावजूद सूचना सुरक्षा के लिए अभी भी बड़े, छोटे और औसत दर्जे के उद्यमों में जागरूकता नहीं है।

कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ (सीआईआई) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल किए 86 उद्यमों में से 38 प्रतिशत की कोई सूचना सुरक्षा नीति नहीं है जबकि 7 प्रतिशत ने कोई जवाब ही नहीं दिया जिससे संकेत मिलता है कि सुरक्षा नीति के प्रति उदासीन हैं। लेकिन सर्वेक्षण में शामिल उद्यमों से 86 प्रतिशत अपने संगठन में सूचना सुरक्षा नीति की जरूरत जाहिर की। लेकिन 32 प्रतिशत ने पीपुल्स सर्टिफिकेशन और 23 प्रतिशत ने प्रोसेस सर्टिफिकेशन की जरूरत मानी। सर्वेक्षण से पता चला कि इन संगठनों के 72 प्रतिशत के अपने सिक्यूरिटी प्रोसेस सर्टिफिकेशन नहीं हैं।

जहां तक कर्मचारियों, गैर-कर्मचारियों और ठेकेदारों को पहचानने का सवाल है, 74 प्रतिशत उद्यमों के पास ऐसा तंत्र है जिससे संगठन के अंदर उनकी पहचान और नियंत्रण किया जा सकता है।

सर्वेक्षण ने निष्कर्ष निकाला कि बिजनेस आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के जोखिम बने हुए हैं। हालांकि सुरक्षा की जरूरत की मोटे तौर पर समझ है, लेकिन इन खतरों के प्रभावों की स्पष्ट समझ नहीं है। यही कारण है कि सूचना टेक्नालाजी सुरक्षा को अब भी कम प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाता है।

सर्वेक्षण के अनुसार जिन उद्यमों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया उनके 40 प्रतिशत के पास कोई नेटवर्क, संरक्षण अथवा सूचना और डेटाबेस का कोई अलग प्रशासन नही है। लगभग 30-35 प्रतिशत के पास न तो बिजनेस निरंतरता योजना है और न ही कोई स्थापित आपदा पुन: प्राप्ति योजना है।

सर्वेक्षण में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। शामिल कंपनियों में एफएमसीजी, आईटी/आईटीईएस, बीपीओ इंटरनेट सर्विसेज, भारी मशीनरी/ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, इंश्योरेंस और भवन निर्माण थे। इसमें प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी और आईटी प्रमुख स्तर के अधिकारी शामिल हुए।

प्रस्तावित संशोधन

- अनुच्छेद 66 : पहले हैकिंग से संबंधित था, अब इसके अंतर्गत कंप्यूटर संबद्ध अपराध आएंगे।
- अनुच्छेद 67 : इलेक्ट्रानिक रूप में

भारत निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता की मांग

भारत इस कार्यक्रम पर एक अरब डालर खर्च कर सकता है: मोंटेक

भारत ने विश्व बैंक को बता दिया है कि ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से संबंधित भारत निर्माण पर बैंक की लगभग एक अरब डालर की सहायता का उपयोग किया जा सकता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने विश्व बैंक के अध्यक्ष, श्री पाल वोल्फोविट्ज़ को यह जानकारी दी है।

योजना आयोग ने सरकार की भारत निर्माण नाम की प्रमुख योजना पर श्री वोल्फोविट्ज़ के समक्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस पर 1,74,000 करोड़ रुपये लागत आएगी। विश्व बैंक प्रमुख को भारत में मूल सुविधाओं की सामान्य स्थिति की भी जानकारी दी गई और प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमों से अवगत कराया गया।

उपाध्यक्ष ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने विश्व बैंक के सामने कोई खास अनुरोध नहीं रखा लेकिन बताया कि भारत निर्माण पर एक अरब डालर की सहायता का सदुपयोग किया जा सकता है। सरकार ने दिखाया कि उसे इस समय मिल रही 3 अरब डालर से ज्यादा वार्षिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। महाराष्ट्र जल परियोजना के लिए 3.25 अरब डालर ऋण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के पूरी होने पर महाराष्ट्र में सिंचाई सुविधाओं में 22 प्रतिशत और कृषि उपज में 5 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

चार दिन की भारत यात्रा के अंत में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विश्व बैंक अध्यक्ष ने कहा कि उनकी संस्था भारत निर्माण के लिए अगले तीन वर्षों में 3 अरब डालर देने को तैयार है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बैंक की उस 9 अरब डालर के पैकेज का एक भाग होगा जो विश्व बैंक 3 अरब डालर प्रति वर्ष की दर से अगले तीन साल तक देने को सहमत हुआ है। विश्व बैंक की सहायता से सरकार हर साल 1 अरब डालर तक की राशि भारत निर्माण पर खर्च कर सकेगी।

विश्व बैंक प्रमुख ने 1991 से भारत की प्रगति को अत्यधिक और अविश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा कि तेजी से सुधार लागू करके सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर 8 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत ऊपर पहुंचाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण मूल सुविधाओं की ठीक योजना बनाई है और महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं में निवेश किया जाना चाहिए। ❑

(संकलन: बी.एन. त्रिपाठी, संपादक (हिंदी))

भारत निर्माण की लागत

		करोड़ रु. में
सिंचाई	-	68,500
सड़कें	-	47,554
आवास	-	11,100
पेयजल	-	25,300
ग्राम विद्युतीकरण	-	23,300
टेलीफोन	-	451
योग		**1,76,205**

चार वर्षीय भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार ने 66,822 गांवों में फोन सुविधा जुटाने, 1,25000 गांवों का विद्युतीकरण करने और 55,067 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। ❑

(स्रोत संसदीय प्रपत्र)

अश्लीलता। भा.दं.सं. के अनुरूप संशोधित। जुर्माना बढ़ाया गया।

- बाल अश्लीलता से संबद्ध नया अनुच्छेद जोड़ा गया और दंड बढ़ाया गया। वीडियो कामुकता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।
- अनुच्छेद 69 : संशोधित। किसी भी कंप्यूटर के द्वारा किसी सूचना पर नजर रखने या हस्तक्षेप करने के निर्देश जारी करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 78-ए : नया। न्यायपालिका को तकनीकी मुद्दों पर सहायता के लिए।
- अनुच्छेद 79 : संशोधित। कुछ मामलों में बिचौलियों की जिम्मेदारी की सीमा निर्धारित करने के लिए।
- दंड संहिता के सामान्य प्रावधान लागू होंगे। केवल डी.एस.पी. या अन्य को छानबीन के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।
- इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर की अनुमति होगी, डिजीटल हस्ताक्षर के अतिरिक्त।
- "इलेक्ट्रानिक कांट्रैक्ट्स के सूत्रीकरण और वैधता" के लिए नया अनुच्छेद।
- सूचना संरक्षण और निजता के लिए अधिक कठोर मापदंड। ❑

बीपीओ उद्योग में पारदर्शी नेतृत्व

○ डैन संधू

पारदर्शिता एक दिन में नहीं आ पाती। यह एक प्रक्रिया है, जो 'निष्ठा को सेवा में लेने' जैसी चीज से शुरू होती है

संगठनात्मक पारदर्शिता अब अपने संकुचित आवरण से बाहर आ रही है। पहले जो बहुचर्चित बहस भरी धारणा मात्र थी, अब एक ऐसी आचार-संहिता बन गई है, जो उत्कृष्ट नेताओं को प्रतिष्ठित बनाती है- एक ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों को कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिये प्रेरित करता है। यह किसी संगठन में मूल्य संरचना भर देता है, जो महज योजना-निपुण कार्पोरेट लक्ष्यों और कार्यों को परे ले जाकर आधारभूत और अपेक्षित व्यावहारिक सिद्धांतों में बदल देता है।

पारदर्शी नेतृत्व उस संगठन की मानसिक स्थिति को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है, जिसमें संचार की केंद्रीय भूमिका होती है। बीपीओ उद्योग का युवापन इसे मुक्त संस्कृति को स्वीकार करने के लिए और भी अधिक प्रवृत्त करता है और उदाहरण के साथ नेतृत्व करने की भावना भी देता है जो अपने आप में पारदर्शिता के सिद्धांत का समर्थन करता है। अधिकांश पारंपरिक उद्योगों में यह भावना इतनी नहीं होती है। यह एक खुली और सकारात्मक मानसिक स्थिति है, जो कहती है कि हम अपनी टीम, अपने ग्राहक और अपने अन्य अंशधारकों को समान सम्मान देते हैं। वे सभी हमारे व्यापार के हिस्से हैं और हम उन्हें ऐसा बताते भी हैं। वे भागीदार तब तथ्यों के आधार पर फैसला कर सकते हैं न कि किसी कटाक्ष के आधार पर, परस्पर समझ के आधार पर न कि एकांशी संप्रेषण पर।

पारदर्शी नेतृत्व विश्वसनीयता का निर्माण करता है और यह अंतर्निहित सम्मान और भरोसे को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन की सफलता सभी स्तरों पर पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करती है। इस उद्योग में तैयार किए जा रहे अगुवा (अधिकारी) सभी स्तरों पर इसी बुनियादी व्यक्तिगत भरोसे पर नेतृत्व का आधार मानकर विश्वास करते हैं। इस तरह के संपर्क परस्पर विश्वास, भरोसे, परवाह और सराहना से बनते हैं। इस तरह का जीवंत उदाहरण 'वर्टेक्स' में देखा जा सकता है जहां हम मुश्किल से खड़े होने की स्थिति में थे और अब हमारी क्षमता 1,900 तक पहुंच गई है। इस उद्योग का सबसे कम ह्रास दर हमारे ही यहां है। हमारे करीब 25 प्रतिशत कर्मचारी वर्टेक्स परिवार में आंतरिक संदर्भों के आधार पर ही आते हैं और अन्य 24 प्रतिशत मौखिक संचार के माध्यम से आते हैं, न कि विशेष भर्ती अभियान के जरिये। यह कभी संभव नहीं होता यदि हमारी खुली और ईमानदार संस्कृति ने तीन-तरफा संचार को सुविधाजनक न बनाया होता। एक बार यह धरातल अच्छी तरह से तैयार हो जाए और वैसी ही बनी रहे तो अगुवाई करने वाले लोग बाकी नतीजे देने का काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब अग्रिम पंक्ति के लोग यह धरातल नहीं बना पाते, या टीम के साथ संपर्क कमजोर होता है, तो उच्चस्तरीय सफलता और प्रभावशीलता की ओर बढ़ने की संभावना क्षीण हो जाती है।

यह बात तब और भी ज्यादा सही साबित होती है जब संगठन के बाहर के लोगों से, चाहे वे ग्राहक हों या आपूर्तिकर्ता, व्यवहार की बात आती है। परिदृश्य की घटनाओं के जानने से स्वस्थ व्यवहार होता है, चाहे वह हमारे पक्ष में हों या निंदक।

किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा की गई कोई टिप्पणी लाभ की कैसे हो सकती है, जब तक कि वे उनके फैसलों पर प्रभाव डालने में समर्थ न हों। आलोचना के नजरिये से देखें तो इन संबंधों में कार्यस्थल की एक पंक्ति होनी आवश्यक है। पारदर्शिता जितनी सूचना से संबंधित है, उतनी ही इस बारे में कि कैसे वह सूचना हासिल हो सके। वे बहुस्तरीय (अर्थात अक्षम) संगठन जो विभिन्न पक्षों के बीच काफी अंतर छोड़ देते हैं, संप्रेषण को अपारदर्शी बनाने में उतने ही गुनहगार हैं।

अंत में, जैसा कि जीवन में अन्य चीजों के साथ बहुधा होता है, यह हर दिन का इस तरह समाप्त करने की योग्यता ही है कि आपको पता हो कि आपने जो कुछ किया है, वह सही है और कुछ भी हो, आपने अपने मूल्यों को जिया है। यही बात उन लोगों का अंतर स्पष्ट करती है, जो शीर्ष पर बैठकर नेतृत्व करते हैं और जो सामने रह कर स्पष्ट उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रेरकों के अनुसार नेतृत्व करते हैं। बीपीओ की टीम को प्रत्येक स्तर पर इसे ध्यान में रखने की जरूरत है, न केवल अपने टीम के अगुआ से बल्कि हर उस भूमिका में जो उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव डालती है। लक्ष्यों के बारे में, चाहे वे संचालन संबंधी हों या व्यापार संबंधी, दृष्टि स्पष्ट हो और उनको पाने का प्रयत्न किया जाए तो काम के निष्पादन पर और सफलता पर उनका सार्थक और निश्चित

प्रभाव पड़ता ही है।

अगुवा (नेता) तो वही होता है, जो टीम को स्वीकार्य हो। नेतृत्व को विशेषाधिकार मानना चाहिए न कि हक, आनंद न कि विवशता। टीम के साथ रहने से जो सम्मान और भरोसा मिलता है, उसे सत्य नहीं मान लेना चाहिए। दोनों को जीतना पड़ता है और फिर उसे बनाए रखना होता है। यह सब बहुउच्चारित मूल्यों से ही प्राप्त होता है, और मूल्यों के लिये अगुवाओं को अपने सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शी होना होगा। जिस गति से बीपीओ संगठन टीम सदस्यों को नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बिना नेतृत्व क्षमता यह आकलन किए कि उनमें है या नहीं, इसे एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय बना देता है। पारदर्शिता बरतने से ये मूल्य संगठन में परिलक्षित होते हैं। जिस संगठन में मूल्यों पर बहस होती है, नेतृत्व को आगे आकर चलना होगा। नेतृत्व को अवश्य ही पारदर्शी होना चाहिए, नेतृत्व को वही मानक स्थापित करने होंगे, जिनके बारे में बोला करता है।

जब किसी बीपीओ में प्रचालन कर्मियों की भर्ती होती है, कितने लोग उम्मीदवार को भावी कार्य प्रमुख के तौर पर देखते हैं, और कितने उसे एक साध्य (कार्य) को हासिल करने वाले साधन (व्यक्ति) के रूप में। यदि आप में शुरू से ही ऐसा विचार नहीं बनाया तो आगे सब कुछ गड़बड़ ही होगा। सफलता नहीं मिलेगी। ईमानदारी और निष्ठा की इस बुनियाद पर उदाहरण द्वारा नेतृत्व करने के संगठन के मूल्यों को भी जोड़ दें। ऐसी टीम बनाऐं जो बुनियादी मूल्यों, लगन और विश्वासों के बारे में समान विचार रखती हो। पारदर्शी नेतृत्व रचनात्मक चुनौतियों से बनती है। प्रतिसूचना (फीडबैक) अवश्य मांगे, क्योंकि इसी से पारदर्शिता को मापा जा सकता है।

ईमानदार बनें और अपने सभी पत्ते मेज पर खोल दें। इस प्रकार आप अपने सहयोगियों को अपने काम में मन से शामिल कर सकेंगे और व्यापार में सफलतापूर्वक काम ले सकेंगे। इससे यह भी पता चलेगा कि आप अपने कर्मचारियों की परवाह करते हैं। कठिनाई के क्षणों में उनके बीच में रहें, क्योंकि जब कभी आप गिरें तो वे आपको उठा सकें। टीम की सहायता के लिए भद्र (आभारी) बनिये। जितना वे आप से सीखते हैं उतना ही आप भी उनसे सीखें। सफलता का जश्न मनाइये और असफलताओं से सबक लें। टीम की उसकी एकाकी योग्यताओं से ऊपर उठाइये और बेहतर बनाइये। टीम के क्षितिज का विस्तार वैयक्तिक विकास के माध्यम से करिये। कोई भी नकद पुरस्कार, विशेष उपहार, या कीमती संदेश या पार्टियां, इसका स्थान नहीं ले सकतीं। पारदर्शिता भरोसे पर ही कायम होती है, अत: वचनबद्धता को सर्वोच्च सम्मान दीजिये। यदि किसी मौके पर दिए गए वचनों को बदला हो तो लोगों को उसके बारे में अवश्य बताएं। खबरें जैसी हों, बताइये, पर जरा ढंग से।

व्यापार के आंतरिक और बाहरी, अंशधारक टीम को बनाने की योग्यता और व्यापार की दृष्टि समझाने की कीमत पहचानेंगे व्यावसायिक और तकनीकी कौशल को परिलाब्धि मानते हुए, टीम की उनकी योग्यताओं से ऊपर उठाकर उसे तैयार करना ही लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्तिगत विकास से टीम के क्षितिज का विस्तार, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। और तब उसका पुरस्कार यही है कि उसे व्यापार की दृष्टि से जोड़ दिया जाए और न केवल सभी अंशधारी सही दिशा में ही इशारा कर रहे होते हैं, बल्कि वे सामान्यतया मंच के सबसे ऊपर खड़े होते हैं। विकास के लिए टीम की उत्सुकता और उत्कठ को देखते हुए उन्हें सीखने के लिये मौका देना होगा, जिससे उनके साथ-साथ कंपनी को भी लाभ होगा। बीपीओ उद्योग में सुयोग्य पेशेवर लोग हैं, जिनके साथ वैसा ही बर्ताव किए जाने की आवश्यकता है। हमारा अनुभव है कि इसका लाभ यह होता है, अधिकांश लोग कंपनी छोड़कर नहीं जाते, और कंपनी में वास्तविक रूप से एक ऐसे समुदाय का निर्माण होता है जो काम करने में यकीन करता है। इसका और कोई सानी होना मुश्किल है।

प्रेरित करने की योग्यता और स्वयं प्रेरित होना, आगे बढ़ने का संकेत है। अपनी कमियों के बावजूद प्रेरित करिये। मुश्किल समय में उनका साथ दीजिये, क्योंकि जब कभी आप मुश्किल में हों तो वे आपके साथ रहें। टीम द्वारा दी गई मदद के लिये उसके आभारी बनिये, उनसे कुछ सीखिये, जैसा कि वे आपसे सीखते हैं, सफलता की खुशी मनाइये और असफलता में सबक लें। अपनी सहयोगियों का चयन बुद्धिमानी पूर्वक कीजिये और उनके विकास में उमगं से भाग लीजिए। विराट लोगों के कंधों पर खड़ा होना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन उनके आगे-आगे रहिये, दूर मुंडेर पर बैठकर हांकिये नहीं। क्योंकि तभी वही वादा करेंगे, जो आप कर सकेंगे, और वही करेंगे, जिसका वादा करेंगे।

मार्गदर्शकों को जब भी अवसर मिले टीम को कंपनी की दीवारों के बाहर की दुनिया के बारे में भी याद दिलाते रहना चाहिए। उनको अपना सामाजिक दायित्व भूलने मत दीजिए। यह सुनिश्चित करें कि वे कंपनी में और इसके बाहर भी अपना जीवन जी भर कर जियें। यह भी आपकी जिम्मेदारी है। उनके बच्चे इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे।

पारदर्शिता एक सराहनीय लक्ष्य है लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। पारदर्शी नेतृत्व तभी होता है जब आप लोगों की आवश्यकताओं और चिंताओं को पहला स्थान दें। इससे समूचा संगठन समृद्ध बनेगा। यह आदर्श हमेशा संभव नहीं होता, परंतु कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी संगठन के वे लोग जिनको पारदर्शी वातावरण से ज्यादा नुकसान होने का भय रहता है, संभवत: भीतरी आलोचक, पूछ सकते है कि कोई व्यक्ति खुला कैसे हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई सही उत्तर नहीं है। प्रत्येक संगठन अपने आप में अनूठा होता है, और मार्गदर्शकों को लोगों के नब्ज पर हाथ रखे रहना होगा। उन्हें सूचना को रोके रखने में उनकी परिपक्वता और क्षमता का निर्णय स्वयं करना होगा। कुल मिलाकर, उन्हें संगठन में पारिदर्शिता को बढ़ने देने के लिए अपनी सहजबुद्धि का पूरा उपयोग करना होगा।

पारदर्शी नेतृत्व एक दिन में नहीं तैयार होता। यह तभी हो सकता है जब संगठन के सभी सदस्य परस्पर व्यवहार में और ग्राहकों के साथ व्यवहार में भी इसे अपनायें। पारदर्शिता के निर्माण में एक युग लगता है। लेकिन इसकी शुरुआत संगठन के सबसे ऊपरी कदम से होनी चाहिए। एक बार बन जाने पर, यह संगठन की विरासत बन जाती है और आगे भी विरासत के तौर पर भावी नेतृत्व के प्रबंधन की ओर आगे बढ़ती रहती है। ❑

(लेखक वर्टेक्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी हैं)

आउटकम बजट क्या है?

आउटकम बजट में सभी सरकारी कार्यक्रमों के परिणामों का लेखा जोखा होता है। उदाहरण के तौर पर यह नागरिकों को बताएगा कि अगर किसी प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए धन आवंटित किया गया था तो क्या यह केंद्र सचमुच बनाया गया? अन्य शब्दों में यह सरकार द्वारा खर्च किए धन और बाद में आने वाले परिणामों के बीच संपर्क कायम करने का तरीका है। यह अवधारणा कई लोकतांत्रिक देशों में विकसित की गई है ताकि बजट को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार इससे प्रभावी सरकार, प्रबंधन और उत्तरदायित्व के एक महत्वपूर्ण साधन के विकास का संकेत मिलता है। इससे पहले भी शून्य आधारित बजट के जरिये सरकारी खर्च को परिणामों से संबद्ध करने के प्रयास किए जा चुके हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि परिणामोन्मुख बनाना इस उद्देश्य की प्राप्ति का बेहतर तरीका है। भारत में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस वित्त वर्ष से वह मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले व्यय के बारे में सूचना सार्वजनिक करेगी ताकि जन प्रतिनिधि, नागरिक, समाज और परियोजना के संभावित लाभार्थी इस बात का विश्लेषण कर सकें कि उक्त परियोजना कितनी कुशलता के साथ कार्यान्वित की गई है। इससे सरकारी खर्च की वास्तविक मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

यह सरकार के काम के तरीके को कैसे बदल सकेगा?

उम्मीद की जाती है कि इसके कारण सरकारी अधिकारियों की मानसिकता बदलेगी और वे परिव्यय केंद्रित होने की बजाय अधिक परिणामोन्मुख हो सकेंगे। अभी अधिकांश विभाग अपने कामकाज का मूल्यांकन बजट के आधार पर करते हैं, इस आधार पर नहीं कि इसके कारण जनता को कितना लाभ मिला। अधिकांश मंत्रालयों और विभागों ने नागरिक अधिकारपत्र विकसित कर लिए हैं इसलिए अब उनके लिए यह संभव होना चाहिए कि वे अपने आउटकम बजट के जरिये अपने नागरिक घोषणापत्रों में उपलब्धियों का उल्लेख कर सकें।

इस कवायद की समय तालिका क्या है?

इस वर्ष आउटकम बजट योजना स्कीमों पर लागू होगा क्योंकि निवेश कार्यक्रमों के लिए खर्च को परिणामों से जोड़ना आसान होगा। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि अगले साल से गैरयोजना व्यय के संभावित परिणामों का भी संकलन किया जाएगा। गैरयोजना व्यय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, रक्षा खर्च, सरकारी ऋणों पर ब्याज और सब्सिडी शामिल है। बहुत जल्द आउटकम बजट नियमित बजट प्रक्रिया का एक भाग बन जाएगा और इसे वार्षिक केंद्रीय बजट पेश करने के तीन महीने के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

इसका मतलब यह कि वित्त मंत्रालय को अपनी अनुदान मांगें प्रस्तावित करते समय हर मंत्रालय को अपना प्रारंभिक आउटकम बजट पेश करना होगा। एक प्रकार से यह खर्च के बाद उसकी जांच के स्थान पर खर्च से पहले उसकी पड़ताल करने जैसा है। उदाहरण के लिए 100 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी देने वाली व्यय वित्त समिति ने अपने नियम में संशोधन किया है और फैसला किया है कि वह किसी कार्यक्रम की योजना बनाते समय ही ठोस परिणामों को स्पष्ट करने की मांग करेगी। इस कवायद की जरूरत बताते समय वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष के अंत में हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि कितना खर्च हुआ बल्कि यह कि क्या परिणाम मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि परिव्यय को परिणामों में बदलना जटिल प्रक्रिया है और यह हर मंत्रालय और हर कार्यक्रम में भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मंत्रालय को इस कवायद को सफल बनाने की प्रतिबद्धता विकसित करना चाहिए।

इसके अलावा परिव्यय को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सही समय पर सही मात्रा में धन सही स्तर तक पहुंच सके। इस काम में न देर हो और न ही मिली रकम को संभाल कर रखने की जरूरत हो। साथ ही इसके लिए प्रभावी मानिटरिंग और मूल्यांकन व्यवस्था भी हो जो यह संकेत दे कि किन क्षेत्रों में अभी प्रणाली को और ठीक करने की जरूरत है ताकि वांछित परिणाम मिल सकें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संभावित लाभार्थियों के लक्ष्य समूह को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

परिणाम प्राप्ति पर कौन-सी एजेंसियां नजर रखेंगी?

यह वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का मिला-जुला काम है। आयोग प्रशासनिक मंत्रालयों से सलाह मशविरा करके उनके आउटकम बजट को अंतिम रूप दे रहा है। इस दस्तावेज को वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।

इस काम में तालमेल लाने के उद्देश्य से योजना आयोग में एक नया आउटकम एवं प्रत्युत्तर मानिटरिंग प्रभाग गठित किया गया है। यह प्रभाग सभी मंत्रालयों में एकरूपता लाने की कोशिश करेगा लेकिन साथ ही, उनके सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की विशेष प्रकृति का भी ध्यान रखेगा। इसका मतलब यह कि यह मालूम

भारतीय आईटी कंपनी को बड़ा ठेका

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस टेक्नोलाजी ने मिल कर डच बैंक एबीएन एमरो से 40 करोड़ डालर का एक बड़ा आउटसोर्सिंग ठेका प्राप्त किया है।

यह इन दोनों कंपनियों को मिलने वाला सबसे बड़ा ठेका है। यह बैंक द्वारा दिए गए 220 करोड़ डालर के ठेके का एक भाग है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा आईबीएम को मिला है। जो 180 करोड़ डालर का है।

टीसीएस का ठेका 26 करोड़ डालर है जो अब तक किसी भारतीय कंपनी को मिला सबसे बड़ा ठेका है। इन्फोसिस का ठेका 14 करोड़ का है जो उसे अब तक मिला सबसे बड़ा काम है।

टीसीएस और इन्फोसिस एमरो का एप्लीकेशन सपोर्ट और इनहैन्समेंट संभालेंगे जबकि आईबीएम इस बैंक की सूचना टेक्नोलाजी मूल सुविधाओं की देखरेख करेगा। ❑

करना अपेक्षाकृत आसान होगा कि क्या रक्षा मंत्रालय ने नयी हथियार प्रणाली की खरीद पर बजट खर्च कर दिया है, लेकिन यह जानना काफी मुश्किल होगा कि किसी ब्लाक में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च किए गए 100 करोड़ रुपये के परिणामस्वरूप कितने परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर आने में सहायता मिली। इसीलिए तय किए गए मापदंडों को लागू करते समय ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा।

परिणामों को परखने का मापदंड क्या होगा?

इस्तेमाल में लाए जाने वाले कुछ मापदंड होंगे- परिणाम प्राप्ति की यूनिट लागत का मानकीकरण, परिणामों की गुणवत्ता और मानकों का स्वीकार्य स्तर तय करना और उपकरणों, टेक्नोलॉजी, ज्ञान और दक्षता को देखते हुए हर स्तर पर आवश्यक कुशलता के लिए क्षमता निर्माण। तदनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को स्पष्ट मालूम रहेगा कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है और निष्पादन संकेतकों के आधार पर उनको परखा जा सकेगा। इससे उनको भी बेहतर और अधिक विकल्प मिल सकेंगे जिनके आधार पर धन का उपयोग करते हुए वे निर्धारित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ❑

(सौजन्य : इकोनामिक टाइम्स)

उत्कृष्ट परम्पराओं के 12 वर्ष

IAS/PCS

GENERAL STUDIES. ESSAY INTERVIEW
& PUBLIC ADMINISTRATION BY THE RENOWNED CONSULTANT

Mr. R.C. SINHA

NEW BATCHES START IN OCTOBER 05

• G.S. Essay
• Public Admin.

Contact Director: AIR CONDITIONED CLASSROOM

Centre for Excellence

8-B, Elgin Road, Opposite Mishra Bhawan,Civil Lines, Allahabad.

Note- Membership through Entrance Test only | Mob. 9415284868

YH/10/5/03

सूचना-सुरक्षा एवं अनुपालन

○ सुनील मेहता

देश में सूचना सुरक्षा चिंता का विषय है और आगे भी बना रहेगा।

विश्व व्यापार उत्तरोत्तर इलेक्ट्रानिक सूचना के आदान प्रदान पर निर्भर होता जा रहा है। इससे जहां जबरदस्त व्यापारिक सजगता आई है, सूचना के दुरुपयोग से जुड़े जोखिम भी काफी बढ़ गए हैं।

सूचना सुरक्षा और अनुपालन की रणनीति में इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संगठनों को पर्याप्त सुरक्षा और अनुपालन के लिए प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के बारे में निर्णय लेने के पूर्व प्रचालन जोखिम का भली-भांति आकलन कर लेना चाहिए।

भारतीय बीपीओ उद्योग - प्रारंभिक चुनौतियां

भारतीय बीपीओ उद्योग ने बड़ी तेजी से तरक्की की है। यह एक दशक से भी कम समय में 5 अरब 10 करोड़ अमरीकी डालर का उद्योग बन गया है। वर्ष 2004-2005 में सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के निर्यात का करीब एक तिहाई भाग इसी के खाते में जाता है। इस प्रगति का प्रमुख कारण भारत और अन्य देशों में लागत का अंतर है। मेरा विश्वास है कि यह उद्योग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां उसे अपनी व्यापारिक सोच में बदलाव की आवश्यकता है। यह नवजात उद्योग जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, ग्राहकों की अपेक्षाओं और उपलब्धि तथा गुणवत्ता के आयामों के कारण इसे उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

- ग्राहक अब लागत में अंतर के पहले निष्पादन के अंतर की ओर बढ़ रहे है। बीपीओ के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह मात्र सहयोगी की अवस्था से ऊपर उठकर निष्पादन में भागीदारी की भूमिका निभाए। इसके लिए आगे होकर सक्रिय रूप से ग्राहक से संवाद स्थापित करना होगा।
- एसएलए प्राप्त करने का अर्थ है ग्राहक (मुवक्किल का ग्राहक)की प्रसन्नता सुनिश्चित करने से पीछे हटना। इसके लिए आवश्यक है कि केवल एसएलए का लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देने की बजाय ग्राहक के संतोष पर ध्यान दिया जाए।
- उद्योग में बड़ी तेजी से लोगों को काम पर रखा जा रहा है और इसमें ह्रास दिखने लगा है। कर्मचारियों की लगातार रगड़ाई की अपनी अलग चुनौतियां हैं।
- कम लागत पर कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के कारण यह उद्योग अब द्वितीय श्रेणी के नगरों तक पहुंच गया है। हालांकि बैंडविड्थ की उपलब्धता के कारण यह उद्योग कहां लगा है, यह एक गौण बात हो जाएगी, लेकिन भौगोलिक विस्तार इस उद्योग के प्रचालन में अपनी अलग समस्याएं और सुरक्षात्मक चुनौतियां ला खड़ा करेगा।
- सुरक्षा के बारे में ग्राहकों की चिंताएं बढ़ रही हैं तो ग्राहक देशों के नियामकों की जांच भी बढ़ रही है। इसलिए अनुपालन की लागत भी बढ़ेगी।

सुरक्षा और नियामक आवश्यकतायें

सूचना सुरक्षा हमारे देश में बीपीओ उद्योग के लिए चिंता का विषय रही है, और आगे भी रहेगी। बीपीओ अब अपने ग्राहकों संस्थानों के विस्तार बनते जा रहे है। इसलिए ग्राहकों के साथ होने वाले संविदा करारो में ग्राहक संबंधी सूचना के संरक्षण को दर्शाने वाली धाराएं बढ़ गई है। इन धाराओं में नेटवर्क, कर्मचारी, भौतिक और सूचना सुरक्षा शामिल होते ही हैं। यह एक अप्राप्य लक्ष्य है, क्योंकि नियामक इसके मानक सतत ऊंचा करते रहते है। एक प्रतीकात्मक बीपीओ में इसलिए विभिन्न वैधानिक अनिवार्यताओं यथा - हेल्थ इंश्योरेंस, पोर्टेबिलिटी एंड एकाउंटेबिलिटी एक्ट, ग्राहम लीच ब्लाइची एक्ट और राइट टू फायनेंशियल प्रायवेसी एक्ट, सर्वनीस आक्ले एक्ट, कंप्यूटर फ्रांड एंड एब्युज एक्ट, अमरीकी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रानिक कम्यूनिकेशंस प्राइवेसी एक्ट और यूनाईटेड किंगडम और अन्य अनेक देशों के लिए डाटा प्रोटेक्सन एक्ट तथा रेग्युलेशन आफ इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट का अनुपालन करना होगा।

अपने परिसर को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

- नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, ताकि उसे हैकिंग/ नकल और पहचान तथा सूचना की चोरी के अन्य तरीकों से बचाया जा सके।
- सूचना, सुरक्षा और ग्राहक की गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी।
- अपने परिसर की चौबीसों घंटों सुरक्षा करनी होगी।
- नुकसान की भरपाई और व्यापार की निरंतरता के लिए प्रबंध करना होगा।

बढ़ती चुनौतियां

जब विश्व स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी हासिल करने का प्रश्न हो चाहे वह आंकड़ों की सुरक्षा हो या भौतिक सुरक्षा, तो बीपीओ ने सदा पथ प्रदर्शक का काम किया है।

- आगंतुकों के आवागमन लिए अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणाली, जैव सांख्यकी, आमंत्रित विशेषज्ञों की सुरक्षा के लिए बाहरी

A. Tiwari's निष्ठा

सिविल सेवा परीक्षाओं (IAS/PCS) की तैयारी हेतु एक उत्कृष्ट संस्थान

U.P.S.C. 2004 में सफल अभ्यर्थी

अभिषेक 147वीं रैंक

निष्ठा तिवारी 219वीं रैंक

अंजू लता

U.P.P.C.S. 2003 में सफल

हरिराम वर्मा

U.P.P.C.S. 2003 में सफल

नामांकन प्रारम्भ

तृतीय सत्र — 06 अक्टूबर, 05

चतुर्थ सत्र — 10 दिसम्बर, 05

U.P.C.S. में सफल

लोवर सबआर्डिनेट 2002 में सफल

अनुराग मिश्रा T.T.O.-I | शान्ता तिवारी A.C.O.-I Rank | धर्मेन्द्र कुमार U.P.P.C.S.-2003 | सुरेश कु. यादव | भीम यादव | सुनील कुमार | अनुराग बरौलिया | छत्रसाल बरनवाल टॉपर L.E.O. | अनिरूद्ध द्विवेदी ऑडिटर | संजय कुमार चौरसिया मार्केटिंग इन्स्पेक्टर

दर्शनशास्त्र

प्रारंभिक परीक्षा / अविनाश तिवारी

- एक दशक से अधिक का सफल एवं लोकप्रिय अधयापन अनुभव।
- तर्कशास्त्र की मानक पुस्तकों के लेखक-तर्कशास्त्र के सि)ान्त, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र एक अधययन।
- पाठ्यक्रम के तीनों भागों - दर्शन की समस्याएँ, तर्कशास्त्र तथा नीतिशास्त्र पर समान बल।
- तीनों भागों का परिष्कृत एवं परिमार्जित अधययन सामग्री वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सहित।

मुख्य परीक्षा / प्रो० द्विवेदी एवं अन्य

- भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ समूह द्वारा।
- दर्शनशास्त्र की ख्यातिलब्धा पुस्तकों के लेखक
- तीन माह का गहन अधयापन पाठ्यक्रमानुसार।
- विषय का विशद्, समग्र तथा विश्लेषणात्मक अधयापन के साथ परिष्कृत एवं परिमार्जित अधययन सामग्री।

सामान्य अध्ययन

(इलाहाबाद की सर्वश्रेष्ठ टीम)

भारतीय अर्थव्यवस्था	अरूणेश सिंह (लेखक)	भूगोल	सिद्धार्थ कुमार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पी.सी. मिश्रा	सांख्यिकी एवं मानसिक योग्यता	असीम मुखर्जी
भारतीय राजव्यवस्था	पी. सी. मिश्रा	इतिहास	नरेन्द्र मिश्रा

भारतीय इतिहास
नरेन्द्र मिश्रा

हिन्दी साहित्य - डॉ० आनन्द रवि

दर्शनशास्त्र

पत्राचार नोट्स भी उपलब्ध

प्रारंभिक परीक्षा-2000/- मुख्य परीक्षा- 2500/-

दर्शनशास्त्र के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उच्चस्तरीय अध्ययन सामग्री का संकलन किया गया है। इस अध्ययन सामग्री में आप विषय सम्बन्धी सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपके समय, ऊर्जा और संसाधन की बचत होगी।

सम्पर्क सूत्र : (0532) 2611212, 2467642
: 9415638449, 9415308157

1183, इस्लाम कॉम्पलेक्स, मनमोहन पार्क, पुराना कटरा, इलाहाबाद-211002

YH/10/5/14

2010 तक लगभग 35,000 अमरीकी कानूनी कार्य बाहर से कराए जाएंगे

ऐसा लगता है कि अगले दौर में विधिक सेवायें बाहरी देशों से कराने पर अमरीका का जोर रहेगा। 2010 तक करीब 35,000 काम अमरीका द्वारा भारत जैसे देशों से कराए जाने की संभावना है। नैसकॉम ने जुलाई 2005 में किए गए एक अध्ययन में कहा कि बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतरराष्ट्रीय कानूनी फर्मों, प्रकाशनों गृहों और विधिक अनुसंधान फर्मों ने विशिष्ट कानूनी कार्य भारत से कराने शुरू कर दिए हैं। अभी तक क्रेडिट कार्ड और आनलाइन तकनीकी समर्थन ही के काम भारत से कराए जा रहे थे लेकिन अब यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ❑

एजेंसियों की सेवाएं लेना, एक ही बिंदु से सेवाओं की आपूर्ति/अनापूर्ति से उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। कार्यस्थल को स्मरण यंत्रों जैसे- मोबाइल फोन, भंडारण क्षमता विहीन सूक्ष्म टर्मिनल, यहां तक कि कागज से भी परे रखकर सुरक्षित रखा जाता है।

- आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों, यथा-बीएस 7799, आईएसओ 17799 और सीओबीआईटी एवं आई टीएसएन के तदनुरूप तैयार कर प्रभावित करना, और समय-समय पर प्रचालन की आंतरिक एवं बाह्य समीक्षा की जाती है।
- ग्राहक की सूचना से संबंधित 'क्या करे और क्या न करे' के बारे में कर्मिकों के प्रशिक्षण में निवेश करना।
- काम पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के रोजगार, शिक्षा और यदि कोई आपराधिक रिकार्ड हो, तो उसकी पूरी पृष्ठभूमि का पता लगाना।
- कार्य परिसर में विक्रेता वेंडर की गतिविधि पर यथोचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कठोर विक्रय नीतियां अपनाना।
- बीपीओ कंपनियां प्रक्रियाओं की विधियों और सामग्री और उन का उपयोग करने वाले लोगों का निर्धारण करने के लिए ऐसी गोपनीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती हैं जिससे वे ग्राहक की प्रणाली की केवल उतनी ही जानकारी प्राप्त कर सकें, जितनी उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार आवश्यक हो।

चुनौतियां

सुरक्षा के इन कठोर उपायों के बावजूद अनेक चुनौतियां बरकरार हैं:

जन चुनौतियां

ह्रास - सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा (आईटीईएस)उद्योग द्वारा अनुभव किया जा रहा है। ह्रास संबंधी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। लगभग 30-40 प्रतिशत तक ये पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि हर दो साल के बाद नए कर्मचारी रखना। बीपीओ कंपनियों को न केवल नये कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, बल्कि तेजी से बढ़ रहे जनशक्ति केंद्रित इस उद्योग में उन्हें हमेशा ही गलत व्यक्तियों को काम पर लेने का डर बना रहता है। अच्छे कर्मचारियों की भर्ती की समस्या के हल के नासकाम, कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने पर काम कर रहा है, जिसे भावी नियोक्ता किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के पहले देख कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

औसत कर्मचारी परिपक्वता

अधिकांश बीपीओ/कालसेंटर के कर्मचारी बीस-बाईस वर्ष के आस-पास होते है और बहुधा यह उनका पहला कार्य होता है। अपने जीवन में वे तब उस दौर में होते हैं जब वे चीजों का संग्रह करना चाहते हैं। तनाव देने वाले कार्य की प्रकृति और ऊपर से दबाव के कारण, उनमें लोभ में पड़ने और कभी-कभी अपनी विवेक बुद्धि से भटक जाने की संभावना बनी रहती है।

उनमें सामाजिक दायित्व की भावना भरना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रणाली को धता बता कर शीघ्र धन कमाने की उनकी इच्छा, सभी कंपनियों के लिए एक चुनौती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

कानूनी चुनौतियां

आंकड़ा-सुरक्षा संबंधी भारत के कानून

लगभग एक दशक से आईटीऔर आईटीएस भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य वाहक रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सूचना और आंकड़ों की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर तुरंत ध्यान दे और कानून बना कर उपाय करे। इस उद्योग का विकास इस बात पर निर्भर है कि हमारे ग्राहक हमारी वैधानिक व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। अमरीका और इंगलैंड के नियम कानूनों के हम कितना भी पालन न कर ले हमारे ग्राहकों को वह संतोष नहीं प्रदान करेगा। उन्हें तो भारत में सूचना सुरक्षा के बारे में व्यापक वही कानून संतुष्ट करेगा। जो ग्राहक देशों की कानूनी आवश्यकताओं का ध्यान रख कर बनाया गया होगा। आखिरकार, बीपीओ तो भारत में स्थित होता है, और अंतिम ग्राहक को यह भी पता नहीं होता कि उसकी सेवा पृथ्वी के दूसरे छोर से हो रही है।

सारांश

सूचना सूरक्षा एवं अनुपालन, आईटीआईएस उद्योग के लिए हमेशा एक प्रमुख विषय बना रहेगा। कंपनियों को चाहिए कि वे प्रचालन के खतरों का पता लगाएं और उनसे निबटने के लिए अपनी कार्ययोजना तैयार करें। प्राविजनिंग जैसी प्रौद्योगिकी उन खतरों को कम करने में मदद कर सकती है। सफलता या असलफता इस बात पर निर्भर करती है कि बीपीओ कंपनियां, नैसकॉम और भारत सरकार किस प्रकार उपभोक्ता के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं और धोखाधड़ी रोकते हैं। ❑

(लेखक नैसकॉम के उपाध्यक्ष हैं)

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास
रजनीश राज

कौशलेंद्र कुमार
118th Rank, UPSC-2004

राकेश यादव
18th Rank, UPPSC-2004

रमेश चंद त्रिपाठी
उत्तरांचल PCS

मनोज तिवारी
IPS-2003

आलोक जायसवाल
DY.SP.UP-2004

अशोक कुमार
भारतीय डाक सेवा 2004

कार्यक्रम

इतिहास फाउंडेशन कोर्स 2006 के लिए

- 500 घंटे का क्लॉसरूम प्रशिक्षण
- साप्ताहिक टेस्ट
- मेंस के लिए मॉडल उत्तर लेखन व आकस्मिक टेस्ट पर बल
- पूर्णतः संशोधित अध्ययन सामग्री
- 4 उत्तर लेखन की संरचना पर सर्वाधिक बल
- मैप और लघुउत्तरीय प्रश्नों पर विशेष बल

इतिहास का नया बैच आरम्भ : 25 सितम्बर 2005
प्रवेश आरम्भ : 4 सितम्बर 2005

SIHANTA IAS

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302,
Ansal Building, Comm. Complex,
(Near Chawla Restarurant),
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph. : 9873399588, 9871423426

न्यूनतम मजदूरी को अलंघ्य माना जाना चाहिए

○ सिद्धार्थ वरदराजन

वैधानिक मजदूरी की न्यूनतम से कम दर पर रोजगार की गारंटी – जैसा कि रोजगार गारंटी अधिनियम में व्यवस्था है, मोटे तौर पर कानून के उद्देश्य को प्रभावित करेगा और एक बुरा उदाहरण बनेगा

अब जब कि संसद से रोजगार गारंटी अधिनियम पास हो गया है जो ग्रामीण भारत का कायापलट कर सकता है, लेकिन ऐसा करके संसद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के महत्व को खतरे में डाल रहा है। यह ऐसा कानून है जिसकी भूमिका असंगठित मजदूरों के सशक्तीकरण में कम सराहनीय नहीं है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने, जिसने रोजगार गारंटी अधिनियम की परिकल्पना की थी, कहा था कि मजदूरों को किसी भी हालत में राज्य में लागू खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। विधेयक अब जिस रूप में पेश किया गया है उसमें कहा गया कि 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निहित किसी भी व्यवस्था के बावजूद जो लोग रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम कर रहे होंगे उन्हें 60 रुपये मजदूरी दी जाएगी। यह कुछ स्पष्ट नहीं किया गया कि मजदूरी इस दर पर क्यों निर्धारित की जा रही है। न ही स्वत: सूचीकरण का कोई कारण बताया गया। सरकारी मसौदाकारों को संदेह का लाभ देने के लिए यह सवाल कि क्या मजदूरी दर देय है, बहुत जटिल है। पहले तो यह कि देश के राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में बहुत भिन्नता है। जहां केरल में यह दर 126 रुपये है वहीं मेघालय में यह सिर्फ 26 है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे अनेक उन राज्यों में जहां बहुत बड़ी संख्या में गरीब रहते हैं, न्यूनतम मजदूरी दर 60 रुपये से कम है। राजस्थान जैसे कुछ अन्य राज्यों में यह दर थोड़ी-सी ज्यादा है।

दूसरी बात है राजकोषीय सौदेबाजी की शर्तों के अंतर्गत रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए निधियों की व्यवस्था। मजदूरी का सारा खर्च केंद्र वहन करेगा, राज्यों को तो केवल निर्माण सामग्री की लागत के 25 प्रतिशत की व्यवस्था करनी है। इस कारण से हो सकता है कि केंद्र इस बात को देखते हुए कि राज्यों की न्यूनतम मजदूरी की राशि बेकार ही बढ़ रही है, अपना बोझ कम करने के उद्देश्य से मजदूरी की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दे। तीसरे, इस स्कीम की कुल लागत मजदूरी दर से इतनी अधिक जुड़ी है कि केंद्र कम दर पर मजदूरी दर तय कर सकता है ताकि वह अपनी राजकोषीय वचनबद्धता न्यूनतम स्तर पर रख सके।

हालांकि ये वित्तोन्मुख तर्क आकर्षक लग सकते हैं लेकिन अनेक विधायी, राजनीतिक और आर्थिक ठोस कारण हो सकते हैं जिनके कारण राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मसौदे की ओर फिर से लौटा जा सकता है कि रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को उस राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दिया जाएगा।

कानूनी रूप से देखा जाए तो इसमें किसी भी दुविधा की गुंजाइश नहीं है। सत्यजीत राय बनाम राजस्थान राज्य (1983 एस सी सी (i) 525) में उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया था कि कानूनी न्यूनतम से कम दर पर मजदूरी देने से, भले ही ऐसा सूखे के दिनों किया गया हो, संविधान की धारा 23 में दी गई बेगार पाबंदी का उल्लंघन हुआ है। इस बात को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी देने का उल्लंघन करने वाला कोई कानून अमान्य हो जाता है। जब भी राज्य द्वारा किसी व्यक्ति से कोई काम करवाया जाए या सेवा ली जाए, चाहे वह व्यक्ति सूखा या अभाव से ग्रस्त हो या नहीं, राज्य को उस व्यक्ति को धारा 23 के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी देनी ही पड़ेगी। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और आर.एस. पाठक ने यह फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य को किसी व्यक्ति को असहाय स्थिति से फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न्यूनतम से कम मजदूरी देकर श्रम या सेवा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीशों ने पहले के एक फैसले का हवाला दिया (पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स तथा अन्य बनाम भारतीय संघ तथा अन्य-982) जिसमें उच्चतम न्यायालय ने बेगार शब्द की व्याख्या करके 'भूख, गरीबी और कंगाली के कारण मजबूरी' को शामिल किया था। स्पष्ट है किसी ऐसे राज्य में जहां न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये से अधिक है, किसी गरीब स्त्री या पुरुष को रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम पर लगाना बेगार माना जाएगा और इससे संविधान की धारा 23 का उल्लंघन होगा। जहां आर्थिक और राजनैतिक कारणों का प्रश्न है, इस दृष्टि से भी न्यूनतम मजदूरी की अनदेखी करना ठीक नहीं होगा। इसका ग्रामीण गरीबों और असंगठित मजदूरों पर बुरा असर पड़ेगा।

किसानों को मुफ्त पानी या बिजली देने जैसे लोक-लुभावन वादों की तरह न्यूनतम मजदूरी कोई लालच या रियायत नहीं है। किसी

श्रमिक के लिए खुद अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए यह आवश्यक माना गया है। 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन में पारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी 'आवश्यकता-आधारित' है और आवश्यकताओं को न्यूनतम कैलोरी भोजन, कपड़े आदि की जरूरत के मुताबिक परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने बाद में इसे और स्पष्ट कर दिया। (रेप्कोस ब्रेट के श्रमिक बनाम प्रबंधन, 1992) इसमें जोड़ा गया कि बच्चों की शिक्षा, इलाज की जरूरतें और बुढ़ापे के लिए बचत का भी ध्यान रखा जाए। यह अलग बात है कि किसी भी राज्य सरकार ने सचमुच 'आवश्यकता-आधारित' न्यूनतम मजदूरी तय करने की कोशिश नहीं की, इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि उन्होंने कानूनन मजबूरी में न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दर को लागू करने की भी कोशिश नहीं की।

गरीब लोगों को रोजगार गारंटी अधिनियम की जरूरत इसलिए ही नहीं है कि उनके पास उपयुक्त काम नहीं है बल्कि इसलिए भी कि इस समय वह जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। भारत का हर गरीब आदमी कई तरह से कड़ी मेहनत करता है लेकिन ऐसी कोई प्रशासनिक अथवा कानूनी व्यवस्था नहीं है जो उसे उसका जायज हक दिला सके। यही कारण है कि में बच्चों में हद दरजे का कुपोषण और बर्बादी देखने को मिलती है। प्रशासन की सहायता से चलाई जाने वाली रोजगार गारंटी अधिनियम योजना का मुख्य आकर्षण इस बात में होगा कि इसके जरिए ऐसे कानूनी तौर पर लागू किए जा सकने वाले मापदंड विकसित किए जाएंगे जिन्हें एक 'क्रांतिकारी पैकेज' में इकट्ठा किया जा सकेगा और जिसको लागू करके खाद्य असुरक्षा समाप्त की जा सकेगी, गांवों का सशक्तीकरण संभव हो सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिसंपत्ति पैदा की जा सकेगी। अन्य शब्दों में एक समुचित संरचना वाले रोजगार गारंटी अधिनियम से सिर्फ प्रत्यक्ष लाभार्थियों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सकारात्मक बल मिल सकेगा। साथ ही राज्यों को इस बात की सहायता भी मिल सकेगी कि वे अपने सभी असंगठित श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दिला सकेंगे।

लेकिन एक ऐसी रोजगार गारंटी योजना लाकर, जो न्यूनतम मजदूरी संरक्षण को कमजोर बनाती हो, सरकार असंगठित श्रमिकों की मजदूरी पर हमले का मार्ग प्रशस्त करेगी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के देशभर में कार्यान्वयन को और मुश्किल बना देगी।

अब जब कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग सरकार ने अपने नागरिकों के बाइज्जत जीवन बिताने के अधिकार को मान लिया है, उसे अंतिम क्षणों में उत्साह नहीं खोना चाहिए। क्रांति आधे अधूरे उपायों से नहीं आती। अगर भारत के गरीबों के लिए एक नए भविष्य का निर्माण किया जाना है तो जहां रोजगार का आश्वासन मिल रहा है, वहीं कानूनी तौर पर न्यूनतम मजदूरी को भी लागू किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए इन दोनों उद्देश्यों में किसी प्रकार की विसंगति न आने पाए एक तरीका यह हो सकता है कि 60 रुपये की दर को केंद्र वित्त-पोषित आधारभूत मजदूरी माना जाए और राज्य 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार अपने दायित्व को देखते हुए इसमें और वृद्धि करें। ❑

(सौजन्य : दी हिंदू)

विश्वसनीयता का प्रतीक,सफलता का पर्याय

Sanjeev Kr. Sharma,s

IAS ERA

ऐसा संस्थान, जो आपके सपने को बनाता है- एक सच।

14 महीने के Foundation Course में PT एवं Main परीक्षा की सम्पूर्ण तैयारी

आप मुझे दें अपने 14 महीने, प्रतिदिन 5 घंटा संस्थान में अध्ययन और 5 घंटा स्वअध्ययन,मैं दुंगा विषयों का सरल,बोधगम्य,वैज्ञानिक समझ,उत्कृष्ठ नोट्स और अन्तिम सफलता

New Batches (Oct.- Nov)

PT, MAIN, PT Cum MAIN for G.S,Geography, Hist. P.A.,Sociology,Law & LSW

भूगोल

PT में 100% सफलता,MAIN में 60से70% अंक की सुनिश्चितता

by संजीव कुमार शर्मा

Author & Expert

समान्य अध्ययन (प्रार० एवं मुख्य) :- संजीव कुमार शर्मा एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा

BPSC 43rd,44th,45th में संस्थान के सफल छात्र

1. कैलाश प्रसाद (Dy.SP) 2. सुभाष नारायण (डिप्टी कलेक्टर) 3. जनक कुमार (डिप्टी कलेक्टर) 4. विनोद कुमार "विमल" (बिहार शिक्षा सेवा) 5. नीलकमल (बिहार लेखा सेवा) एवं अन्य कई छात्र

नोटः- उपरोक्त सभी छात्रों का एक वैकल्पिक विषय भूगोल रहा है।

संजीव सर के मार्गदर्शन में मैंने भूगोल, समान्य अध्ययन एवं साक्षात्कार की तैयारी किया, जिसके फलस्वरुप बिहार पुलिस सेवा में मैं चयनित हो सका।

कैलाश प्रसाद (Dy.SP)

Special Features

Recent Data का प्रयोग एवं UPSC/ BPSC की नवीन प्रवृतियों पर आधारित अध्ययन

Test Series, Class Lecture,Class Notes

Factual, Conceptual & Analytical Study

◎वाद-विवाद के द्वारा निबंध की साथ-साथ तैयारी ◎ पत्राचार की व्यवस्था

CDPO Special Batch for All Subjects

गंगोत्री कॉम्पलेक्स,(तीसरा तल्ला), हाईकोट मोड़ एवं बोरिंग रोड चौराहा के मध्य, पटना-1

Mob.: 9835227489 Admission Open

YH/10/5/20

जम्मू-कश्मीर : पर्यटन उद्योग

पर्यटन से संबंधित गतिविधियों की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विशेषता आय, रोजगार और विदेशी मुद्रा के सृजन में उनके योगदान में पाई जाती है।

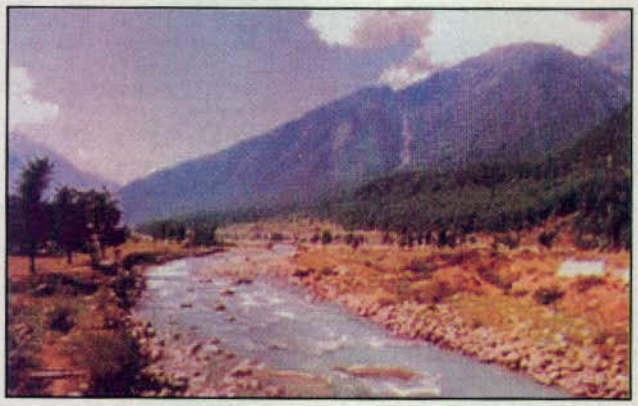

पर्यटन उद्योग में राजस्व और पूंजी का अनुपात काफी ऊंचा होता है। रोजगार और निवेश का अनुपात तो सबसे अधिक की श्रेणी में माना जाता है। जम्मू-कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य ने सभी पर्यटकों का मन मोहा है और उनकी प्रशंसा हासिल की है। कश्मीर को पूरब का स्विटजरलैंड भी कहा जाता है। जम्मू-कश्मीर मुख्यत: तीन क्षेत्रों में बंटा हुआ है : जम्मू के मैदानी इलाके, कश्मीर की झीलें और नीली घाटियां और लद्दाख के ऊंचाई वाले मैदान और पहाड़।

राज्य विभिन्न वर्गों के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा है। अनेकों आकर्षक केंद्र है यहां, इनमें से प्रमुख हैं:

श्रीनगर : राज्य की राजधानी है और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहां के प्रमुख पर्यटक स्थलों में डल झील, निशात बाग, शालीमार बाग और चश्मेशाही ही शामिल हैं।

जम्मू : राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू का स्थान श्रीनगर के बाद दूसरे क्रम पर है। ज्यादातर सैलानी जो जम्मू आते हैं, वे माता वैष्णों देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। इसकी गिनती देश के सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में होती है।

लेह और लद्दाख : राज्य के अल्पसंख्यक बौद्ध संप्रदाय के लोगों का घर है लद्दाख। यहां के प्रमुख आकर्षण हैं- लेह प्रासाद, नामग्याल, त्सेमो गोम्पा, संकर गोम्पा, शांति स्तूप और सोमा गोम्पा।

मंदिर : रघुनाथ मंदिर समूचे उत्तर भारत में भगवान राम का सबसे विशाल मंदिर है। इसके अलावा बहू किले स्थित महाकाली का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में गौरीकुंड मंदिर, शुद्ध महादेव मंदिर, शिव मंदिर, पीरखोह गुफा मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर और परमंडल मंदिर परिसर सम्मिलित हैं। अप्रतिम सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों में सोनमर्ग, अखनूर, पहलगाम, गुलमर्ग, जहस्कार घाटी और अन्य अनेक स्थान हैं।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन सबसे पुराना और सबसे सफल उद्योग रहा है, परंतु 14 वर्षों के सशस्त्र उपद्रव में सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी का हुआ है। तथापि हाल के वर्षों में सरकार ने राज्य में इस उद्योग को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास किए हैं - पर्यटन संरचना को उन्नत बनाया गया है और लोगों के मन से भय की भावना हटाकर आतंकवाद की समस्या से निपटने के प्रयास भी किए गए हैं। घुसपैठ की दर में कमी और प्रभावी आतंकवाद विरोधी अभियान के फलस्वरूप आतंकवाद से संबंधित घटनाएं जो 2003 में 3400 के लगभग थी, 2004 में घटकर 2500 तक रह गई थी। स्थिति में सुधार का नतीजा यह हुआ है कि राज्य में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। आने वाले 3 लाख 76 हजार पर्यटकों में से 18 हजार 500 विदेशी पर्यटक थे।

राज्य के विभिन्न भागों में पर्यटन संरचना में सुधार और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक योजना कर उन पर क्रियान्वयन शुरू किया है। न केवल संरचना के स्तर पर बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार ने स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तियां सौंपी हैं। पर्यावरणीय प्रणाली के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी उपायों से भविष्य में काफी लाभ मिलने की आशा है। राज्य में विषयवस्तु आधारित पर्यटन परियोजनाओं में निवेश की संभावनाएं अब काफी उज्ज्वल दिखाई देने लगी हैं।

इस क्षेत्र की विपुल संभावनाओं को देखते हुए, जहां पर्यटन के विकास और प्रोत्साहनों में कमी करने की आवश्यकता है, वहीं यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस प्रगति से नागरिकों को लाभ मिले और वाणिज्यिक एवं पारिस्थितिकीय गतिविधियां सतत बढ़ती रहें। प्रकृति हितैषी प्रौद्योगिकियों और कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन नीतियों पर ध्यान देने से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य की पर्यावरणीय व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य भी बरकरार रहेगा ताकि राज्य में पर्यटन के विकास से इन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्थानीय लोगों को पर्याप्त लाभ मिलता रहे। स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने से राज्य के पर्यावरण हितैषी ढांचे में उनकी आमदनी के अवसरों में वृद्धि होगी, उनके कौशल में सुधार होगा, सामुदायिक विकास को गति मिलेगी और अति लघु योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता भी मिल सकेगी।

अतएव जब हम राज्य में पर्यटन क्षेत्र में

निवेश आकर्षित करने के मुख्य विषय की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि समूचे पर्यटन के संदर्भ में इसके टिकाऊपन की धारणा पर भी संक्षिप्त चर्चा करें। जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में विशेष विषयवस्तु केंद्रित पर्यटन के कुछ पहलुओं पर भी विचार करना उचित होगा।

संपोषणीय पर्यटन : संपोषणीय पर्यटन की परिभाषा इस प्रकार की गई है - पर्यटन और उससे संबंधित वर्तमान और भावी संरचना नैसर्गिक संसाधनों के पुनर्सृजन और भावी उत्पादकता की प्राकृतिक क्षमताओं के भीतर ही संचालित होती है : लोगों और समुदायों, रीति-रिवाजों तथा जीवनशैलियों द्वारा पर्यटन के अनुभव के लिए जो योगदान किया जाता है, उसको स्वीकार करना इन लोगों का पर्यटन के आर्थिक लाभों में समान हिस्सा होने के तथ्य को मानना, मेजबान क्षेत्र के लोगों और समुदायों की इच्छाओं से निर्देशित होते हैं। संपोषणीय पर्यटन के विचार को पर्यावरणीय पर्यटन समझ कर भ्रमित नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह है कि सभी पर्यटन गतिविधियां भरण-पोषण के योग्य होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि पर्यटन संरचना, और इसके अनुगामी संचालन तथा उसकी मार्केटिंग के नियोजन और विकास के लिए पारिस्थितिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उसके जीवन यापन की क्षमता पर ध्यान देना होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों के आगमन से मेजबान समुदायों के नैसर्गिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक ताने-बाने पर कोई आंच नहीं आए। इसके विपरीत पर्यटन से मेजबान समुदायों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभ मिलना चाहिए जीवन यापन के लिए सक्षम होने का अर्थ है कि उद्यम और समुदाय जिनमें वे काम करते हैं, दोनों को पर्यटन से कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए।

इसलिए हम संपोषणीय पर्यटन और पर्यावरणीय पर्यटन के विचार को साथ-साथ रख रहे हैं। वे एक जैसी नही है, परंतु निश्चित रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में। यह राज्य इसी पर्यटन क्षेत्र के विकास के जरिये ही अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिवान बनाना चाहता है। पर्याभ्रमण (पर्यटन) को परिभाषित करने के कई प्रयास किए गए हैं। मोटे तौर पर पर्यावरणीय पर्यटन वह भ्रमण है जो ऐसे प्राकृतिक वातावरण वाले क्षेत्रों में किया जाता है जहां परिस्थितियों से ज्यादा छेड़-छाड़ नहीं हुई हो। इसका मुख्य उद्देश्य तो परिस्थितियों को समझना, उनका अध्ययन करना और उनकी सराहना करना ही है। इस परिभाषा में यह निहित है कि जिस क्षेत्र का भ्रमण किया जाए वहां कम से कम अपनी निशानी छोड़ जाएं और उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए।

अंतरराष्ट्रीय पर्याभ्रमण सोसायटी (टीआईईएस) ने पर्याभ्रमण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह उन नैसर्गिक क्षेत्रों का भ्रमण है जो पर्यावरण को बचा कर रखते हैं और स्थानीय लोगों की भलाई को बढ़ावा देते हैं। इसका अर्थ है कि जो पर्याभ्रमण गतिविधियों को लागू करते हैं और उनमें भाग लेते हैं वे निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम करते हैं :-

- न्यूनतम आघात करना
- पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चेतना जगाना और सम्मान करना
- पर्यटको और मेजबान दोनो को सकारात्मक अनुभव प्रदान करना

विशाल स्वास्थ्य सैरगाह भी माना जाता है : लोगों ने इसे धरती पर स्वर्ग के रूप में भी सराहा है। फूलों का मौसम मार्च के मध्य से अप्रैल तक रहता है। मई और जून के महीनों में फलों के वृक्षों पर आए रंग-बिरंगे पुष्पों से सारे घास के मैदानों और पहाड़ियों की ढलानों पर मानो फूलों की कालीन-सी बिछ जाती है। राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, नि:सर्ग और वन्यजीवन के पर्याभ्रमण के लिए बढ़ावा देने के मामले में अत्यन्त उपयुक्त है। राज्य सरकार ने इस ओर कदम भी उठाए हैं। इस तरह का पर्यटन विशेष रुचि वाले समूहों को पसंद आता है। परंतु इसके लिए विशेष संरचना और उसमें निवेश की आवश्यकता है।

साहसिक पर्यटन

कश्मीर के सर्वाधिक आकर्षक पक्षों में इसकी साहसिक गतिविधियों की संभावनायें है, जिसमें पर्यटक पूरे वर्ष भाग ले सकते हैं। इनमें दुर्गम स्थानों की यात्रा, पूरे हिमालय क्षेत्र में जीप सफारी, पर्वतारोहण, मत्स्य खेट, बेडे पर यात्रा करना, हेली-स्कीइंग जैसे साहसिक और रोमांचक गतिविधियां शामिल हैं। तैराकी, सूर्य स्नान, सर्फ-राइडिंग और दुर्गम स्थानों की यात्रा गर्मियों में की जा सकती है जबकि अगस्त और सितंबर के महीने मत्स्याखेट के लिए उपयुक्त हैं। पतझड़ का मौसम दुर्गम स्थानों की यात्रा के लिए उपयुक्त माना जाता है जबकि दिसंबर से फरवरी का मौसम शीतकालीन खेलों के लिए उत्तम है।

स्थल इसे निसर्ग पर्यटन के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं, जबकि वर्ष भर की बाह्य गतिविधियां साहसिक पर्यटन के लिए अनुकूल हैं। पर्याभ्रमण के तहत ये दोनों खंड सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य इनका लाभ उठा सकता है। घरेलू पर्यटको के लिये पर्याभ्रमण का सबसे बड़ा प्रकार तीर्थाटन ही है। राज्य में बड़ी मात्रा में विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थानों और तीर्थों को देखते हुए राज्य इस मामले में भी लाभ की स्थिति में है।

जम्मू और कश्मीर में पर्याभ्रमण के विभिन्न पहलुओं की उपयुक्तता

प्रकृति, स्थानीय समुदाय और सांस्कृति और साहसिक गतिविधियों पर ध्यान दिये जाने से पर्याभ्रमण में पर्यटन से पारस्परिक व्यवहार की संभावना बनी हुई है। पर्याभ्रमण के सभी खंडों में से निम्नलिखित राज्य के लिए अधिक प्रासंगिक और उपयुक्त है:

निसर्ग पर्यटन : उन पर्यटकों के लिये जो गैर शहरी, प्रकृति की गोद में बसे नैसर्गिक वातावरण की तलाश में हैं, उनके लिए जम्मू और कश्मीर अप्रदूषित वातावरण, सुंदर झीलें, ऊंचे-ऊंचे पर्वत, झरने और वन्य जीवों से भरे वनों के रूप में अत्यन्त आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

राज्य प्रचुर वन और वनस्पति संपदा से परिपूर्ण है। कश्मीर घाटी, कायदे से एक

- संरक्षण के लिये प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करना
- स्थानीय लोगों को वित्तीय लाभ देना और

उन्हें समर्थ बनाना

- आतिथेय देश की राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक वातावरण की संवेदनशीलता का पूर्ण सम्मान देना
- अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों और श्रम समझौतों का समर्थन करना

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पर्याभ्रमण के लिये आवश्यक पांच आधारभूत सिद्धांत ये है:-

- इसकी मुख्य प्रेरणा है नैसर्गिक क्षेत्रों में प्रचलित पारम्परिक संस्कृतियों के साथ प्रकृति का अवलोकन और उनकी कद्र करना
- इसमें शैक्षिक और व्याख्यात्मक विशेषताएं समाहित है
- विशिष्ट और लघु स्थानीय स्वामित्व वाले व्यवसायों द्वारा छोटे-छोटे समूहों के लिए आयोजित होता है
- यह प्राकृतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम बनाता है
- यह (1) मेजबान समुदायों के लिए आय के साधन सृजित कर (2) वैकल्पिक रोजगार और आय के अवसर प्रदान कर (3) प्राकृतिक और सांस्कृतिक निधियों के संरक्षण की चेतना को बढ़ावा देकर - प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण का समर्थन करता है।

पर्याभ्रमण की विशेषताएं, इसे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास योजना पर लागू करने के लिए उपयुक्त मामला बनाती हैं। विशाल प्राकृतिक पर्यावरण के साथ-साथ बिखरी आबादी कश्मीर और लद्दाख के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए मई और सितंबर के महीने आदर्श हैं। साहसिक यात्रा विशेष रुचि वाले समूहों को भी आकर्षित करती है और यह अक्सर निसर्ग पर्यटन के साथ-साथ चलती है क्योंकि दोनों में ही शहरी क्षेत्रों से दूर भीड़भाड़ से परे दूर दराज के विरल स्थानों की यात्रा की जाती है। पर्यटन के इस रूप के उन्नयन और विकास के लिए राज्य में असीम संभावनाएं हैं। तथापि, परिवहन और यात्रा की सुविधाएं विकास के लिए अपरिहार्य है।

तीर्थाटन/धार्मिक पर्यटन : राज्य का भ्रमण करने वाले देशी पर्यटकों में से अधिकांश धार्मिक यात्री होते हैं। माता वैष्णों देवी की पवित्र गुफा मंदिर, देश के सबसे लोकप्रिय देवालयों में से एक है। अमरनाथ मंदिर, कश्मीर घाटी आने वाले अधिकतर यात्रियों को आकर्षित करता है। आठ अगस्त, 2004 तक कश्मीर घाटी की यात्रा करने वाले 2 लाख 57 हजार 192 लोगों में से 2 लाख 48 हजार 179 यात्रियों ने अमर नाथ की यात्रा की थी। रघुनाथ मंदिर उत्तर भारत में भगवान राम का सबसे बड़ा मंदिर है। बहू किले में महाकाली का मंदिर भी काफी लोकप्रिय है। गौरीकुंड मंदिर, शुद्ध महादेव मंदिर, शिव मंदिर, पीर खोह गुफा मंदिर रणबीरेश्वर मंदिर, परमंडल मंदिर और लद्दाख के बौद्ध मठ अन्य धार्मिक स्थान है जो पूरे देश से पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। राज्य में तीर्थ स्थानों की संख्या को देखते हुए धार्मिक पर्यटन से राज्य की आय में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

आंचलिक पर्यटन : जिन पर्यटकों को किसी स्थानीय प्रजाति अथवा समुदाय की परम्पराओं, विविध शिल्पों की परख होती है या उनकी विरासत को समझने सराहने की अभिलाषा होती है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंचलिक पर्यटन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ये किसी मेरे, ग्रामहाट अथवा स्थानीय कला और शिल्प का प्रदर्शन करने वाले किसी भी रूप मे आयोजित हो सकता है। कश्मीरी हस्तशिल्प अपनी खूबसूरत कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है जबकि श्रीनगर अपनी पारंपरिक शिल्प कला के लिए जाना जाता है। लद्दाख अपनी चित्रकारी, काष्ठ शिल्प और पशमीना बुनाई के लिए मशहूर है। यहां बनने वाली वस्तुओं में ऊनी कपड़े, हाथ की बुनी कालीने, पेपर मैशी से बने नक्काशीदार उत्पाद, लकड़ी का सामान, चांदी और तांबे के बने बर्तन तथा सजावटी सामान शामिल हैं। पर्यटन के इस खंड को बढ़ावा देने से न केवल स्थानीय लोगों मे गर्व का अहसास पैदा होगा, बल्कि इससे उनको रोजगार और आमदनी के अवसर भी मिलेंगे। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और संरचना के विस्तार के लिए पर्यटक ग्रामों की स्थापना के विषय में विचार कर रही है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य में पर्याभ्रमण के कुछ रूपों के विकास की अच्छी संभावनाएं है लेकिन एक चीज तो बार-बार इसके विकास को रोक रही है वह है पर्यटकों के स्वागत के लिए संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव। आलेख के अगले भाग में इसी पर चर्चा की गई है।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन की तैयारियों का विश्लेषण

जम्मू और कश्मीर को पर्याभ्रमण को इस तरह आगे बढ़ाना होगा जिससे वह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन सके और उन्हें जीवन यापन के दीर्घावाही अवसर मिलें। इसके अतिरिक्त सुरक्षा और विकास और उसके साथ-साथ इस तरह के धारणीय दीर्घावधि पर्यटन के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी क्षेत्र में धारणीय पर्याभ्रमण के उन्नयन के लिए आवश्यक संरचना इस प्रकार होगी:

प्रशासकीय संरचना आधार तंत्र: इसके अंतर्गत पर्यटन सुविधाओं के संचालन से संबंधित संगठनात्मक ढांचे से जुड़े मुद्दे आते हैं। इसमें सरकार के प्रशासकीय विभागों, विदेशी संस्थाओं और अन्य संबंधित लोगों से संपर्क रखना होता है।

भौतिक संरचना : भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे, भूतल, रेल और वायु परिवहन, होटल, बार और रेस्तरां आदि के अलावा पर्यटन संचालन के लिए ईंट गारे के बने भवन, कार्यालय, सार्वजनिक सुविधाये, मंजिल और भौतिक संचार की संरचना इस श्रेणी में आते हैं।

तकनीकी संरचना : पर्यटन कार्यक्रम बनाए जाने से जुड़ा है। पैकेज भ्रमण से संबंधित विचार और रणनीति की रूपरेखा तैयार करना, अपने उत्पाद (सेवाएं) प्रस्ताव, विपणन रणनीति और ई.वाणिज्य के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इसी के तहत शामिल है। परंतु इन सबके ऊपर है, प्रशासकीय, भौतिक और तकनीकी संरचनाओं का एकीकरण, उनका समन्वयन।

STUDY CIRCLE

Career Development Institute

Here your Dream comes true.....

IAS G.S.

हिंदी माध्यम
सामान्य अध्ययन
Alok Kumar & Team

Prelims
Mains
Foundation

Compulsory English For IAS/PCS
One month Exclusive Program by Madhumita Mishra & Surjan Singh

IAS G.S.

English Medium General Studies by Dr.Anand Patil (Director)

Gyanendra Singh Yadav
Rahul & Team

Prelims
Mains
Foundation

History
By
Alok Kumar
हिंदी माध्यम
Pre-cum-Mains

Public Administration
By
Vishal Mishra
हिंदी माध्यम
Pre-cum-Mains

Admissions open-15th oct.2005

867,1st floor, opp Batra Cinema ,Main Road
Dr.Mukherjee Nagar ,Delhi-9,Ph.27601013,9350940365

YH/10/5/11

राज्य में पर्यटन की तत्परता के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आनंदमय पर्यटक अनुभव के लिए आवश्यक समस्त पर्यटन संरचनाओं पर समग्र रूप से नजर डालना होगा। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन की तत्परता और उपलब्धता के बारे में एक सांकेतिक सिंहावलोकन सारणी में दिया गया है। सारणी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) की विशेष विकास परियोजनाओं के जरिये समूचे क्षेत्र की आधार तंत्र से समस्याओं के निराकरण की सिफारिशें भी दी गई हैं:-

मुद्दे और सिफारिशें : राज्य में पर्यटन के एकीकृत विकास के लिए उपयुक्त सारणी पर आधारित मुख्य मुद्दे और सांकेतिक रणनीति की जानकारी दी जा रही है। सरकार राजकोषीय प्रोत्साहनों और सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिये इसमें, विशेषकर प्रारम्भिक वर्षों में, उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगी। इस प्रक्रिया में बैंक और वित्तीय संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

देशी और विदेशी पर्यटकों तक सूचना पहुंचाना : जम्मू और कश्मीर सरकार ने इंटरनेट के जरिये देशी और विदेशी पर्यटकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय और सराहनीय प्रयास किए हैं। तथापि राज्य के जिलों और सर्किटों की जोरदार मार्केटिंग की जरूरत है।

परियोजना क्र. 1 : राज्य के भीतर सर्किलों की इंटरनेट मार्केटिंग

हमें विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर के लिए अपने प्रचार-प्रसार उन्नयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जनित सेवाओं का उपयोग कर इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटकों तक पहुंचा जा सकता है। सूचना प्राप्त करने और उसके प्रसार में लगने वाले समय में कमी आने के कारण तमाम तरह की सूचनाओं और अनुभवों को आपस में बांटना सरल हो जाएगा। याहू और गूगल जैसे सर्च इंजनों का 57 प्रतिशत इंटरनेट उपभोक्ता करते हैं। इनमें कुछ होम पेज भारतीय भाषाओं में भी हैं। इनके माध्यम से और अधिक देशी पर्यटकों तक पहुंचा जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन तत्परता का सिंहावलोकन

क्र.	विचारणीय विषय	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित परियोजना
1.	सूचना प्राप्त करना	इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। सर्किट जिलों में पर्यटन के लिए और अधिक मार्केटिंग की जरूरत	इंटरनेट मार्केटिंग राज्य के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए वेब पोर्टल बनाना, मौजूदा वेबसाइट का उपयोग
2.	आनलाइन बुकिंग, भुगतान और आरक्षण की सुविधा	इस समय आनलाइन बुकिंग, आरक्षण और भुगतान सुविधाएं, देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक नहीं हैं।	आनलाइन बुकिंग आरक्षण और भुगतान के लिए वेब पोर्टल
3.	पर्याप्त परिवहन सुविधाएं	अपर्याप्त और अधोस्तरीय परिवहन सुविधाएं	
3(क)	सड़क मार्ग	इस दिशा में प्रयत्न हुए है। अंदरूनी क्षेत्रों के लिए परिवहन सुविधाएं अभी भी समस्याग्रस्त	बढ़िया सड़कों के निर्माण के लिए पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी)
3(ख)	रेलवे	मौजूदा रेल संरचना का उन्नयन होना है। देश के विभिन्न भागों से जम्मू का रेल संपर्क अच्छा है। रेल मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे उधमपुर, श्रीनगर-बारामूला रेलमार्ग से व्यापार को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा	रेलवे स्टेशनों के पास पास सहायक परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी भागीदारी आमंत्रित करना (उदाहरणार्थ-कृषि निर्यात प्रक्षेत्रों की स्थापना)
3(ग)	वायुसेना	वर्तमान में तीन विमान तल लेकिन यात्री और विमान तम (टर्मिनल) क्षमता ना काफी	विमान तलों के उन्नयन हेतु पी.पी.पी.
4	अन्य सुविधाओं का प्रावधान	स्पद्धात्मक और रियायती मूल्यों की आवश्यकता सेवाओं का अधिक विकल्प और अधिक संपर्क सुविधा	
4(क)	पेयजल सुविधा	पानी की कमी की समस्या के निराकरण की आवश्यकता	वर्षा जल का संचयन (हार्वेस्टिंग)
5	साहसिक पर्यटन के उन्नयन के लिए सुरक्षा सावधानी	क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को लागू करने की आवश्यकता	बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूर्व में ही बीमा किये जाने का प्रावधान
6	स्थानीय समुदाय से अंर्तव्यवहार ग्रामीण पर्यटन	स्थानीय समुदायों की और ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए	ग्रामीण पर्यटन के उन्नयन के लिए समुदाय आधारित पहल

आनलाइन बुकिंग और आरक्षण की सुविधा को सरल बनाना : दूसरे देशों में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को देखते हुए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार की यात्राओं और आवास के आरक्षण, बुकिंग और भुगतान की आनलाइन सुविधा होनी जरूरी हैं। इस समय जम्मू और कश्मीर में, आरक्षण, बुकिंग और भुगतान की आनलाइन सुविधाएं ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसा पहले बताया जा चुका है।

बुनियादी सूचनाओं की अच्छी खासी उपलब्धता के बावजूद निजी आपरेटरों और सरकार के बीच बेहतर संपर्क और समन्वय के लिए इंटरनेट सुविधा की एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता है ताकि कुकिंग की योजना बना कर उस पर अमल किया जा सके। इसके लिए जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग की मदद से एकीकृत सव्यवहारिक बैंकिंग समाधान लागू किया जा सकता है। इसमें ने केवल स्थानीय भुगतान शामिल होगा बल्कि अन्य मुद्राओं में भी भुगतान की सुविधा रहेगी। इस प्रकार किसी भी देशी-विदेशी संभावित पर्यटक के लिए एक ही स्थान पर भुगतान और आरक्षण की सुविधा होने से उलझी समस्याएं कम होगी।

परियोजना क्र 2 : ऑनलाइन बुकिंग और आरक्षण के लिए वेब पोर्टल

यद्यपि इस दिशा में प्रयास किए गए हैं लेकिन और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। यात्रा, आवास और व्यक्तिगत भ्रमण कार्यक्रमों के लिए बेहतर इंटरनेट संपर्क सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए अलग से एक वेब पेटिल खोला जा सकता है या फिर जम्मू कश्मीर पर्यटन की वेबसाइट के हिस्से के रूप में भी शुरू किया जा सकता है।

प्रस्तावित वेब पोर्टिल के लिए ई-वाणिज्यिक माडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी की भावना से विकसित किया जाना चाहिए। निजी निवेशकों को राज्य और केंद्रीय स्तर पर इंटरनेट गुमटियों और कार्यस्थलों में निवेश करना चाहिए। सरकार राज्य और केंद्र कर्ज अथवा अंश पूंजी के रूप में धन मुहैया कराने के अलावा आवश्यक डाटाबेस (आधारभूत आंकड़ें) अपलब्ध करायेगी। इसके अतिरिक्त, यात्रा, आवास और भ्रमण के बारे में सूचनाएं देने के लिए स्थानीय संस्थाओं और उद्यमियों को इस प्रणाली में निवेश के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिए। वे इस ढांचे में अशं धारक के रूप में भाग ले सकते हैं।

पर्याप्त परिवहन सुविधाएं- सड़क, रेल और वायुमार्ग

आनंदमय पर्यटक अनुभव के लिए परिवहन के द्रुतगामी साधन पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। इन सुविधाओं की कमी देशी और विदेशी पर्यटकों के आगमन में प्रमुख बाधक है। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के बारे में वांछित सूचना इंटरनेट के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, खासकर विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार राज्य में आम संरचना के सुधार के लिए जोरदार प्रयास कर रही है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।

यद्यपि हाल के वर्षों में सुविधाओं में काफी हद तक सुधार हुआ है

IAS/PCS-2005-06

GEOGRAPHY & GENERAL STUDIES (Hindi & English Medium) with

SAROJ KUMAR

SANJAY AGGARWAL
IST RANK
IAS 2002

DEVENDRA PINCHA
UTTRANCHAL & U.P.P.C.S.
TOPPER-2005

KRISHAN KUMAR NIRALA
I.A.S.-2005

PREMVIR SINGH
I.A.S.-2005

RAM BABU
I.A.S.-2005

MANOJ KUMAR SHARMA
I.A.S. 2005

MANOJ SAINI
UTTRANCHAL
TOPPER-2005

RAKESH SAINI
Haryana PCS
TOPPER -2005

SHRADDHA JOSHI
UTTRANCHAL P.C.S.
TOPPER -2005

DEEPAK RAWAT
I.A.S. 2005

SHAKTI SINGH
UTTRANCHAL P.C.S.
TOPPER-2005

MITHLESH KUMAR
HARYANA P.C.S.
TOPPER -2005

DATA RAM
IST RANK (SC/ST)
RAJASTHAN P.C.S.

DILIP SINGH TOMAR
TOPPER
M.P.P.C.S.

Batch Starts :-

Every Month of 5th, 10th, 15th, 20th, 25th & 30th dated
For Geog., (P.T. & Mains) & G.S. (P.T. & Mains)

Batch Starts :-

10th October, 2005 : Geog. (P.T.) & G.S. (P.T.)

Geography (P.T. & Main) & G.S. (P.T. & Main)
(Hindi & English Medium)
Test Series Programme throughout the year

Postal Course for Geog. & G.S. (P.T. & Mains) & Sociology (Mains)

G.S. Marks 2005		Geog. Marks	Interview Marks
Krishan Kumar Nirala 360	Manoj Kumar Sharma 358	R. Kumari (Eng. Med.) 426	Abhey Kumar, IAS 2004 240
Premvir Singh 338	Deepak Rawat 323	Harkesh Mina (Hindi Med.) 362	Sanjay Aggarwal, IAS 2002 226

For prospectus and more details please contact on Tel. No. 9811285863

: CONTACT :

DR. VEENA SHARMA
SAROJ KUMAR'S IAS ERA
1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Road, Near Shakti Nagar Red Light,
Above P.N.B., Delhi-110007 Ph.: 23847516 Mob. : 9811285863

लेकिन अभी भी बहुत सी संभावनाएं अछूती पड़ी है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य के अनेक स्थानों में पहुंचने के साधन अपर्याप्त हैं। अब हम वायुमार्ग, रेल और सड़क परिवहन से जुड़ी उन परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे पर्यटन सर्किट के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के अवसरों में इजाफा हो सकेगा।

वायुमार्ग

विमान परिवहन सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे तेज परिवहन का साधन है। लंबी दूरी के पर्यटकों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लाने ले जाने में इसकी प्रबल भूमिका रहेगी। विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए विमान परिवहन यात्रा का प्रमुख साधन है। अत: अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राज्य में वायु मार्गीय परिवहन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार लाना होगा।

वर्तमान में, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और जेट एयरवेज घरेलू उड़ाने संचालित करती है, जो श्रीनगर, जम्मू और लेह के तीन प्रमुख नागरिक विमान तलों को आपस में जोड़ती हैं। लेकिन अधिक मूल्य कम उड़ानें पर्यटन को प्रोत्साहित करने में बाधा हैं। काफी पहले बुकिंग करनी होती है। रियायती मूल्य पर बेहतर संपर्क सुविधा की आवश्यकता को महसूस करते हुए, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर विमान तल को जनवरी 2005 में अंतरराष्ट्रीय विमान तल घोषित कर दिया है।

इससे विदेशी पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। अधिक यात्री क्षमता वाले बड़े विमान के उड़ान भरने और उतरने की सुविधाजनक बनाने के लिए 59 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से हवाई अड्डे के भवन का विस्तार करने के साथ-साथ सुविधाओं को भी उन्नत बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु सुरक्षा कारणों से अभी केवल इंडियन एयरलाइन्स और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया को ही विमान तल का उपयोग करने की अनुमति होनी। तथापि हमें विश्वास है कि राज्य में सुरक्षा वातावरण में सुधार की वजह से आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही श्रीनगर विमान तल को और भी उन्नत बनाने की आवश्यकता होगी।

परियोजना क्र. 3 : विमानतलों के उन्नयन के लिए (पीपीपी) सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों की भागीदारी

श्रीनगर विमानतल के उन्नयन के लिए और क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और अधिक विमान सेवाओं को लाने की अच्छी संभावना है। इसके अलावा सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की आवश्यकता है जिससे ज्यादा यात्रियों और विमानों को जगह मिल सके। इसी प्रकार जम्मू और लेह के विमानतलों का उन्नयन भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी की भावना में, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा कर किया जा सकेगा। इन परियोजनाओं की व्यापारिक संभाव्यता की गणना अलग से की जानी चाहिए। पर्यटन वृद्धि के लिए मुख्य विमानतलों के विस्तारित संपर्कों के रूप में छोटे विमान और हवाई पट्टियों के विकास की भी संभावना है।

सड़क परिवहन

कार और बस, अपनी कम लागत और सरलता से उपलब्धता के कारण परिवहन का सबसे आसान और आम साधन है। घरेलू पर्यटक आम तौर पर इसी साधन को पसंद करते है, क्योंकि उन्हें इससे अपनी यात्रा का स्वतंत्र कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा रहती है और निजता भी। इसके अलावा कई पर्यटक अपनी यात्रा में क्षेत्र की खोज के लिए यातायात के इसी साधन को वरीयता देते है। यद्यपि सड़क परिवहन प्रणाली के विकास के लिए प्रयास और निवेश तेज किए जा रहे है, तथापि राज्य के अंदरूनी क्षेत्र, दुर्गम और पहाड़ी होने के कारण समस्यामूलक बने हुए हैं। लेकिन इन कठिन क्षेत्रों में स्थित कतिपय पर्यटक आकर्षणों तक केवल सड़क मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। अत: इन पर्यटक स्थलों के विकास के लिए सड़कों का उच्च स्तर का होना अनिवार्य है। लद्दाख शीत कालीन खेलों के प्रमुख स्थानों में से है, लेकिन श्रीनगर और मनाली से पहुंचने के लिए अत्यंत कठिन सड़क मार्गों से गुजरना पड़ता है।

जम्मू के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए से पहुंचा जा सकता है। यह राजमार्ग पंजाब से शुरू होकर इस शहर (जम्मू) से होता हुआ गुजरता है और राजधानी श्रीनगर सहित राज्य को अन्य भागों से जोड़ता है। राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर भारत के अनेक छोटे-बड़े शहरों के लिए जम्मू से बसें चलाता है। लेकिन बेहतर और स्पर्धात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए डीलक्स और आरामदायक बसों के चलाये जाने की जरूरत है। इसके लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ये परिवहन सेवाएं एवं व्यापक पर्यटन लक्ष्य का अनिवार्य भाग हैं, इसलिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इनकी सहायता के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इससे तीन प्रकार से क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। (1) प्रथम, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नई बसों से राज्य में आने वाले पर्यटकों को अधिक सुविधा मिलेगी (2) दूसरे, इससे काम की तलाश में भटक रहे तमाम शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार और काम के अवसर मिलेंगे। और (3) तीसरे, इससे राज्य में उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और यह समय की मांग भी है।

परियोजना क्र. 4: क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण और उन्नयन

राज्य में उच्च स्तर की सड़कों का निर्माण और उन्नयन जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पीपीपी की भावना में किया जा सकता है। देश के अन्य भागों में निजी निवेशकों ने सफलता हासिल की है। राज्य में भी वे बीओटी (बिल्ट आपरेटर एंड ट्रांसफर अर्थात बनाओ, चलाओ और वापस करो) आदि निजी भागीदारों के विभिन्न माध्यमों से परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं।

जम्मू कश्मीर सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहायता मिली है। परियोजनाएं बनाकर अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दी गई है। इस योजना का लाभ उठाते हुए, वर्तमान में क्षेत्रों में दुरूह लोगों का आना-जाना

आसान बनाया जा सकता है। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, स्थानीय लोगों को भी काफी लाभ होगा। इस समय ग्राम संपर्क कार्यक्रम के तहत 20 गांवों को जोड़ने का काम चल रहा है। इनमें से 5 गांवों को अब तक जोड़ा जा चुका है। सरकार ने 10 नई सड़क परियोजनाओं का काम हाथ में लिया हैं। अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है और प्रगति पर निगरानी रखने की आवश्यकता है।

रेलमार्ग

जम्मू-कश्मीर में रेलमार्ग का विकास परिवहन के संभावित साधनों के रूप में किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए मौजूदा रेल संरचनाओं का उन्नयन होना जरूरी है। जम्मू का तो देश के अन्य शहरों से अच्छा रेल संपर्क है, पर अन्य शहरों के साथ ऐसा नहीं है। रेल संरचनाओं का निर्माण भी राज्य के दुरूह और दुर्गम स्थानों, पहाड़ियों आदि को देखते हुए काफी कठिन है।

287 किलोमीटर लंबे उधमपुर-श्रीनगर-बारमूला रेलमार्ग के निर्माण और जम्मू तवी-जालंधर रेलमार्ग को दोहरा किए जाने में सरकार ने भारी निवेश किया है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन, राज्य आर्थिक सामाजिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के उन्नयन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस रेल लाइन का क्षेत्र से वस्तुओं और सामान के आवागमण को बढ़ावा देने की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु इसके लिए सहायक सड़क संपर्क प्रणाली स्थापित करनी होगी, जिससे वस्तुओं/माल का परिवहन आगे तक हो सके। रेलमार्गों के साथ ही निर्यात क्षेत्रों यथा- एईजेड की स्थापना से राज्य में वस्तुओं के आने और उन्हें बाहर भेजने में सुविधा होगी। इससे आपूर्ति करने की शृंखला सुदृढ़ होगी और मूल्य भी स्पर्धात्मक होंगे।

अन्य सुविधाओं का प्रावधान

पर्यटन संरचना के उन्नयन और विकास के साथ-साथ राज्य के लिए यह भी आवश्यक है कि गंतव्य प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए जिससे चरम यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सके। इसके लिए यात्रा के स्थान संवैधानिक रूप से जुड़े अन्य पहलुओं संबंधित गतिविधियों और निहित सुविधाओं पर ध्यान देना होगा।

पेयजल सुविधाएं

देश में भूजल संसाधनों में निरंतर हो रही कमी के साथ ही आमतौर पर देखा गया है कि विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों की तादाद तो बढ़ रही हैं पर वहां उत्तम किस्म के पेयजल की सुविधा क्षीण होती जा रही है। जहां तक जम्मू-कश्मीर का प्रश्न है, राज्य पेयजल के मामले में अपने हिस्से की समस्या भोग चुका है। इसलिए, न केवल पर्यटनों के लिए बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी इस समस्याओं का निराकरण अति आवश्यक है। इस दिशा में प्रयास किए गए है। विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं और पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नई पाइप लाइनें डाली गई हैं। अनेक स्थानों में नलकूपों और हैंडपंपों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त समस्या वाले 30 शहरों में ही 21 में पेयजल सुविधा में वृद्धि की योजनाओं पर अमल हो चुका है।

The power to excel

Does your son have it?

He thinks differently. He aims high.

And he acts with a self-assurance that never ceases to amaze you.

You rightly believe he'll make his mark in any field he chooses.

But remember: today, the choicest of careers are the toughest to enter. And the finest of institutions mean the keenest of competition.

Does he have the power to outperform the brightest of contestants? The power to excel?

Make sure he does, with Brilliant Tutorials – a pioneer whose correspondence courses have brought success to thousands of young aspirants like your son, for nearly 35 years now.

Brilliant's Postal Courses open for Competitive Entrance Exams

IIT-JEE

- **2-Yr. ELITE** Course with **YG-FILEs + B.MAT**, for 2007 (Std. XI)
- **1-Yr. Course** with **YG-FILE + B.MAT**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **YG-FILE + B.MAT**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **TARGET-IIT:** Primer Courses for students of Std. IX, X

AIEEE & BITSAT

- **1-Yr. Course** for **CBSE's All-India Engg. Entrance Exam** 2006 & BITSAT 2006 (BITS Pilani/Goa)

GATE

- GATE 2006

IAS, ESE

- Civil Services Exam '06
- Engg. Services Exam '06

CSIR-UGC/UGC (NET)

- JRF/L Exams, June '06, Dec. '06

MEDICAL ENTRANCE

- **2-Yr. CBSE-PLUS** with Question Bank **(QB) + B.NET** (Brilliant's National Evaluation Tests) for Medical Entrance 2007 (Std. XI)
- **1-Yr. Course** with **QB + B.NET**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **QB + B.NET**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **TARGET-MBBS:** Primer Courses for students of Std. IX, X

MBA

- MBA Entrance Exams, 2006
- Target MBA: For early preparation towards the 2007 Exams

MCA

- MCA Entrance Exams, 2006

GEOLOGISTS EXAM 2005

GRE, TOEFL, BANK P.O.

- Year-round enrolment

BRILLIANT TUTORIALS®

For free prospectus and application form for the course of your choice write, call, fax or access www.brilliant-tutorials.com

Box: 4996-YOH, 12, Masilamani St., T. Nagar, Chennai 600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829 e-mail: enquiries@brilliant-tutorials.com

परियोजन क्र. 6 : पर्याप्त जल सुविधाओं का प्रावधान

यद्यपि राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में प्रयास किए गए हैं, तथापि दैनिक उपयोग का पानी (पेयजल नहीं) प्राप्त करने के लिए पर्यटक सम्पत्तियों (भवनों) पर वर्षाजल का दोहन किया जा सकता है। इसके साथ ही पेयजल की विभिन्न आकार में पैकेजिंग के लिए लघु उद्यमियों को आगे आना होगा। वे पालीथीन की थैलियों, बोतलों, प्लास्टिक के गिलासों, डिब्बों आदि में पानी की पैकेजिंग कर सकते हैं। और पेयजल के इन पैकेजों को विभिन्न बाजारों और पर्यटक स्थलों पर आपूर्ति कर उनकी तात्कालिक प्यास बुझा सकते हैं। परंतु इन पैकजों के उचित निस्तारण और रिसाईकिल कर उनके उपयोग के साधनों के बारे में भी सोचना होगा।

पर्यावरण और ग्रामीण पर्यटन का उन्नयन

किसी भी क्षेत्र में संपोषणीय पर्यटन के उन्न्यन के लिए स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी से न केवल पर्यटन अुनभव सच्चा और विश्वसनीय लगता है बल्कि इससे स्थानीय समाज भी शक्तिसंपन्न होता है। स्थानीय लोगों और समुदायों, उनके रीति रिवाजों और उनकी जीवन शैलियों के योगदान को मान्यता देने के साथ-साथ इस तथ्य को भी स्वीकारना आवश्यक है कि पर्यटन के लाभों में इन लोगों की भी समान सहभागिता है।

परियोजना क्र. 7 : ग्रामीण पर्यटन के उन्नयन हेतु समुदाय आधारित पहल

हमारा प्रस्ताव एक ऐसे आदर्श का है जहां स्थानीय क्षेत्र एक नाभिचक्र (हर्ष) है और निकटवर्ती गांव उसकी तीलियों की भांति समुदाय आधारित धरोहर (विरासत) वाला सर्किट विकसित करते हैं जिसमें स्थानीय पकवान, हस्तशिल्प और समुदाय के अन्य सांस्कृतिक पहलुओं का भली-भांति परिचय मिलता है। मुख्य पर्यटन गंतव्य स्थल जहां पर्यटक ठहरते है, नाभिचक्र का काम करेगा। निकटवर्ती गांवों की संस्कृति, पकवान आदि का स्वाद चखने के लिए दैनिक भ्रमण और इच्छा हो तो रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्या हितैषी संपोषणीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर में प्रचुर संभावनाएं है।

साहसिक पर्यटन का उन्नयन

जम्मू और कश्मीर में साहसिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। कुछ प्रणालियां पहले से ही काम कर रही हैं। लद्दाख में ट्रेकिंग, व्हाइट वाटर रैफ्टिंग, कैनोइंग और पर्वतारोहण की संभावनाओं को, उसको साहसिक खेलों के स्थल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। गुलमर्ग को भी शीतकालिन खेलों के गंतव्य के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते समय हमें अपनी जिम्मेदारी का भी ख्याल रखना होगा। साहसिक पर्यटन को समुचित प्रोत्साहन मिले, इसलिए किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए न्यूनतम सुरक्षात्मक उपायों का अपनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए एक नियामक संस्था है जो बुनियादी मानक सुनिश्चित करे।

पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ अनिवार्य बीमा के बारे में भी लोगों को बताना भी साहसिक पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण है।

परियोजना क्र. 8: साहसिक पर्यटन के उन्नयन हेतु बीमा का प्रावधान

साहसिक खेलों/गतिविधियों में पर्यटक निश्चित होकर भाग ले सकें, इसके लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को बीमा की सुविधाएं मुहैया करा सकती हैं। यदि साहसिक पर्यटन को भी (पर्यटन) सर्किट विकास का अभिन्न अंग मान लिया जाए तो बैंकों के लिए इसका हल निकालना आसान हो जाएगा।

उपसंहार

"भारत मानवजाति का पालना है, इंसान की बोली का जन्म स्थान, इतिहास की मां, आख्यानों की दादी और परंपराओं की परदादी। हमारी सबसे बहुमूल्य और मानव इतिहास की सबसे आकर्षक समाग्रियों का खजाना भारत में ही भरा पड़ा है।"

"जहां तक मैं निर्णय कर सकता हूं कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी गई है, जो मनुष्य अथवा प्रकृति द्वारा भारत को उन देशों में सबसे असाधारण देश बनाने में न की गई हो, जहां सूर्य भ्रमण करता है।" -मार्क ट्वेन

कश्मीर की रहस्यात्मक और सांस्कृतिक धरोहार ने सदस्यों से समूची दुनिया से सैलानियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह नजारों सांस्कृतिक, पाकशास्त्रीय और आनंद के विविध उपायों से सुसज्जित है लेकिन पिछले 15 वर्षों से राज्य अपनी पूरी संभावनाओं और क्षमताओं का दोहन नहीं कर सका है। पर्यटन के सामाजिक लाभों से राज्य सतत वंचित रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी संपोषणीय पर्यटन के प्रोत्साहन में मुख्य बाधक तत्व संरचना, सूचना और विपणन की सुविधाओं का अभाव है। इसके साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दे तो हैं ही, जिनका निदान आवश्यक है।

इस रिर्पोट में हमने जम्मू और कश्मीर राज्य में संपोषणीय पर्यावरण की आवश्यकता और संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए पर्यटन की सुविधा के विस्तार के एककृत सामाधान पर ध्यान केंद्रित किया है। सामाधान, मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा (आईटीईएस) के उपयोग से आनलाइन बुकिंग, आरक्षण और भुगतान सुविधाओं के साथ-साथ पर्यटन सुविधाओं के समेकित विपणन पर केंद्रित है। इसके अलावा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी की पर्याप्त परिवहन सुविधाजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी की भावना में पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के विकास से पर्यटन संरचना से जुड़ी समस्या तो दूर होंगी ही देशी और विदेशी पर्यटन के केंद्र के रूप में क्षेत्र को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। साथ ही भारत सरकार एक पर्याभ्रमण विकास निधि (इकोटूरिज्म डेवलेपमेंट फंड) बना कर और आकर्षक राजकोषीय लाभ दे कर सुविधाजनक वातावरण तैयार कर सकती है।

हमें यकीन है कि उपर्युक्त परियोजनाओं पर रणनीति और कुशल क्रियान्वयन से जम्मू और कश्मीर का विकास भारत के प्रमुख पर्यटक केंद्र के रूप में सुनिश्चित होगा। ❑

(यस बैंक द्वारा पीएचडीसीसीआई के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ शताब्दी भागीदारी शिखर के लिए तैयार रिपार्ट दी रोड टू इंवेस्टमेंट इन जे एंड के पर आधारित)

जम्मू-कश्मीर समाचार

- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने 1200 लाभ-प्रद इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर में ये आय और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।
- साइबेरिया के बाद दुनिया के सबसे ठंडे स्थान द्रास को एक पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। 1999 के करगिल युद्ध के समय द्रास में भयंकर लड़ाई हुई थी। इसे एक करोड़ की लागत से पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। साथ ही द्रास में लोनी चांद से कोहसर को जोड़ने वाली सड़क को बेहतर बनाने पर 80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने आदर्श गांवों में विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए जिलास्तर की समितियां और ग्रुप गठित करने का फैसला किया है। आदर्श गांवों की स्थापना को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इनका ग्राम विकास पर अच्छा असर पड़ेगा और इनमें विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मानिटरिंग की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री के पुनर्निर्माण पैकेज के तहत राज्य के 119 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा जिनमें सफाई, गलियों, नालियों, सामुदायिक सूचना केंद्र, मनोरंजन पार्क और स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिए एक छोटा बाजार होगा। राज्य सरकार ने अब तक ऐसे 14 आदर्श ग्रामों की आधारशिला रखी है।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने वूलर झील के परिरक्षण की 180 करोड़ रुपये लागत वाली एक परियोजना केंद्र को प्रस्तुत की है।
- 40 करोड़ रुपये मूल्य की सब्जियों के रिकार्ड निर्यात के बाद राज्य के कृषि मंत्रालय ने अधिक जमीन पर सब्जियों की खेती करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है।
- जम्मू-कश्मीर की विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 260 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
- केंद्र ने घाटी की ईंधन की जरूरतें पूरी करने के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव एस.सी. त्रिपाठी ने श्रीनगर में राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद कहा कि उनका मंत्रालय दोनों शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की संभावना पर विचार कर रहा है।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपना वह आदेश वापस ले लिया है जिसके जरिये अविवाहित महिलाओं को उनका विवाह होने तक स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों की वैधता की अवधि सीमित की गई थी। ❑

कश्मीर की बीपीओ फर्म बिजनेस किट तैयार करेगी

जम्मू-कश्मीर में मुख्यालय वाली ठेके पर दूसरों के लिए व्यापारिक कार्य करने वाली फर्म इन्फोटेल एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस (आईएमसी) राज्य के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सेवा प्रदाताओं, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारियों आदि के लिए एक कम लागत वाली व्यापार संवर्धक किट तैयार कर रही है।

आईएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल गुप्ता ने कहा कि हालांकि 'येलो पेजेज' नामक यह प्रकाशन कोई नयी अवधारणा नहीं है लेकिन इसका दृष्टिकोण, प्रकाशित प्रतियों की संख्या और इसका प्रचार-प्रसार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकाशन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत उत्साहपूर्ण है। अन्य अनेक लोगों ने ऐसा प्रकाशन लाने की कोशिश की है लेकिन उनमें से कोई भी टाटा येलो पेजेज जैसा मानक प्राप्त नहीं कर पाया। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनमें से कोई प्रकाशन यहां नहीं टिक पाया।

येलो पेजेज

- प्रसार: 40,000 और पाठक संख्या कम से कम 2,00,000
- कवरेज: लखनपुर से लेह (लद्दाख) तक
- दृष्टिकोण: प्रतियों की संख्या और प्रसार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रकाशन की 40,000 प्रतियां बेची जाएंगी और इनकी पाठक संख्या कम से कम 2,00,000 होगी। इसमें लखनपुर से लेह (लद्दाख) तक का कवरेज होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि 'सिटीइनफो जेके येलो पेजेज' नाम के इस प्रकाशन की प्रतियां जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, प्राइवेट व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अग्रणी फुटकर व्यापारियों को नि:शुल्क भेजी जाएंगी।

श्री गुप्ता ने कहा कि उनकी कंपनी इसकी प्रतियां वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के परिजनों, रक्षा कर्मचारियों, अर्धसैनिक बलों, बैंकों और निगमों को भेजने पर खास तौर से ध्यान देगी।

आईएमसी ने सबसे पहले अप्रैल में 'सिटीइनफो जम्मू लैंडमार्क्स' नामक व्यापार संवर्धन प्रकाशन के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा था। बाद में उसने इसी प्रकाशन का 'कटरा वैष्णोदेवी' संस्करण निकाला। उसने जम्मू लैंडमार्क्स का एक फोल्डेबल संस्करण भी पेश किया था। ❑

(सौजन्य : इकोनामिक टाइम्स)

कश्मीर में गलीचा विश्वविद्यालय खुलेगा

कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प को आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और डिजाइन के लिये नये और डिजीटल तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक शिल्प विकास संस्थान की स्थापना की है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी का एक केंद्र तथा हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादों का एक साझा सुविधा केंद्र होगा।

ये आधुनिक संस्थान श्रीनगर के बागे अली मर्दान खां में खोले जाएंगे और इन्हें पूर्ण विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जाएगा जहां से महत्वाकांक्षी छात्र निकट भविष्य में स्नातक डिग्री एवं शिल्प से मास्टर्स की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। देश में यह अपने ढंग का पहला विश्वविद्यालय होगा।

उद्योग मंत्री पं. मंगतराम शर्मा ने कहा कि देश में हर साल 1,000 करोड़ रुपये मूल्य के गलीचे तैयार करने की क्षमता है जिसे ध्यान में रखते हुए हमने भदोही के आईआईसीटी जैसा संस्थान जम्मू-कश्मीर में खोलने का फैसला किया है। 5.45 करोड़ रुपये की लागत से यह केंद्र खोलने का मूल उद्देश्य गलीचा उद्योग को मानव संसाधन विकास, नवीन डिजाइनों, रंगाई और रंग मिलान करने वाले उपकरणों के आधुनिकीकरण में सहायता देना है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य कंप्यूटर की मदद से डिजाइन करने की क्षमता का विकास करना, नयी डिजाइनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बाजार अनुसंधान करना और दुनिया के अन्य भागों में बेचे जा रहे गलीचों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी है।

यह संस्थान अन्य राज्यों के गलीचा उत्पादकों के साथ संपर्क बढ़ा कर और आपस में विशेषज्ञ भेज कर इस काम में लगे लोगों की सहायता करेगा। यह गलीचा बुनकरों को परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान करेगा। संस्थान को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करा लिया गया है और इसने श्रीनगर के बूलवार्ड से काम करना शुरू कर दिया है। इसके स्थायी परिसर का निर्माण इसी साल शुरू हो रहा है। इस संस्थान का सारा खर्च केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय उठाएगा। जब तक इसकी अपनी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इसे आईआईसीटी भदोही के फैकल्टी संचालित करेंगे। यह संस्थान अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

जम्मू-कश्मीर सरकार इस समय हर वर्ष 350 करोड़ रुपये मूल्य के गलीचे निर्यात कर रही है। लेकिन यह क्षमता बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये मूल्य के गलीचों का निर्यात किया जा सकता है। राज्य में लगभग 80,000 शिल्पकार इस काम में लगे हुए हैं।

बागे अली मर्दान खां में स्थापित किया जा रहा शिल्प विकास संस्थान सभी शिल्पों को ऐसे डिजाइन उपलब्ध कराएगा जो बाजार में लोकप्रिय हो सकेंगे। इस पर 9.10 करोड़ रुपये लागत आएगी। यह संस्थान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ सहयोग करके बाजार अनुसंधान और जानकारी इकट्ठा करेगा और उद्योग को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करेगा। यह इस उद्योग के उपयुक्त टेक्नोलॉजी और उपकरण विकसित करेगा और इस शिल्प के लिए दस्तकारों के बीच दक्षता प्रसार करने वाली ज्ञान संस्था की भूमिका निभाएगा। यह इस शिल्प संबंधी जानकारी और उत्पादों को नेटवर्क के जरिये विश्व बाजार से जोड़ेगा और डिजाइन नवीकरण के लिए डिजीटल टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगा। यह संस्थान कश्मीरी उत्पादों का व्यापार चिह्न तैयार करने में सहायता करेगा और अगली पीढ़ी के उद्योगपतियों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। साथ ही, यह गुणवत्ता आश्वासन, कच्चे माल के प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास के जरिये नये कच्चे माल के निर्माण में सहायक होगा। इस संस्थान ने काम शुरू कर दिया है और दो पाठ्यक्रम संचालित कर चुका है।

बागे अली मर्दान खां में एक साझा सुविधा केंद्र भी खोला जा रहा है। इस पर करीब 1.96 करोड़ रुपये लागत आएगी। यह केंद्र उत्पादन के बाद जरूरी अति आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। ❑

(सौजन्य : स्टेट्समैन)

श्रीनगर की डल झील में जलक्रीड़ा उत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेती बालिकायें

प्रमुख अमरीकी विश्वविद्यालयों के छात्र जम्मू-कश्मीर के ब्रांड अम्बेसडर बनेंगे

जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग जल्दी ही अनोखे ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त करने वाला है। हार्वर्ड, येल, एमआईवी, प्रिंसटन और स्टान्फोर्ड जैसे जाने-माने विश्वविद्यालयों के छात्र शीघ्र यह जिम्मेदारी संभालेंगे।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जल्दी ही विदेशी और खासतौर से अमरीकी छात्रों के लिए एक विशेष परियोजना, गुरुकुल पैकेज शुरू करने वाला है। यह उन छात्रों के लिए होगी जो अपने वार्षिक ग्रीष्मावकाश में भारत आ सकें और गांवों में रह कर गलीचे, शाल और कंबल बनाना सीखें। यह क्रैश कोर्स पूरा करने पर उन्हें सरकारी तौर पर एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

पर्यटन मंत्री रेणुका चौधरी का विचार है कि स्वदेश लौट कर ये छात्र अपने लोगों को बता सकेंगे कि पर्यटन के लिहाज से कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है।

गुरुकुल पैकेज के लिए पांच गांवों (जम्मू में दो- सुइंसर और झीरी तथा कश्मीर में तीन- पहलगाम, द्रुंग और गगनगिर) का चुनाव किया गया है। इन अमरीकी छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सिद्धहस्त हस्तशिल्पियों की सूची तैयार की जा रही है।

पांच अन्य गांव भी गुरुकुल पैकेज स्कीम के अंतर्गत आएंगे। ये हैं- आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली, तमिलनाडु में चेट्टिनाड, उड़ीसा में रघुराजपुर, हिमाचल प्रदेश में नगर और केरल में अरामुल्लाह।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि गुरुकुल पैकेज स्कीम की घोषणा के लिए अलग से एक वेबसाइट तैयार की जा रही है जिसे अमरीकी विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों से जोड़ दिया जाएगा। छात्रगण भारत आ सकते हैं, स्थानीय लोगों की तरह गांवों में रह सकते हैं और सिद्धहस्त शिल्पियों से शिल्प की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

कश्मीर एक सुरक्षित प्रदेश है- यह बताने का छात्र समुदाय से बढ़िया और कोई माध्यम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन की भारत में अपार संभावनाएं हैं और इनका उपयोग किया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही की मेरी अमरीका की यात्रा के दौरान गुरुकुल स्कीम की जानकारी पाकर लोग रोमांचित हो उठे थे। वे सब यहां आने और शिल्पियों की तरह रहने के इच्छुक हैं। वे यहां पांच सितारा होटलों में नहीं, गांवों में रहना चाहते हैं। कोरिया और फ्रांस के अनेक छात्र ओडिसी नृत्य सीख रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पर्यटन सचिव अनिल गोस्वामी के अनुसार, जुलाई 2006 में छात्रों का पहला बैच आने वाला है। उन्होंने कहा कि तब तक गांवों में मूल बुनियादी सुविधाएं सुधार दी जाएंगी। ❑

(सौजन्य : टाइम्स आफ इंडिया)

50 वर्षों बाद वाघा होकर व्यापार

लहसुन और आलू लदे ट्रक भारत से वाघा होकर पाकिस्तान जाने लगे हैं। इसके साथ ही आधी सदी में यह पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच सड़क मार्ग से व्यापार फिर होने लगा है।

इस व्यापार मार्ग के फिर खुल जाने से दोनों देशों के व्यापारियों की काफी पुरानी मांग पूरी हो गई है। इससे पहले इन व्यापारियों को दोनों तरफ पहले अपना माल निकटतम बंदरगाह या रेलवे स्टेशन पहुंचाना पड़ता था जिसके बाद यह सीमापार भेजा जाता था। अमृतसर से एक निर्यातक राजदीप उप्पल ने टेलीफोन पर बताया कि पिछले पांच दशकों में यह पहला अवसर है जब सीधे व्यापार की अनुमति दी गई है। व्यापारी खुश हैं और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं।

भारत और पाकिस्तान ने इस वर्ष के शुरू में चार तरह की सब्जियों के व्यापार की अनुमति देने पर सहमति प्रकट की थी। ये थीं - प्याज, टमाटर, लहसुन और आलू। इसके अलावा मवेशियों- अधिकांशत: भेड़, बकरी और भैंसों के व्यापार की भी अनुमति दी गई। इसके बदले भारत पाकिस्तान से मसूर, कपास, चीनी और सूखे मेवे खरीदना चाहेगा।

2004 में दोनों देशों के बीच व्यापार 38 करोड़ डालर तक पहुंच गया। लेकिन भारतीय उद्योग समूहों के अनुसार दुबई या सिंगापुर जैसे तीसरे देश होकर एक अरब डालर मूल्य का व्यापार हुआ।

समुद्र अथवा रेल मार्ग से अधिकृत व्यापार में काफी देर तटकर को लेकर होती है। इसके कारण जल्दी खराब होने वाले माल - फल, सब्जियों आदि का व्यापार नहीं हो पाता। व्यापारियों का कहना है कि सड़क मार्ग से व्यापार शुरू हो जाने से दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

उप्पल ने कहा कि यह हमारे नेताओं के बीच महीनों से चल रही वार्ता का व्यावहारिक लाभ है। उप्पल ने दो ट्रकों में 500 टन लहसुन और आलू लदवा कर पाकिस्तान रवाना किया।

लेकिन व्यापारी अभी भी प्रतिबंधात्मक वीजा नियमों से खुश नहीं हैं क्योंकि इनके कारण पाकिस्तानी व्यापारी भारत में निर्बाध घूम-फिर नहीं सकते। उप्पल ने कहा कि हम पाकिस्तानी व्यापारियों को भारत बुलाना चाहते हैं ताकि वे घूम-फिर कर देख सकें कि यहां व्यापार की कितनी अधिक गुंजाइश है। लेकिन मौजूदा नियमों के अंतर्गत उन्हें एक या दो शहर में आने का वीजा मिलता है। ❑

(सौजन्य : हिंदुस्तान टाइम्स)

जम्मू-कश्मीर में व्यापारिक खेती को प्रोत्साहन

कंगन का प्रांग गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। इसे अब सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती के लिए विकसित किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री, अब्दुल अज़ीज़ ज़रगर ने श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर प्रांग में कृषि उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि प्रांग को बल्गेरियाई गुलाब की खेती के लिए भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गांव को औषधियों में काम आने वाले और सुगंधित पौधों की खेती के अनुकूल बनाने की बहुत गुंजाइश है।

कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रीन हाउसेज के अलावा यहां किसानों को जुताई के लिए पावर टिलर उपलब्ध कराए जाएंगे। टेक्नोलॉजी मिशन के तहत लाभार्थियों को प्रति टिलर 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।

उद्योगपतियों ने संयुक्त रूप से यहां पांच हेक्टेयर जमीन पर विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए एक कृषि फार्म विकसित किया है। इनमें मछली पालन, फूलों की खेती, खुंब उगाने और बेमौसम की सब्जियों की खेती शामिल है।

राज्य कृषि मंत्री ने कृषि का व्यापार सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए हर प्रकार की संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे बागवानी और फूलों की खेती शुरू करें क्योंकि इनमें उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति बदलने की क्षमता है।

कृषि मंत्री ने श्रीनगर में संवाददाताओं को बताया कि इस समय कृषि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाजुक स्थिति में है। ऐसे समय में हर एक को और खासतौर पर किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को खेती के अंतरराष्ट्रीय स्तर के तरीके अपनाए जाने में सहायता करनी चाहिए ताकि पुराने और परंपरागत की जगह नये तरीके अपनाए जा सकें।

फूलों की खेती की प्रभूत संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र की ओर बेरोजगार कृषि स्नातकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें दो वर्षों तक 2,000 रुपये प्रतिमास का स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव किया है ताकि वे अपना लाभप्रद कृषि कारोबार जमा सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि श्रीनगर के पास ही गंदरबल के नुर्नर में फूलों की खेती का एक आदर्श फार्म स्थापित किया गया है। इससे इच्छुक उद्यमी आवश्यक जानकारी और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के विविधीकरण के बारे में श्री ज़रगर ने कहा कि अखरोट की खेती को राज्य की भावी कृषि गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्र माना गया था। अखरोट उत्पादन में कलम बांधने का यूरोपीय तरीका अपना कर इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फलों के पुराने पेड़ों की जगह नये पेड़ लगाने और पुरानी किस्मों की जगह नयी किस्में उगाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत एक समग्र बागवानी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कलम किए हुए अखरोट के पेड़ तीन साल में फल देने लगते हैं जबकि सामान्य वृक्ष 15 वर्ष में फल देते है। उन्होंने कहा कि अखरोट की दो नयी प्रजातियां 'सुहामा' और 'हमदन' पहले ही अपनाई जा चुकी हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को फिर बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है और सहकारिता गतिविधियों में मुर्गीपालन शामिल किया जा चुका है। राज्य में प्रतिवर्ष 2-20 करोड़ मुर्गे-मुर्गियां आयात की जाती हैं। स्थानीय क्षमता का उपयोग करके यह कमी दूर की जा सकती है। इसके लिए 400 कुक्कुट पालक सहकारी समितियां पंजीकृत कराई जा चुकी हैं। ❑

(एजेंसियां)

जम्मू-कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार

इंडिया टुडे के मुख्यमंत्री सम्मेलन में वित्तमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री की ओर से सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार इंडिया टुडे समूह ने जम्मू-कश्मीर राज्य को पिछले तीन वर्षों में गरीबी उन्मूलन के लिए दिया गया। नयी दिल्ली स्थित अशोक होटल में अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित एक भव्य समारोह में 'राज्यों में राज्य' के तृतीय वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति और मुख्य अतिथि भैरों सिंह शेखावत ने ये पुरस्कार वितरित किए। इस समारोह में अन्य लोगों के अलावा 14 राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इंडिया टुडे ने पिछले तीन वर्षों में राज्यों में किए गए सामाजिक-आर्थिक कार्यों का निष्पक्ष अध्ययन किया। यह अध्ययन देश भर के 17 राज्यों में किया गया। राज्यों को पूंजी निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, मूल-सुविधाओं, उपभोक्ता बाजार, कृषि और मैक्रो-आर्थिक निष्पादन क्षेत्रों में काम करने के लिए ये पुरस्कार दिए गए।

जम्मू-कश्मीर को गरीबी उन्मूलन क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करने वाला राज्य माना गया। अध्ययन से पता चला कि इस राज्य में गरीबों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है और इसने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार दिखाया है। पाया गया कि इस राज्य में आर्थिक विकास गरीबों के हित में है और आर्थिक विकास के लाभ तेजी से गरीबों तक पहुंच रहे हैं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि राज्य की निर्वाचित गठबंधन सरकार ने पिछले तीन वर्षों में खासतौर पर बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार अवसर जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किए।

केंद्र सरकार द्वारा उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता की चर्चा करते हुए श्री बेग ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की आर्थिक और सामग्री संबंधी मदद के कारण ही अपने लक्ष्य पूरे कर पाई। उन्होंने कहा कि सुशासन और संतुलित आर्थिक विकास के कारण राज्य में शांति स्थापित हुई और उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई। ❑

IAS R.D. & R.S. PCS

A Navodaya Institute for Civil Services Exams

(Hindi & English Medium)

भूगोल

द्वारा

सुमन कुमार

• इतिहास • सामान्य अध्ययन
• दर्शनशास्त्र • फांउडेशन कोर्स

Special Features :

- 100% पाठ्यक्रम को 400 घंटे का क्लास रुम अध्यापन के साथ समापन की गारंटी तथा ज्ञान से लेखन तक का संपूर्ण मार्गदर्शन।
- पूर्णतः अद्यतन और परिमार्जित कम्प्यूटरीकृत अध्ययन सामग्री की उपलब्धता।
- तकनीकी रूप से दक्ष संरचनात्मक सुविधाओं के साथ पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रशिक्षण केन्द्र।
- मानचित्र अध्ययन के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था।
- छात्रावास सुविधा उपलब्ध।

With Record Success Ratio in IAS/PCS

विशेषीकृत एंव गुणात्मक मार्गदर्शन, आगामी सत्रः **15 Nov.** से

VENUE : 2615 (BASEMENT), HUDSON LINE, KINGSWAY CAMP, DELHI - 9
PH. : 011-27460104, 9350255514, 9899206576, 30990432.

YH/10/5/12

IAS 2005-06
ADMISSION NOTICE

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

DREAM INDIA Group

GEOGRAPHY
by Prof. Majid Husain

OCT. 2005 (PT-CUM-MAIN)
REGISTRATION OPEN

समाजशास्त्र
by Dr. S.S. Pandey

MAINS : 8 अगस्त,05
PT-CUM-MAINS : 8 जून,06

94 CLEARED PT, 2005
(Till latest information)

OUR TOPPERS
4th TOPPER THE VERY 1st YEAR
6th TOPPER IN 2002
3rd & 4th TOPPERS in 2003
4 IAS, 6 IPS & more than 8 In Allied In 2004

OUR HIGHEST
Eco.-341;Geog.-362;Socio.-325;
G.S.-361; Essay-146;Inter.-240

GEN. STUDIES
by Dr. Ramesh Singh
"The expert with the Golden touch"

ECO. + POLITY	: 16-22 AUG. (6 Hrs.Per day)
SC. & TECH.	: 23-30 AUG. (2Hrs. Per day)
I. R. + FOR. POLICY	: 31 AUG- 6SEPT. (6 Hrs.Per day)
HIST. + NATIONAL	: 7-15 SEPT. (6 Hrs.Per day)
GEOGRAPHY	: 16-19 SEPT. (6 Hrs.Per day)
STAS. bY Dr. S. S. Pandey	: 23-30 AUG.(2Hrs. Per day)

(NO CROWD! ONLY 35 STUDENTS EACH BATCH)

IMPROVEMENT PROGRAMME
10 Meetings every 5th day of Answer Writing & Analysis and your GS (Mains) is ready to fetch 350 & 350+

ESSAY
First Class on 21st Aug. (8.30 AM. - 1.30 PM)
WE GET 140+, EVERY YEAR!

Nobody improves our students! Just Nobody!
We improve students who have already taken coaching (our speciality)
Lectures, don't pay! ***LEARN DIRECTLY TO WRITE!***
Best Materials in India
(Hand-Written by Dr. Singh)
No reading at your residence! Class is enough!

CIVILS INDIA
A Quality Institute for IAS

202-203,A/12-13 ANSAL BUILDING, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09. Ph.: 27652921, 9818244224, 27601344, 9810553368

YH/10/5/07

किशमिश छंटाई की मशीन

रामदास माधवराव जगताप(51) महाराष्ट्र के नासिक जिले के जोपुल गांव में रहते है। उनके पिता सुतार (बढ़ई) थे, लेकिन रामदास को बढ़ईगिरी में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने 1969-1970 में अपना खुद का वेल्डिंग कारखाना लगाया। वे कृषि यंत्र, बैलगाड़ी और इसी तरह के अन्य उपकरण बनाते हैं। हालांकि वह स्वयं 11वीं तक ही पढ़े हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। उनके बड़े पुत्र ने अकार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है और अब एक विद्यालय में शिक्षक हैं। दो अन्य पुत्र रासायनिक और यांत्रिकी इंजीनियर हैं। सबसे छोटा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।

प्रारंभ

रामदास महाराष्ट्र के नासिक जिले के निवासी हैं। नासिक अंगूर उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। कुछ वर्षों पहले कुछ किसानों ने उनसे सूखे अंगूरों से डंठल अलग करने और किशमिश की छंटाई के लिए एक मशीन तैयार करने का अनुरोध किया। उस समय तक यह काम ज्यादातर हाथ से किया जाता था।

किशमिश का वर्गीकरण उनके आकार के अनुसार किया जाता है जिससे निर्यात में सुविधा हो। किशमिश के उत्पादन के लिए, अंगूर के बगीचों से अंगूरों के गुच्छे, किशमिश उत्पादक घरों में लाए जाते हैं। वहां किशमिश बनाई जाती है। इसके अनुसार उनका प्रसंस्करण किया जाता है। मुख्य रूप से उनके दो वर्ग होते हैं। एक है 'हिरवा' जो हरे रंग की होती है, दूसरा -पिवला जो पीले रंग का होता है। निर्यात के लिए हिरवा को प्राथमिकता दी जाती है जबकि पिवला को घरेलू बाजार में बेचा जाता है।

इन किशमिशों का आगे और प्रसंस्करण होता है अर्थात उनकी सफाई की जाती है, कचरा हटाया जाता है और आकार के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाता है। परंपरा के अनुसार यह काम महिलाएं अपने हाथों से करती थीं। उनको न्यूनतम निर्धारित वेतन मिलता था और जितना वे अपनी नजरों से देख पाती थीं, उसी हिसाब से उनको अलग-अलग वर्गों में बांट पाती थी। रामदास ने वर्गीकरण (ग्रेडिंग) के लिए दो वर्ष तक थ्रेशर के सिद्धांत पर काम किया, लेकिन उससे काम नहीं बना। इसका मुख्य कारण अनाज और किशमिश तथा उनके कचरों में भार का अंतर था। किशमिश के कचरे का वजन काफी कम होता है। अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उन्होंने 1993 में एक मशीन तैयार की, जिससे अंगूर उत्पादकों की आवश्यकता की पूर्ति होती थी।

परंतु उसमें कई खामिया थी, जिन्हें दूर करने में थोड़ा समय लगा। पहली डिजाइन में एक खामी तो यह थी कि मशीन में ज्यादा कुटाई के कारण उसमे से शक्कर का तत्व काफी कम हो जाता था। कुटाई के बाद जब किशमिश को शीतगृहों में रखा जाता था तो उनमें से शक्कर का तत्व रिस कर बाहर निकल जाता था। इससे किशमिश की गुणवत्ता पर असर पड़ता था। रामदास ने अपनी मशीन में कुछ परिवर्तन किए और शीघ्र ही एक संशोधित डिजाइन तैयार कर ली। एक और समस्या यह थी कि ब्लोअर कचरे के साथ किशमिश को भी उड़ा देता था। अत: उन्होंने मशीन के इम्पेलर का व्यास कम कर दिया जिससे उसमें बनने वाले शून्य की तीव्रता कम हो गई। अब कचरे के साथ किशमिश नहीं जा पाते थे। धीरे-धीरे किसानों तक इस मशीन की जानकारी पहुंची। अच्छी तरह देखभाल के बाद उन्हें लगा कि मशीन को काम में लाना सरल है और कार्य क्षम भी। इसके बाद मशीन के लिए आर्डर मिलने लगे।

नवोन्मेष

यह एक ऐसी एकल इकाई है जो कचरे और गर्द को हटा कर आकार के अनुरूप किशमिशों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट देती है। मशीन में तीन मोटर और तीन छलनियां, ब्लोअर, बेल्ट और पुली(घिर्री) की यंत्र रचना के अलावा रबर ब्रूश भी लगाया गया है।

अलग-अलग अंगूरों को 15 से 20 दिनों तक सुखाया जाता है और उसके बाद उन्हें रसायन से उपचारित किया जाता है ताकि उनको भलीभांति सुखाया जा सके, साथ ही कीड़े-मकोड़ों से बचाया जा सके। सूखे अंगूरों को एक फीडर के जरिये मशीन में डाला जाता है। फीडर में एक रोटर और रबर ब्रूश लगा होता है। तीन अश्वशक्ति की एक मोटर से इस यंत्र को चलाया जाता है। ब्रूश से सूखे अंगूरों पर प्रहार कर छोटे-छोटे डंठलों को उनसे अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन सूखे अंगूरों को ब्लोअर से होकर गुजारा जाता है। इसके लिए उच्च दाब के वायु प्रवाह की मदद ली जाती है। ब्लोअर को 2 अश्वशक्ति की एक मोटर से चलाया जाता है। सूखे अंगूरों की अब सफाई की जाती है और तीनों छलनियों में लगे एक वायब्रेटर के जरिये हिला कर उनका वर्गीकरण किया जाता है। प्रत्येक छलनी पर एकत्रित सूखे अंगूरों

को अलग-अलग चैंबरों में भर कर उनके विशिष्ट वर्ग में रखा जाता है। और अंत में, किशमिश बनाने के लिए इनका प्रसंस्करण किया जाता है। मशीन किशमिशों को तीन आकार-बड़ी मध्यम और छोटे आकार में विभाजित कर देती है।

इस मशीन के दो मॉडल हैं - छोटे मॉडल से 12 घंटों में दो टन किशमिश की छंटाई होता है, जबकि बड़ी मशीन से उतने ही समय में चार टन किशमिश की श्रेणीवार छंटाई होती है। छोटी मशीन का वजन 600 किलोग्राम है और बड़ी का 1,000 किलोग्राम। छोटी वाली की कीमत 30 हजार रुपये है जबकि बड़ी का मूल्य 45 हजार रुपये।

लाभ

मशीन के इस्तेमाल से धूल और कचरा हटाने और आकार के अनुसार किशमिश के वर्गीकरण में समय की काफी बचत होती है। इससे किसान के लिए समूची प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है। किशमिशों छंटाई के बाद किसान देखकर उसकी गुणवत्ता का जायजा लेता है। इस यंत्र से ब्लोअर से उड़ने वाली धूल से आपरेटर का बचाव भी होता है। मशीन के प्रयोग से हाथ से एक-एक किशमिश को छांटने, साफ करने और उनको अलग करने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है।

इसकी तुलना में जो अन्य मशीन है, वह अयात करनी होती है। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये पड़ती है। यह आयातित मशीन अंगूरों को रंग, आकार और बनावट के अनुसार छांटती है। लेकिन लागत अंतर का लाभ जगताप की मशीन को मिलता है। केवल 45 हजार रुपये की यह मशीन आयातित मशीन के मुकाबले संतोषप्रद परिणाम देती है। यह तथ्य भविष्य में उपभोक्ता के लिए मशीन का चुनाव करने में काफी निर्णायक हो सकता है।

वर्तमान स्थिति

रामदास जगताप इस मशीन पर 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं और सतारा, सांगली और शोलापुर क्षेत्र के किसानों को बेच भी रहे हैं। महाराष्ट्र के इन जिलों के अलावा कर्नाटक के बीजापुर जिले में भी जगताप की मशीन की मांग है। एक इकाई 'रंगोली' किशमिश के कारखाने में भी लगाई गई है। यह कारखाना अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा निर्यातक है। अब तक रामदास ने 25-30 छोटी मशीनें और 40-50 बड़ी मशीनें बेची हैं। सभी प्रमुख अंगूर उत्पादक क्षेत्रों में मशीनों की लोकप्रियता की अच्छी संभावनाएं हैं। क्षेत्र के अनेक प्रमुख अंगूर किसानों ने रामदास से ये मशीनें खरीदी है।

आमतौर पर जब किसान मशीन के लिए आर्डर देते हैं तो वे कुछ भुगतान बयाने के तौर पर करते हैं और बाकी राशि का भुगतान मशीन तैयार होने के बाद किया जाता है। रामदास ने कुछेक मजदूरों को भी काम पर रखा है। जब उनको पर्याप्त आर्डर मिलते हैं तो ज्यादा मजदूर भी रख लेते है। इन मशीनों का निर्माण वे नवंबर से जनवरी के बीच करते हैं और उनकी बिक्री फरवरी से अप्रैल के बीच होती है क्योंकि इसकी मांग मौसमी है।

इस मशीन को अचार बनाने हेतु आम या अन्य फलों के वर्गीकरण के लिए भी अपनाया जा सकता है। रामदास की मशीन को पेटेंट कराने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि इसी तरह की मशीनें पहले से ही बाजार में उपलब्ध थीं।

छंटाई मशीन में रामदास द्वारा किए गए नये परिवर्तनों की तीन अन्य निर्माताओं ने नकल कर अपनी मशीनें बना ली और उन्हें महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के प्रमुख अंगूर उत्पादक क्षेत्रों में बेच रहे हैं। लेकिन इन निर्माताओं को भलीभांति अहसास है कि मौलिक मशीन का विकास तो जगताप ने ही किया था। उसकी मशीन में कुछ और भी विशेषताएं हैं, जिन्हें किसान उपयोगी पाते हैं। एक बार बिकने के बाद मशीन को पेटेंट नहीं कराया जा सकता क्योंकि माना जाता है कि प्रौद्योगिकी तो सार्वजनिक हो चुकी है।

अंगूर उद्योग के प्रति अन्य योगदान और अर्जित सराहना

रामदास ने एक और मशीन बनाई है, जिससे सूखे अंगूरों को धोया जाता है। इसके अलावा उन्होंने अंगूर पैकेजिंग उद्योग के लिए एक कन्वेयर बेल्ट भी विकसित की है। प्राथमिक घर से निर्यात के लिए पैकिंग हाल में जाने में इस बेल्ट के उपयोग से काफी आसानी होती है। अंगूर निर्यातकों के लिए यह काफी उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि पैकेजिंग का क्षेत्र आमतौर पर थोड़ा छोटा ही होता है। इस बेल्ट के इस्तेमाल से अनेक बक्सों को शीघ्रता से पैक किया सकता है। इससे मजदूरी में बचत होती है। इससे सीख लेकर अनेक अंगूर निर्यातकों ने अपनी-अपनी इकाइयों में कन्वेयर बेल्ट लगा लिए हैं।

अंगूर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रामदास जगताप को 23 दिसंबर, 2002 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ने सम्मानित किया। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जन्मशती के अवसर किसान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र अंगूर उत्पादक संघ, पुणे ने भी अंगूर प्रसंस्करण के क्षेत्र में जगताप के योगदान को मान्यता दी है। रामदास जगताप को स्थानीय लोगों से भी अपने नव परिवर्तन के लिए पुरस्कार मिले हैं। ❑

अगर पाठक ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हों, जिसने सृजनात्मक तरीके से स्थानीय प्रौद्योगिकी का समाधान किया हो अथवा जीविका के किसी क्षेत्र से संबंधित पारंपरिक ज्ञान रखने वाला हो तो कृपया हमें अथवा एनसी (एस एंड डी) एनआईएफ, पोस्ट बॉक्स-15051, अंबावाडी, अहमदाबाद- 380015 पर अथवा ई-मेल द्वारा info@nifindia.org पर विवरण भेजें।

आयुर्वेद गांव वल्कि

○ सव्यसाची मल्लिक

बांग्ला भाषा में जादू का पर्यायवाची शब्द वल्कि कहलाता है। पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले में वल्कि नाम का एक ऐसा गांव है, जहां हाल के वर्षों में लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा उन दृढ़ निश्चयी गांव वालों के कारण हो सका है। जिन्होंने भारत के प्राचीन और पारंपरिक आंचलिक जड़ी-बूटियों के जनाधार का आश्रय लिया। वैदिक काल के पहले से ही, इस देश के चिकित्सक विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भारत की जैव विविधता से पुष्पित-पल्वित पादप प्रजातियों पर निर्भर रहते आए हैं। हिमालय की पहाड़ियों, पश्चिमी घाट और दक्षिणी पठार जैसे प्राकृतिक संपदा से संपन्न इन क्षेत्रों में ज्ञात और अज्ञात अनेकों औषधीय और उनके तत्वों के लाभकारी गुणों से भलीभांति परिचित थे। चरक और सुश्रुत जैसे प्राचीन चिकित्सक तो इन पौधों और जड़ी-बूटियों के उपयोग के कारण किंवदती बने हुए हैं। परंपरा से प्रसिद्ध भारत की चिकित्सकीय प्रणाली, आयुर्वेद, इन्ही औषधीय गुणों वाली चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में हमारे पूर्वजों के गहन ज्ञान पर आधारित थी। वल्कि गांव धरती के उस टुकड़े पर बसा है जिसे भूगोल की पुस्तकों में एक ऐसा अर्द्धशुष्क लहरदार समतल क्षेत्र कहा जाता है, जो जमीन के कटने से बनता है। अतएव, यह कोई आश्चर्य की बात नही है कि यहां पानी का अभाव है। समूचे क्षेत्र में खेतों की सिचाई के लिए खोदे गए गहरे नलकूपों के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। इस वजह से भूमिगत जल का स्तर और भी नीचे चला गया है, और इससे फसलों को लाभ होने के बजाय नुकसान ही हो रहा है। इस हताश स्थिति से मुकाबला करने के लिए बीडीओ के स्तर पर राज्य सरकार की सहायता और नाबार्ड द्वारा दी गई तकनीकी ज्ञान से वर्ष 2000 के आस-पास वाटरशेड परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का केवल एक ही उद्देश्य था कि वर्षा के जल को तालाबों और पोखरों में जमा किया जाए। भूतल पर पानी रोकने के लिए परिरेखा कान्टूर वाले बांध, बरसाती नाले में पत्थर लगाकर उसे सुदृढ़ करने तथा चेक पानी रोकने वाले छोटे-छोटे बांध बनाने का काम भी शुरू किया गया। गांव के मौजूदा तालाबों, झीलों की गाद निकालने और सफाई के साथ नए जलीय निर्माण कार्यों के लिए गांव के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के स्वैच्छिक सहायता समूहों को काम पर लगाया गया। दरअसल, वल्कि ने परियोजना का अनूठा अवसर प्रदान किया। इस तरह की वाटरशेड परियोजना हर उस जगह लगायी जा सकती है जहां जमीन सूखी है, और वर्षा बहुत कम होती है। वल्कि के आसपास के इलाके इसी तरह के हैं। अपनी पास पड़ोस के हल्कों को देखते वल्कि एक ऊंचे मैदान पर बसा है। अत: वर्षा का जल बहकर नीचे की ओर चला जाता है और पड़ोसी गांव की जमीनों में इकट्ठा हो जाता है तथा वल्कि को वर्षा के जल से मिलने वाले लाभों से वंचित कर देता है। इसको रोकने के लिए इस सहस्त्रादी के प्रारंभ में ही बुनियादी तौर पर वाटरशेड परियोजना शुरू की गई। गांव के लोगों के बीच से ही विभिन्न स्वयं सेवको के समूह तैयार किए गए। महिलाओं को भी इनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रत्येक समूह में 5-20 लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते है। कुछ सर्वेक्षण का काम करते हैं, तो कुछ गांव के लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वयं ही अपनी जीविका खोजने का पाठ पढ़ाते है। परियोजना ने स्थानीय लोगों को वर्ष भर नियमित आय प्रदान करने में भी मदद की है। बरसात के मौसम में कच्चे बांधों के निर्माण बरसाती नालों की पानी के रिसाव को रोकने के लिए पत्थर लगाने, तलाबों और निचले इलाकों की साफ-सफाई आदि के काम में गांव वाले व्यस्त रहते है और उन्हें निश्चित राशि भी मिलती है। वर्ष के अन्य मौसम में उन परिपक्व वृक्षों की बिक्री पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया है, जो स्वयं सेवकों के समूहों ने पहले लगाए थे। इन समूहों ने तालाबों में मछली पालन भी किया है, वृक्षों के फलों और पौधघरों में पौधों की रक्षा की है और औषधीय पौधे उगाए हैं। पहले गांव वाले आसपास के जंगलों से जड़ीबूटियों को एकत्रित कर उन्हें गांव से गुजरने वाले वैद्यों को बेचा करते थे। वे यह काम शौकिया तौर पर करते थे। इस बात की जानकारी मिलने पर जयशंकर सरकार नाम के औषधीय पौधों के जाने माने वाले व्यापारी ने स्वयं आगे बढ़कर वल्कि के लोगों से संपर्क बढ़ाया। शुरू-शुरू में तो वे नियमित रूप से गांव वालों द्वारा एकत्रित सभी जड़ी-बूटियां खरीद लिया करते थे। बाद में, उन्होंने वाटरशेड परियोजना की संचालन समिति को उकसाया कि जमीन खरीद कर नियमित रूप से औषधीय पौधों की खेती की जाए, तो गांव वालों के लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने ही गांव में और आसपास के क्षेत्रों में परती जमीन खरीदने के लिए धन मुहैया कराया। परती जमीन की इन पट्टियों में स्वैच्छिक समूहों ने हाल के दिनों में औषधीय पौधों की खेती शुरू की है। वे इनमें 'सर्पगंधा', अयपन और 'स्टीविया' उगा रहे है। इन पौधों के बीज और तकनीक जानकारी भी श्री सरकार ही उपलब्ध करा रहे हैं।

सर्पगंधा अर्थात गलकिया सर्पेन्टाइना, रक्त चाप के नियंत्रण के लिए अत्यंत उपयोगी औषधि मानी जाती है। अयपन को मूत्र विकारों के इलाज में और स्टीविया को हृदय संबंधी बीमारियों के लिए लाभकारी माना गया है। इस छोटे से उद्यम के परिवेक्षक श्री कल्याण मुकर्जी के अनुसार इन दिनों बाजार में इन जड़ी-बूटियों की भारी मांग है। श्री सरकार ने जड़ी-बूटियों के समूचे उत्पाद को खरीदने की जिम्मेदारी ली है। वल्कि निवासी अब तो इन पौधों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहे है। उन्हें उम्मीद है कि इन जड़ी बूटियों के विक्रय से अच्छी आमदनी होगी। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में जीवन बीमा

○ रवीन्द्र सिंह

वर्ष 1999 तक जीवन बीमा निगम एक एकाधिकार उपयोग था परंतु उपभोक्ता को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सुविधाओं और विलंबित दावों, जटिल प्रक्रिया तथा अन्य अड़चनों का अनुभव किया गया तथा इस प्रकार बीमा उद्योग जो विक्रेता बाजार के रूप में भारत वर्ष में पूर्ण एकाधिकार के रूप में कार्य कर रहे थे अचानक क्रेता बाजार के रूप में परिवर्तित हो गया।

सरकार ने 1998 के बजट भाषण में अपनी बीमा-उद्योग को निजी क्षेत्र हेतु खोल देने तथा सांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के संबंध में घोषणा की। जिसके अनुसार 5 दिसंबर, 1998 को एक बिल संसद में रखा गया, बिल में बीमा अधिनियम 1938, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956 तथा साधारण बीमा अधिनियम 1972 में आवश्यक संशोधनों हेतु तीन अनुसूचियां सम्मिलित की गईं, बिल के पक्ष में तर्क रखते हुए तत्कालीन वित्तमंत्री ने कहा कि "भारतीय नागरिकों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने एवं अवसंरचना की योजनाओं हेतु दीर्घकालीन अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सांविधानिक प्राधिकरण की स्थापना करना आवश्यक है तथा बिल को वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति को विवेचना व सुझावों हेतु भेजा गया। समिति ने अन्य कई सुझावों और संशोधनों के साथ बिल का शीर्षक "बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण" करने का सुझाव दिया अंततः संसद में बिल पारित हुआ और 5 जनवरी, 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 अस्तित्व में आया जो 19 अप्रैल, 2000 से प्रभावी हुआ।

एक उदार अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका होती है। आर्थिक विकास के प्रयासों में जीवन बीमा का क्षेत्र महत्वपूर्ण बीमा उत्पाद बीमाकर्ता तथा बीमित के मध्य एक संविदा पर निर्भर होता है तथा बीमा पालिसी क्रय करने वाले की आर्थिक रूप से हानि होने पर जो विशेष जोखिम होती है उससे उसकी रक्षा करती है।

बीमा के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त होने के पश्चात ग्राहकों की प्रकृति प्रयोगात्मक हुई है। उदारीकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को उपलब्ध सेवा तथा विकल्प का विकास करना था। भारत में निजी कंपनियों को आए हुए मात्र चार वर्ष ही हुए है और उपभोक्ता आज शीर्ष पर हैं बीमा बाजार विक्रेता बाजार से क्रेता बाजार में परिवर्तित हो चुका है। उदारीकरण लागू होने के पश्चात जब भारतीय बीमा बाजार के दरवाजे निजी तथा विदेशी कंपनियों के लिए खोले गए, तब यदि कोई यह कहता है कि चार वर्षों में निजी कंपनियां देश में बीस लाख बीमा पॉलिसी का विक्रय करने में सफल हो जाएंगी तो शायद किसी को यह विश्वास न होता। परंतु धीरे-धीरे निजी बीमा कंपनियों ने उस शक को पीछे कर अपने लिए जगह बनाई है।

आज निजी जीवन बीमा कंपनी की कार्यशैली तथा व्यापारिक नीतियों के कारण उनका आगाज ठीक रहा है। इस अल्पावधि में उन्होंने भारतीय बीमा बाजार में अपनी हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से भी अधिक कर ली है और यह निरंतर विस्तार का संकेत दे रहा है। घोर प्रतिस्पर्धा के इस युग में उत्पादों की भीड़ ने उपभोक्ताओं को न केवल विकल्प प्रदान किए है बल्कि इसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं में तीव्र वृद्धि भी हुई है।

ग्राहकों की अपेक्षाएं

आज उपभोक्ता अधिक जानकार, ज्ञानवान हैं। कई बीमा कंपनियों की भीड़ के कारण ग्राहकों के समक्ष एक ही वस्तु कई रूप में होती है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता के पास कई विकल्प होती है। बीमा उत्पादों की व्यूह रचना का सामना करने वाला ग्राहक अब अपनी पॉलिसी को तत्काल सुपुर्दगी, व्यक्तिगत ध्यान, कस्टमाईज्ड प्रस्ताव तथा उनकी पॉलिसी के संबंध में सुगमता से जानकारी, भुगतान तंत्र की बहुलता तथा शिकायतों पर तुरंत प्रभाव के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ अपेक्षा रखता है। एक विशेषता और यह है की, यह सब सुविधाएं, सेवाएं ग्राहक निशुल्क प्राप्त करने की भी अपेक्षा रखता है। वर्तमान समय में उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। आज की मौजूदा स्थिति में ग्राहकों की संतुष्टि वित्तीय सेवा क्षेत्र में विकास करने के लिए प्राथमिक बाध्यताओं में एक है। सेवा की गुणवत्ता ही विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य का एक मुख्य विभेदक हो चुका है।

बीमा कंपनियों की परिवर्तित कार्यशैली

उपभोक्ताओं की रुचि तथा बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार चलने के लिए भारत की अधिकतर बीमा कंपनियां उन्नत सीआरएम टूल्स को अपना रही हैं जो कि उन्हें ग्राहकों की गतिविधियों का अनुवीक्षण करने में मदद कर रही हैं।

सीआरएम टूल्स के माध्यम से कंपनियां अपने ग्राहकों के विषय में विवरण प्राप्त करने,

अच्छे उत्पादों की अभिकल्पना करने, अपनी सेवाओं का विकास करने तथा प्रचालन की लागत को कम करने की मंजूरी देते हैं। प्रतिस्पर्धा के वर्तमान समय में बीमा कंपनियों के द्वारा सुधारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। परंतु एलआईसी ने अपनी कार्य प्रणाली में उपभोक्ता को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु सी.आर.एम. टूल्स के अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को बेहतर एवं शीघ्र सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी का विविध प्रयोग किया है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ने स्वयं को भी अन्य बीमा कंपनियों से अग्रणी रखने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में निम्न परिवर्तन किए हैं।

फंड एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम

इस प्रोग्राम के माध्यम से एलआईसी के सभी 2048 शाखाओं में "इन हाऊस" के रूप में प्रोग्राम उपलब्ध है जिससे कि पालिसी सेवा से संबंधित सभी पहलू को शामिल करके ग्राहकों को तुरंत कम्प्यूटरीकृत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके।

नेटवर्किंग

इस प्रोग्राम के अंतर्गत एलआईसी के विशाल एरिया नेटवर्क में 100 प्रभागीय केंद्रों को शामिल किया गया है, जो एक मेट्रो एरिया नेटवर्क के माध्यम से लगभग 1805 शाखाओं का एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं।

आनलाईन प्रीमियम भुगतान

एलआईसी द्वारा कुछ बैंकों एवं सविर्स प्रोवाइडरों के साथ विशेष अनुबंध स्थापित हुए है, तथा अपनी कार्य प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन करते हुए आनलाइन प्रीमियम संग्रह की सुविधा आरंभ की है। उपभोक्ता अपनी पालसी के संबंध में दूरभाष द्वारा ही समग्र जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इंटरनेट पहल

वर्तमान समय में एलआइसी बेवसाइट के माध्यम से कई तरह की आसान सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, एलआईसी की वेबसाइट है:-www L.I.C. india.com जिसमें उपभोक्ता की जानकारी हेतु उपलब्ध है

- उत्पाद संबंधी को जानकारी
- प्रीमियम की गणना संबंधी सेवाएं
- आयकर संबंधी सेवाएं
- आयकर संबंधी सेवाओं के लिंक्स
- सहायक कंपनियों के लिंक्स

किऑस्क

अपनी उपभोक्ता सेवा को और दुरूस्त करते हुए एलआईसी ने अपना पहला इन्फोसेंटर स्थापित किया, इसके उपरांत अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली तथा पुणे जैसे सात अन्य शहरों में भी ऐसे सेंटरों की स्थापना की है। भविष्य में अन्य शहरों में भी इस योजना को अग्रसारित करने की योजना है। सभी सेंटर अतिआधुनिक टेक्नोलाजी के अलावा प्रशिक्षित कर्मचारियों से पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं जिससे कि उपभोक्ता को हर प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जा सके तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ने कार्य निष्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया है तथा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर अपनी कार्य प्रणाली में कई परिवर्तन किए है।

परिवर्तित कार्यशैली के परिणाम

वर्ष 2002-03 में देश के जीवन बीमा कारोबार में मात्र 0.31 हिस्सा रखने वाली ओम कोटक लाइफ इंश्योरेन्स ने उपर्युक्त वर्ष में 35 करोड़ रुपये की प्रथम प्रीमियम आय की प्राप्ति की थी परंतु वर्ष 2003-04 में कंपनी ने 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा तथा कंपनी ने इसे आसानी से प्राप्त कर लिया। टाटा ए.आई.जी. की प्रीमियम आय में 2002-03 के दौरान 239 फीसदी की वृद्धि हुई। निजी जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम आमदनी में पिछले 2-3 वर्षों से औसतन 100-150 फीसदी की दर से सालाना वृद्धि हो रही है। बिरला सन लाइफ ने पिछले वर्ष 1.80 से अधिक पालिसियों की बिक्री, जो की इसके पिछले वर्ष की 75,000 पालिसियों से कहीं अधिक है। इस प्रकार मैक्स न्यूयार्क ने अभी तक 11,000 करोड़ रुपये की 1.46 पालिसियां बेची जबकि 31 मार्च, 2003 तक कंपनी 5,420 करोड़ रुपये की 77,500 पालिसियां बेच पाई थी। सबसे बेहतर प्रदर्शन आईसीआईसीआई का रहा, इसकी 31 मार्च, 2004 तक 7.80 लाख पालिसियों का विक्रय किया गया तथा कंपनी ने 16,000 करोड़ का बीमा कवर भी प्रदान किया।

जीवन बीमा उद्योग जुलाई, 2004 के दौरान 1,86,605.46 लाख प्रीमियम का नया व्यवसाय किया। चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान कुल एकत्रित प्रीमियम 5,52,515.95 लाख की थी, जिसमें भारतीय

एलआईसी पॉलिसीधारकों को विशेष बोनस

वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वर्ण जंयती वर्ष पर इसके पालिसीधारकों को प्रत्येक हजार रुपये की बीमित रकम पर पचास रुपये का विशेष बोनस देने की घोषणा की है। 31 मार्च, 1981 से पहले बीमा कराने वालों को प्रत्येक हजार रुपये की बीमित रकम पर 50 रुपये और एक अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 2001 के मध्य बीमा कराने वाले वालों को 45 रुपये से 6 रुपये तक अतिरिक्त विशेष बोनस दिया जाएगा।

एक अप्रैल, 2001 के बाद बीमा कराने वालों को प्रत्येक हजार रुपये की बीमित रकम पर पांच रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बोनस पर निगम को 2000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करना होगा। इससे देशभर में एलआईसी का 16.82 करोड़ पॉलिसीधारक लाभान्वित होंगे। श्री चिदंबरम ने निगम के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि यह 90 दावों का प्रति मिनट निबटारा करती है। बीमा गोल्ड पॉलिसी पर अपने विचार रखते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी के माध्यम से ग्राहक किस्तों में अपने रिटर्न वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत यदि पॉलिसीधारक दो साल तक प्रीमियम नहीं दे पाता है तो भी बीमा चलता रहेगा।

पहले वर्ष का प्रीमियम-जुलाई 2004

कंपनी	प्रीमियम यू/डब्ल्यू		प्रीमियम का प्रतिशत	पालिसियों की संख्या		पालिसियों की संख्या का प्रतिशत	समूहों कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या (जुलाई तक)		समूह कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए व्यक्ति की संख्या का प्रतिशत
	जुलाई	जुलाई तक	जुलाई तक	जुलाई	जुलाई तक	जुलाई तक	जुलाई	जुलाई तक	जुलाई तक
बजाज एलियांज	**4092.12**	**10675.20**	**1.93**	**20634**	**53427**	**0.89**	**27754**	**49066**	**2.73**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	1522.80	3559.45		1697	4247				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	256.99	7020.22		18933	489155				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम									
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	10.33	95.52		4	25		27754	49066	
आईएनजी वैश्य	**762.05**		**0.35**	**8913**	**26803**	**0.45**	**339**	**5898**	**0.33**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	0.19	32.44		27	4771				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	708.33	1778.20		8885	22026				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	53.01	95.26			1		123	255	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम		15.57		1	5		216	5643	
एएमपी सनबार	**372.04**	**1302.03**	**0.24**	**2696**	**9616**	**0.16**	**2597**	**17956**	**1.00**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	145.00	529.92		345	1153				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	173.85	673.57		2338	8438				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	18.35	20.85		1	1		190	190	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	34.83	77.69		12	24		2407	17766	
एसबीआई लाइफ	**3357.41**	**844460.42**	**1.53**	**9296**	**26515**	**0.44**	**73737**	**170035**	**9.47**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	705.89	1986.43		418	1144				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	508.85	1573.69		8468	24759				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	1046.04	3257.56		1	2		13381	40165	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	1096.63	1642.74		409	610		60356	129870	
टाटा एआईजी	**2556.48**	**7551.74**	**1.37**	**17830**	**64420**	**1.08**	**31880**	**113730**	**6.33**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम					64344				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	1688.16	5704.18		17797					
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	47.47	198.62			76		6602	29094	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	820.85	1648.94		33			25278	84636	
एसडीएफसी स्टैंडर्ड	**2347.73**	**7658.62**	**1.39**	**17003**	**43755**	**0.73**	**17723**	**52045**	**2.90**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	642.44	2104.99		1655	4632				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	1566.72	5147.12		15336	39066				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	79.45	245.57		11	53		17243	44216	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	59.12	160.94		1	4		480	7829	
आईसीआई प्रोडेन्सल	**8993.41**	**31173.97**	**5.64**	**43447**	**142814**	**2.39**	**705**	**17956**	**0.37**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	1514.21	5863.79		1011	3565				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	7171.05	21985.78		42429	139204				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	4.58	11.59		2	5		192	850	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	303.57	3312.81		5	40		513	5840	
बिरला सन लाइफ	**4229.52**	**13591.67**	**2.46**	**12739**	**36411**	**0.61**	**7039**	**14256**	**0.79**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	136.49	430.59		2450	6450				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	3770.42	10616.21		10280	29926				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	38.76	138.18					314	1121	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	283.85	2406.70		9	25		6725	13135	
अवीवा	**1283.15**	**452.67**	**0.82**	**6354**	**23816**	**0.40**	**10619**	**39076**	**2.18**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	15.66	147.90		37	142				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	1236.29	4308.27		6316	23662				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	1.92	4.39			1		14	43	
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	29.28	82.11		1	11		10604	39033	
कोटेक महेन्द्रा ओल्ड मैच्यूल	**829.02**	**2547.54**	**0.46**	**3941**	**11704**	**0.20**	**779**	**27197**	**1.51**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	270.33	560.59		169	357				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	556.31	1522.11		3770	11340				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम									
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	2.38	464.83		2	7		779	27197	
मैक्स न्यू यार्क	**1863.72**	**4896.90**	**0.89**	**19239**	**50126**	**0.84**	**3843**	**31030**	**1.73**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	25.67	91.57		42	84				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	1825.71	4752.18		19188	50015				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम									
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	12.34	53.15		9	27		3843	31030	
मैट लाईफ	**370.07**	**1174.48**	**0.21**	**2621**	**7325**	**0.12**	**11874**	**78883**	**4.39**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	17.76	38.71		33	91				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	267.45	822.30		2580	7204				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम									
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम	84.86	313.47		8	30		11874	78883	
एल.आई.सी.	**155546.73**	**457019.23**	**82.72**	**1857036**	**5488955**	**91.70**	**04097**	**1189843**	**66.26**
इन्डीवीजूवल सिंगल प्रीमियम	36288.57	65897.98		90537	159170				
इन्डीवीजूवल नान-सिंगल प्रीमियम	90836.93	233740.53		1765413	5326070				
ग्रुप सिंगल प्रीमियम	28421.23	117380.72		1086	3715				
ग्रुप नान सिंगल प्रीमियम							04097	1189843	
कुल	**186605.46**	**552515.95**	**100.00**	**2021749**	**5985687**	**100.00**	**512985**	**1795705**	**100.00**

स्रोत :- आई.आर.डी.ए. जर्नल द्वारा संकलित

जीवन बीमा निगम ने 4,57,019.23 लाख की प्रीमियम राशि प्राप्त की, तथा निगम की बाजार की हिस्सेदारी 82.72 थी, जबकि निजी जीवन बीमा क्षेत्र की कंपनी जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल, तथा बिरला सन् लाईफ ने 31,173.97 लाख का प्रीमियम, बाजार की हिस्सेदारी 5.64 तथा 13,591.67 लाख का प्रीमियम तथा बाजार की हिस्सेदारी 2.46 प्रतिशत क्रमश: थी। यदि वर्ष 2004 की प्रथम छमाही के आकड़ों का अवलोकन करे तो उन आकड़ों से भी ज्ञात होता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है तथा निजी बीमा कंपनियों के व्यवसाय से उसके स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निजी तथा सरकारी बीमा कंपनियों की कार्य प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन संलग्न चार्ट से भी कर सकते हैं।

इन्हीं आकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी निजी जीवन बीमा कंपनी ग्राहकों को अपनी ओर किस तरह आकर्षित कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इनके परिणाम इतने उत्साहजनक रहे है जबकि इनके पास वर्क फोर्स का अभाव, अनुभव अभाव, भारतीय बीमा बाजार के संबंध में संकलित आकड़ों का अभाव रहा, फिर भी इन्होंने अपनी बाजार में उपस्थिति दर्ज करायी है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी कार्यशैली परिवर्तित करने पर मजबूर कर दिया। वित्तीय वर्ष 2004-05 के शुरुआत से ही जीवन बीमा कंपनियां उत्साहवर्धक कार्य परिणाम प्रदान कर रही जो एलआईसी के साथ सभी बीमा कंपनियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात हो रहा है, जिसमें एलआईसी ने अपनी सूचना एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तित कार्य और प्रणाली के माध्यम से काफी अग्रणी रूप ले लिया है। एलआईसी के ग्राहकों के साथ कर्मचारियों का भी उत्साहवर्धन हुआ है जिसके परिणाम-स्वरूप कार्यों को समय से पहले कुशलतापूर्वक संपन्न कर लिया जाता है।

वर्ष 2004 में एलआईसी की आय (एफपीआई) का लक्ष्य 11,800 रुपये थी जबकि शुद्ध आय इससे कहीं अधिक 12,179 करोड़ रुपये रही, जिसकी वृद्धि दर 119 फीसदी रही। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता रहा है कि सभी निजी जीवन बीमा कंपनियों की संयुक्त प्रथम प्रीमियम आय से अधिक आय अकेले एलआईसी की है।

निजी जीवन बीमा कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के माहौल में काम करना पड़ रहा है। सभी निजी जीवन बीमा कंपनियां क्रमश: विस्तार का संकेत दे रही हैं परंतु भारतीय जीवन बीमा निगम को स्पर्श नहीं कर पा रही हैं जैसा कि व्यापार के आंकड़ों से ज्ञात हो रहा है। आज उपभोक्ता अपनी अपेक्षाओं को लेकर शीर्ष पर विद्यमान हैं इसलिए ग्राहकों की मनोस्थिति को समझ कर उनकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए यह आवश्यक है कि बीमा कंपनियां अपने उत्पादों एवं सेवाओं का पुर्नमूल्यांकन करें। बीमा के क्षेत्र में भविष्य के नियमन जो रास्ता तय करेंगे वह ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की बीमा कंपनियों की योग्यता पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिभूत रहेंगे। इसलिए उपभोक्ताओं के हित में मुख्य कानून परिवर्तन किए जाने की एवं कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का अनुसरण करने की आवश्यकता है:-

1. एजेंट की वर्तमान कमीशन दरों पर लगी सीमा इस व्यापार में उत्कृष्ट प्रतिभा को प्रभावित कर रही है तथा कुछ व्यावसायिकों को छोड़ कर ज्यादातर एजेंसी में आज अंशकालिक लोग हैं। अत: अधिनियम 1938 की धारा अ से 44 तक के अंतर्गत नियमों में संशोधन की आवश्यकता है, जिससे कि पूर्णकालिक व्यावसायिकों की भर्ती की जा सके।
2. बीमा कंपनियों द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के समस्त ढांचे के भीतर एजेंटों के लिए क्षतिपूर्ति योजनाओं की अभिकल्पना करने की स्वतंत्रता प्रदत्त होनी चाहिए।
3. भारत की जनसंख्या एक अरब से भी अधिक हो चुकी है इसलिए देश के उपनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावी रूप से लक्ष्य बनाकर अतिशीघ्र कुशलता बढ़ानी होगी जिससे कि सभी का जीवन बीमा प्रदत्त हो सके।
4. कुछ देशों के तुच्छ बिक्री प्रयासों तथा प्रकटीकरण के अभाव के कारण असंतुष्ट ग्राहकों के द्वारा मुकदमे के कारण जुर्माना हुआ है। ऐसी पुनरावृत्ति को भारत में रोकना होगा।
5. उदारीकरण लागू होने के पश्चात भारतीय बीमा बाजार में कई कंपनियां मैदान में हैं जिसके कारण ग्राहकों की अपेक्षाओं में तीव्रता से वृद्धि हुई है तथा जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। उद्योग को भारत के लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ाने के लिए बीमा क्षेत्र में अन्य जोखिम धारकों को साथ मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है।

उदारीकरण और वैश्वीकरण आज भारत का नारा बन गया है जिसके फलस्वरूप अनेक उपयोग, जो कल तक रिजर्व थे आज समस्त विश्व, निजी कंपनियों और औद्योगिक घरानों हेतु खोल दिए गए है। विश्व स्पर्धा के वातावरण में औद्योगिक अग्रणी राष्ट्र बनने के लिए संभवत: ऐसा करना एक अनिवार्यता बन गई थी, इस परिवर्तन के फलस्वरूप बीमा उद्योग के साथ अन्य उद्योगों के द्वार भी भारत में निजी उद्योगपतियों के लिए खोल दिए गए हैं। ❑

(लेखक कानपुर विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं)

कृपया ध्यान दें

भारतीय मनोरंजन उद्योग का तीव्र विकास हो रहा है। 'योजना' का नवंबर 2005 अंक देश के मनोरंजन परिदृश्य पर केंद्रित होगा। इस अंक में फिल्म, टीवी, रेडियो तथा मनोरंजन के पारंपरिक माध्यमों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री एस.के. अरोड़ा, प्रसार भारती के सीईओ श्री के.एस. सरमा, अभिनेत्री तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री शर्मिला टैगोर और प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री महेश भट्ट के आलेख सहित अन्य अनेक लेख होंगे। पाठक कृपया अपनी प्रति सुरक्षित करा लें।

पुनर्वास

तमिलनाडु में सिरकाज़ी से 20 किमी. पूरब मछुआरों का एक छोटा-सा गांव है पुडुकुप्पम। 60 परिवारों वाली इस बस्ती के 50 लोग कुछ समय पहले आई सुनामी लहरों में समा गए थे। 26 दिसंबर को सवेरे समुद्र की तूफानी लहरें उठीं और इस बस्ती के अनेक स्त्री-बच्चों को लील गईं। इन लोगों के मकान तट से 50 मीटर के अंदर थे और आस-पास झाड़ियां होने के कारण ये लोग भाग भी नहीं पाए। अनेक महिलाओं की साड़ियां और बाल झाड़ियों में फंस गए और वे भाग नहीं सकीं और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। आज पुडुकुप्पम के बचे हुए लोग अपनी पहले वाली बस्ती से 300 मीटर दूर अस्थायी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। जब भी उनकी नजर अपनी पुरानी उजड़ी हुई बस्ती पर पड़ती है, वे उस दिन की याद करके सिहर उठते हैं जब 10 मिनट के अंदर उनकी जिंदगी बदल गई थी और वे दुखमय जीवन बिताने को मजबूर हो गए थे। अगर आप उनकी पुरानी बस्ती से गुजरें तो टूटी दीवारें और उड़ी हुई छतें गांव की तबाही की कहानी खुद बयान कर देती हैं। और यह कहानी सिर्फ पुडुकुप्पम की ही नहीं बल्कि उन सभी गांवों की है जो तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में बसे हैं।

इन उजड़ी हुई बस्तियों को फिर से बसाना सरकारी और गैर सरकारी- दोनों तरह की संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती थी। दोनों तरह की संस्थाओं ने इस मौके पर अच्छी पहल की और आपदा की मार और तबाही से लोगों को उबारने में जुट गईं। प्रभावित अधिकांश गांवों में आज बुनियादी सुविधाएं जितनी अच्छी हालत में हैं, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। एक प्रभावित तटीय गांव पेरुमलपेट्टइ के पंचायत सदस्य, राजशेखरन ने बताया कि यह सुनामी राहत संस्थाओं की कोशिशों का नतीजा है कि उनके गांव में बिजली और पेयजल की सप्लाई में बहुत सुधार हुआ है। इन गांवों में पेयजल एक बड़ी समस्या है क्योंकि सुनामी के कारण भूजल खारा हो गया और पीने के लायक नहीं रहा। अब इन लोगों को टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। गांवों में टंकियां रख दी गई है ताकि इतना पानी उपलब्ध रहे कि जरूरतें पूरी होती रहें। पहले वाले हैंड पंप सुनामी के कारण बेकार हो गए थे जिससे काफी संख्या में हैंड पंप लगा दिए गए हैं। अनेक गैर-सरकारी संगठनों और दातव्य संस्थाओं ने खारे पानी को ठीक करने के यंत्र लगा दिए हैं ताकि पेय जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। ग्रामवासियों ने इन प्रयासों का स्वागत किया है।

सुनामी लहरों के कारण तटवर्ती गांवों के मछुआरों के अधिकांश मकान बह गए हैं। फाइबर से बनी नावों और लकड़ी की मछलीमार नौकाओं के मालिकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से ज्यादातर तट के पास झोपड़ियों में रहते थे अत: वे बेघर हो गए। आपदा के दस दिनों के अंदर सरकारी और गैर-सरकारी राहत संस्थाओं ने उन्हें अस्थायी आश्रय उपलब्ध करा दिया। आश्रय बनाने की जल्दी में ये संस्थाएं इनकी योजना और गुणवत्ता पर समुचित ध्यान नहीं दे पाईं। इनके आश्रय बनाने में अधिकांशत: जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया वह है डामर और कार्डबोर्ड का मिश्रण। बनाते समय शायद इन एजेंसियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सुनामी पीड़ितों को इनमें काफी समय तक रहने की जरूरत पड़ सकती है। ये आश्रय इस इलाके में गर्मी में रहने के एकदम अनुपयुक्त थे। अप्रैल से मई तक इन गांवों में जाने पर ग्रामवासी पेड़ों के नीचे बैठे दिखाई देते थे क्योंकि दोपहर की तेज धूप में घर के अंदर रहना मुश्किल होता है। चिलचिलाती धूप में अनेक आश्रयों का डामर पिघल जाता है। बच्चों और शिशुओं का ज्यादातर समय इन घरों के अंदर बीतता है अत: उन्हें खसरा हो गया। कुछ गांवों में ऐसे मकान बनाए गए जिनमें बिजली नहीं है। नतीजा यह कि इनमें रहने वालों को अंधेरे में रहना पड़ता है या फिर रात में सड़क पर लगी बत्ती के नीचे समय बिताना पड़ता है। कई गांवों में इन मकानों की स्थिति के कारण भी समस्या है। कई जगह ये आश्रय निचले इलाके में बनाए गए हैं अत: थोड़ी-सी बारिस होते ही वहां पानी भर जाता है। अप्रैल में मामूली बारिश होते ही लोगों को अलग जाना पड़ा क्योंकि इन मकानों में रहना मुश्किल हो गया। कई मकानों की छत दरक गई जिससे पानी टपकने लगा। कई मकानों में बाहर गली का पानी भर गया।

भविष्य में सुनामी जैसी आपदा के कारण ऐसी तबाही से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने इन परिवारों को समुद्र तट से कम से कम 200 मीटर दूर बसाने का फैसला किया है। इसकी मछुआरों ने मिली जुली प्रतिक्रिया हुई है। मछुआरे सहमत हैं कि दूर बसने से उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे लेकिन उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा। थलमपेट्टइ के एक मछुआरे मुतुरामन के अनुसार मछली पकड़ने वालों के लिए 'मापु' (मछलियों की आवा-जाही) देखना बहुत जरूरी है। समुद्र से दूर रहने पर वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस इलाके के मछुआरे अधिकांशत: परंपरागत तरीके से मछली पकड़ते हैं अत: उनके लिए 'मापु' बहुत महत्वपूर्ण है। वे एकदम किनारे पर झोपड़ी डाल कर रहना चाहते हैं ताकि 'मापु' देख सकें और उसी झोपड़ी में मछली पकड़ने के उपकरण भी रख सकें। सरकार चाहती है कि तट की जमीन उसे मिले। मछुआरे अपने पिछले तजुर्बों से परेशान हैं कि तटीय

जमीन का इस्तेमाल फैक्ट्री अथवा तटवर्ती उद्योग लगाने में किया जाएगा। उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर उनका समुद्र में आना जाना सीमित हो जाएगा। नागपट्टिनम के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल के दिनों झींगा मछली के फार्म खुल गए हैं जिससे मछुआरों को अपनी जीविका का खतरा लगता है। इस इलाके में भी तटवर्ती भूमि प्राइवेट फर्मों या उद्यमियों को पहले दी गई थी जो मछुआरों के लिए चिंता का कारण था। ऐसे फार्मों के कारण मछुआरों की आवा जाही ही बाधित नहीं होती बल्कि उनके व्यापार पर भी इसका असर पड़ता है। इन झींगा पालकों ने काफी ज्यादा उत्पादन बढ़ाया है जिसके कारण पिछले 20 वर्षों में झींगा की कीमत में 200 रुपये तक की कमी आ चुकी है। अनेक झींगा फार्मों ने अपनी गंदगी समुद्र में डाल दी जिससे झींगा के बच्चे मर जाते हैं और मछुआरों को कम शिकार मिल पाता है। ये सब वे बातें हैं जिनका मछुआरों को तट से दूर बसाने पर विचार करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार को इस इलाके में और झींगा फार्म खोलने की अनुमति न देकर मछुआरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अनेक गांवों में पुनर्वास का काम गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से किया जा रहा है। इन संगठनों ने नये मकानों के निर्माण के लिए जगह का चुनाव करने के लिए ग्राम नेताओं के साथ सलाह मशविरा किया है। इस काम में लगी एजेंसियां प्राइवेट लोगों से जमीन प्राप्त करने का काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम पूरे परिवेश पर नजर डालें तो लगता है कि स्थानीय लोगों से सलाह का कुछ खास महत्व नहीं है। अनेक मामलों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार की संस्थाएं ऐसे ढंग से काम कर रही हैं मानो वे सब कुछ जानती हों। इसका दीर्घअवधि में इन समुदायों पर बुरा असर पड़ सकता है। इन लोगों को फाइबर विश्नफोर्स्ड प्लास्टिक (एफ आर पी) की नावें दान की गईं है लेकिन ऐसा करते समय मछली व्यापार की बारिकियों का ध्यान नहीं रखा गया। मछली पकड़ने में उसका स्रोत सीमित है, अत: व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नाव उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। चिन्नुरपेट्टइ गांव में जहां पहले सिर्फ 6 नावें होती थीं, अब 15 नावें हो गई हैं। इससे ग्रामवासियों में प्रतियोगिता बढ़ गई है। सद्भाव के साथ उनका हित साधन करने के लिए उठाए गए कदम से भी उनका अहित हो सकता है। कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने गांवों को गोद लिया है। ऐसा करके उन्होंने उस गांव को राहत पहुंचाने की सभी जरूरतें पूरी करने की कोशिश की है। गैर-सरकारी संगठन सिर्फ छोटे गांवों को गोद लेना चाहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि बड़े गांव को अपनाने का मतलब होगा ज्यादा लोगों के लिए काम करना। इसका परिणाम यह हुआ है कि गांवों में विषमता आ गई है। छोटे गांव को उनकी जरूरत से ज्यादा सामग्री मिली जबकि बड़े गांवों को आवश्यकता से कम प्राप्त हुई। इससे छोटे बड़े गांवों के बीच आपसी संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। तमिलनाडु के पूरे तटीय इलाके में गांवों में परंपरागत पंचायत व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। यहां के गांव एक सोपानात्मक व्यवस्था से जुड़े हैं और उनके हर 16 गांवों पर एक प्रधान गांव होता है। गैर-सरकारी संगठनों की गांवों को गोद लेने की प्रक्रिया से इस व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है। प्रधान गांव एक बड़ा गांव होता है अत: प्रशासनिक मामले ठीक ठाक चले, इसके लिए छोटे गांव को बड़े गांव पर निर्भर होना पड़ता है।

एक और क्षेत्र जिस पर सुनामी का बुरा असर पड़ा, वह है खेती। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले नागपट्टिनम के 65 प्रतिशत गांव कृषि प्रधान हैं। लेकिन इन गांवों के लोगों को सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसियों से कोई खास सहायता नहीं मिली है। कृषि प्रधान गांवों में मछुआरों के गांवों के मुकाबले भले ही लोगों की जानें कम गई हो, लेकिन सुनामी का उनकी जीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा। सुनामी के कारण मछुआरों की जीविका का स्रोत समुद्र बर्बाद नहीं हुआ लेकिन नागपट्टिनम जिले के गांवों में खेती की जमीन ऊसर हो गई है और वह खेती के योग्य नहीं रही। तमिलनाडु जैविक किसान आंदोलन की निदेशक, रेवती के अनुसार सुनामी का पानी रिस कर जमीन के अंदर पहुंच गया जिससे जमीन का खारापन बढ़ गया और अम्लता के कारण जमीन खराब हो गई। खारेपन का सामान्य स्तर 0.65 होता है लेकिन सुनामी के बाद यह 21 हो गया है। इससे जमीन कड़ी हो

महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास दर में गिरावट

छह महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्रों में विकास दर में कमी के कारण कुल मिला कर मूल सुविधा क्षेत्र की विकास दर जुलाई में 0.5 प्रतिशत घट गई है। पिछले साल इसी महीने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कुल विकास दर 11.1 प्रतिशत थी।

पिछले कुछ महीनों में दर्ज की गई यह सबसे कम विकास दर है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास दर गिरी (अंक प्रतिशत विकास दर्शाते हैं)

	जुलाई 2005	जुलाई 2004
मूल सुविधाएं	0.5	11.1
कच्चा तेल	-4	0.2
कोयला	-1.7	7.5
बिजली	-1.3	13.8
सीमेंट	2.3	8.4
शोधन	3.6	3.8

गई है और सुनामी के बाद काफी दिनों तक तेज धूप पड़ी जिससे उसमें दरारें आ गईं। इतनी ज्यादा खारी जमीन में बीज नहीं उगते। खेतों में समुद्र की गाद भी काफी जमा हो गई है। इस गाद से सिंचाई के काम आने वाले खुले कुएं एकदम भर गए हैं। यही कारण है कि इस समय अनेक गांवों में जमीन खेती लायक नहीं रह गई बल्कि कुएं भी सूख चुके हैं।

ईसाइयों के लोकप्रिय स्थान वेलंकनी के पास दक्षिण पोइगनलुर की एक किसान एस्तर अरोकियामेरी ने पिछले दिनों की याद करते हुए कहा कि सुनामी से पहले वह अपनी जमीन पर 10 लोगों को काम पर लगाया करती थी। उसके पास जो भी पैसा था वह इस जमीन को फिर से खेती लायक बनाने में खर्च हो गया। उसे अपनी बेटी की पढ़ाई भी बंद करा देनी पड़ी क्योंकि सभी बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया। इस क्षेत्र के अधिकांश किसान छोटे कृषक हैं और उनके पास एक एकड़ से कम जमीन है। यहां किसानों को 4000 रुपये प्रति परिवार दिया गया था। अन्य कोई मुआवजा नहीं मिला। किसानों का अनुमान है कि जमीन को कृषि-योग्य बनाने पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च आएगा। लेकिन सरकार सिर्फ 400 प्रति एकड़ दे रही है। किसानों की शिकायत है कि इससे कोई लाभ नहीं। सरकार 1970 की दरों पर राहत सहायता दे रही है। शुरू में सरकार ने गाद से पटे कुओं की सफाई के लिए 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर देने की घोषणा की थी। लेकिन अब सिर्फ सब्सिडी वाले ऋण दिए जा रहे हैं। सरकार की इस कार्रवाई से किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं।

अन्य लोगों को राहत कभी भी दी जा सकती है, लेकिन किसानों को उपयुक्त समय पर संसाधन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। किसान ठीक समय पर फसल काट सकें, इसके लिए उन्हें सितंबर-अक्तूबर में सहायता मिलनी चाहिए। ऐसा तब है जब बुवाई करनी हो। यहां की खेती अधिकांशत: बारिस पर निर्भर करती है अत: इस समय तक बुवाई हो जानी चाहिए ताकि जनवरी में फसल काटी जा सके। अगर अक्तूबर तक जमीन का खारापन और गाद हटाने का काम पूरा न हुआ तो लोगों को फसल की योजना बनाने के लिए एक साल और इंतजार करना पड़ेगा।

इस क्षेत्र के किसानों को लगातार चार वर्षों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चार साल से उन्हें सूखे अथवा वर्षा के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2004 में उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद थी कि सुनामी ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया और सारी फसल बर्बाद हो गई। यही कारण है कि किसानों पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यहां काम कर रही एजेंसियों को अब और देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका सारा ध्यान मछुआरों पर रहा है और किसानों की अनदेखी हुई है। किसानों को भी वैसी ही तबाही का सामना करना पड़ा है जैसी मछुआरों को। अगर बाहरी मदद मिल भी गई तो किसानों को अच्छी और सामान्य दिनों की तरह फसल उगाने की हालत में आते-आते 3-4 साल लग जाएंगे। ❑

IAS द हिस्टोरिका PCS

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित संस्थान

श्री रमेश चन्द्रा के कुशल नेतृत्व में **'द हिस्टोरिका'** संस्थान ने इतिहास विषय के संदर्भ में प्रचलित नवीन संकल्पनाओं/अवधारणाओं के आलोक में सिविल सेवा हेतु इतिहास के अध्ययन एवं लेखन को **'वैज्ञानिक दृष्टिकोण'** प्रदान करते हुए नये प्रतिमानों को स्थापित किया है।

संस्थान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने B.Sc./M.Sc. या B.Com./M.Com या अन्य विषयों की पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए इतिहास को समझना एवं लिखना अत्यंत सरल बना दिया है.....। आइये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कक्षाओं में एवं सफलता का मार्ग प्रशस्त करें....।

STAR of the 'HISTORICA'

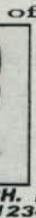

उत्तरांचल पी० सी० एस० टॉपर : रैंक-3

(उप जिला अधिकारी)

'द हिस्टोरिका' संस्थान के निदेशक श्री रमेश चन्द्रा जी ने मुझे उच्च रैंक दिलाने में विशेष योगदान दिया है। इतिहास विषय पर उनका वैज्ञानिक व समग्र दृष्टिकोण अत्यन्त सराहनीय है। साक्षात्कार तैयारी में उनके मार्गदर्शन से मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई।

HARISH CH. KANDPAL
R. N. : 112347

मेरी सफलता में श्री रमेश चन्द्रा का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। 'द हिस्टोरिका' में गुणवत्ता उन्मुखीकरण पर विशेष जोर दिया जाता है जो सफलता हेतु अनिवार्य है। इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय के लिए यह संस्थान काफी मददगार सिद्ध हो रहा है।

Ajay Kr. Keshri
R.No. 139064 I.A.S. - 2004

'द हिस्टोरिका' संस्थान इतिहास एवं सामान्य अध्ययन के लिए एक, प्रमाणिक संस्थान है। मेरी सफलता में इस संस्थान का एवं इसके निदेशक श्री रमेश चन्द्रा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

Rajesh Kr. Meena
R. No. 140758 I.A.S. - 2004

'सर की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कक्षाओं, लेखन-कला एवं साक्षात्कार में दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों ने मेरी सफलता सुनिश्चित की।'

Shivani Bhauryal
(Trade Tax Officer) उत्तरांचल पी.सी.एस.

कुल चयन 55 (2003-05) संघ एवं सभी राज्य सिविल सेवा में (प्रारम्भिक परीक्षा / मुख्य परीक्षा / साक्षात्कार)

सफलता की यह यात्रा अनवरत् जारी है...। आइयें आप भी शामिल हो अपनी 'अर्जुन दृष्टि' के साथ हमारी परिणामोन्मुखी कक्षा कार्यक्रमों में...।

इतिहास द्वारा रमेश चन्द्रा

सामान्य अध्ययन द्वारा रमेश चन्द्रा एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ

नया सत्र: 10 नवम्बर (नि:शुल्क कार्यशाला के साथ)

निबन्ध: अगस्त में 15 दिवसीय कार्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा (विशेष सत्र)
20 सितम्बर (नि:शुल्क कार्यशाला के साथ)
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल पी.सी.एस. पर विशेष बल

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम
विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास, निबन्ध, अंग्रेजी अनिवार्य

2063 (BASEMENT), OUTRAM LINES,
(IN THE LANE BEHIND D.A.V. PUBLIC SCHOOL) KINGSWAY CAMP,
DELHI- 110009 TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

YH/10/5/08

खबरों में

- आखिरकार संयुक्त हिंदू परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन विधेयक 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई। कानून पारित हो जाने के बाद अब संपत्ति में पुत्र-पुत्री के बीच कोई भेदभाव नहीं रहेगा।
- सरकार ने लाभ में चलने वाले 13 बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी उसी क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत लिया गया है। इन सार्वजनिक उपक्रमों में उसी क्षेत्र की किसी कंपनी को हिस्सेदारी बेचने के लिए विनिवेश प्रक्रिया को औपचारिक रूप से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इन उपक्रमों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, भारतीय नौवहन लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम शामिल हैं।
- एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बांबे स्टॉक एक्सचेंज अपने गठन के 120 वर्ष बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो गया है। नये अवतार में इसने कई नयी योजनाएं लाने का फैसला किया है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद बीएसईएस के 51 फीसदी शेयर आम जनता को दिए जाएंगे।
- देश की 65 करोड़ से अधिक की ग्रामीण आबादी को कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी देने वाला ऐतिहासिक विधेयक संसद में पारित हो गया है। शुरुआत में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत गांव के हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। पांच साल के भीतर यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। निश्चित अवधि में रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- लोकसेवा के लिए इस वर्ष के रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भारत की सुश्री वी. शांता को सम्मानित किया गया है।
- भारत के इकलौते ओलंपिक रजत विजेता राजस्थान के राज्यवर्द्धन सिंह राठौर को देश के सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही राजस्थान के ही देवेन्द्र झांझरिया को पैरालिंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अर्जुन पुरस्कार के लिए झांझरिया के साथ टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और गोल्फर ज्योति रंधावा समेत 14 अन्य खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। विलियर्डस के अरविंद सावुर समेत तीन अन्य कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा हॉकी कोच राजेन्द्र सिंह जूनियर समेत तीन को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- अमरीका ने भारत के 6 परमाणु एवं अंतरिक्ष संस्थानों को प्रतिबंधित सूची से निकाल दिया है। प्रतिबंधित सूची से बाहर होने वाले संस्थानों में राजस्थान, तारापुर और कुंडकुलम में स्थित नाभिकीय ऊर्जा विभाग शामिल है। उनके अलावा इसरो और तिरुअनंतपुरम स्थित इसकी सहायक यूनिटों- इसरो टेलीमेन्ट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसरो इनरशियल सिस्टम यूनिट तथा अहमदाबाद स्थित द स्पेस एप्लिकेशन सेंटर को प्रतिबंध मुक्त किया गया है।
- विश्व के तीन कुपोषित बच्चों में से एक भारत का है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने से इन बच्चों की मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण की संख्या ज्यादातर निम्न वर्ग के बच्चों में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और केरल में कुपोषण की समस्या ज्यादा है।
- दुनिया में जितने लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है उनमें एक-तिहाई लोग भारत के हैं। गैर सरकारी संगठन कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी कटस ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में पानी का 70 प्रतिशत हिस्सा प्रदूषित है। यहां 80 प्रतिशत बीमारियां घटिया पानी पीने से होती है। विश्व जल विकास पर हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत को घटिया गुणवत्ता वाले पानी के देशों की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में 122 देशों में भारत को 120वां स्थान मिला है।
- नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री एडवर्ड प्रेसकाट ने हाल में सिंगापुर में आयोजित आर्थिक सम्मेलन में कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दृष्टि से चीन के मुकाबले भारतीय बाजार ज्यादा विश्वसनीय होता जा रहा है। भारत में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के कारण भारतीय बाजार के प्रति विदेशी निवेशकों का विश्वास ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 5.5 अरब डालर से ज्यादा की प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी भारत आई थी। वर्ष 2005-06 में भारत में आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक होने के कारण विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है।
- सुप्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक श्री अडूर गोपालकृष्णन को वर्ष 2004 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिने जगत में उत्कृष्ट

योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए श्री अडूर पहले ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। श्री अडूर गोपालकृष्णन को न केवल निर्देशन बल्कि पटकथा के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है।

- गत 6 सितंबर की रात से पेट्रोल तीन रुपये प्रति लीटर और डीजल दो रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। रसोई गैस और केरोसिन के दामों में कोई वृद्धि नहीं की है।
- राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 को लागू किये जाने की अनुमति दे दी है। यह राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद घरेलू हिंसा कानून-2005 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत राज्य और केंद्र शासित सभी प्रदेशों में महिलाओं को केवल संरक्षण ही नहीं मिलेगा अपितु महिलाओं के प्रति बढ़ रही इस तरह की प्रवृत्तियों पर लगाम भी लगेगी।
- आखिरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहने वाली केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना पर सहमति हो गई। यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है तथा इस दिशा में महत्वपूर्ण भी। करीब 2,000 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना के जरिए बेसिन का अतिरिक्त पानी 231 किमी. लंबी लिंक नहर के जरिए बेतवा बेसिन में पहुंचाया जाएगा।

केन-बेतवा परियोजना

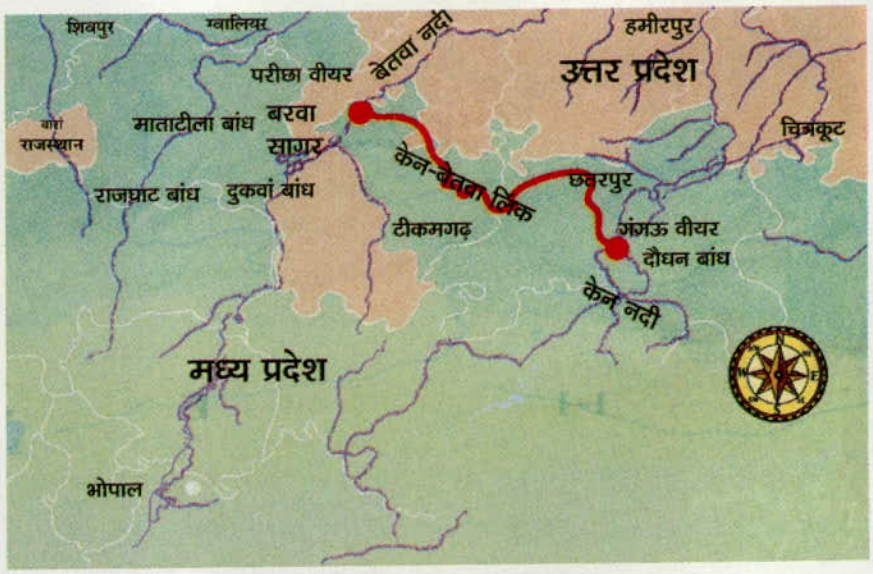

- भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा 33 करोड़ निरक्षर बसते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड मॉनीटरिंग रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन में भी निरक्षर महज 11 प्रतिशत है। निरक्षरता के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान में 6 प्रतिशत और बांग्लादेश में 7 प्रतिशत लोग ही निरक्षर हैं। यूनेस्को की इस रिपोर्ट के अनुसार, आज भी 80 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं, जो विश्व की कुल आबादी का 18 प्रतिशत है। इनमें भी दुनिया के 70 प्रतिशत वयस्क नौ सघन आबादी वाले देशों में रहते हैं। इन देशों में भारत में निरक्षर वयस्कों का प्रतिशत सर्वाधिक 33 प्रतिशत है। रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर भी ध्यान खींचा गया है कि विश्व की दो-तिहाई वयस्क आबादी निरक्षर है जिसमें 64 प्रतिशत महिलाएं हैं। योजना आयोग के अनुसार भारतीय परिवार की धुरी यानी महिलाओं की आधी आबादी निरक्षर है।
- मुंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स ने 8 सितंबर के दिन अभूतपूर्व आंकड़ें को पार कर लिया। पिछले काफी दिनों से 8000 की ओर तेजी से भागते हुए सेंसेक्स 105.78 पाइंट्स की ऊंची छलांग लगाकर 8052.56 पर बंद हुआ। महज 55 दिनों के भीतर ही सेंसेक्स ने 7000 अंक से 8000 अंकों तक पहुंचने का सफर पूरा कर लिया।

बीपीओ उम्मीदवारों के लिए नैसकाम परीक्षा

नैसकॉम ने बीपीओ कर्मचारियों के लिए एक परीक्षा की घोषणा की है। इसे 'नैसकॉम असेसमेंट आफ कंपीटेंस' (एनएसी) अर्थात योग्यता आकलन की नैसकॉम परीक्षा कहा जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण-योग्य उम्मीदवारों को काम पर लगाने योग्य कार्यबल घोषित करना होगा। दूसरे और तीसरे स्तर के नगरों में रहने वालों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा क्योंकि इन शहरों में बीपीओ कंपनियां भर्ती करने नहीं जाते।

आजमाइशी योजना बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा तथा गुड़गांव में शुरू की जाएगी जिसमें लगभग 36 बीपीओ कंपनियां और करीब 15,000 स्नातक भाग लेंगे।

इस परीक्षा का उद्देश्य बीपीओ की भर्ती लागत में 50 प्रतिशत कमी लाना है। इसके कारण प्रशिक्षण अवधि और लागत भी काफी घट जाएगी। हाल ही में हुई आनलाइन परीक्षा में जीईसीआईएस में 60 कर्मचारी शामिल हुए थे।

इस परीक्षा में उम्मीदवारों की गणित और मौखिक संचार योग्यता की परीक्षा होती है। परीक्षा पास करने पर उम्मीदवारों को एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जिसमें उसके द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड का भी उल्लेख होता है।

जो लोग इस परीक्षा में बैठेंगे उन्हें विभिन्न बीपीओ में कई दौर की परीक्षाओं में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जरिये बीपीओ कर्मचारियों की सक्षमता का एक राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित किया जाता है। इससे उम्मीदवारों को भी उनकी क्षमता और कमजोरियों का पता चल जाएगा और उन्हें लाभ होगा। ❑

सृजनात्मकता

○ मनोज गैरोला 'मनु'

मंथन

गति विश्व का नियम एवं उसकी अनिवार्य प्रक्रिया है तथा सृजन जीवन की आवश्यकता है। हममें से अधिकांश सृजनात्मक शक्ति का महत्व ही नहीं समझते तथा उस शक्ति की पूर्णत: अवहेलना कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सृजनात्मक शक्ति केवल कुछ प्रतिभाशाली लोगों को ही मिलती है। वस्तुत: ऐसी बात है नहीं। प्रत्येक मनुष्य में अपने व्यक्तित्व और भविष्य का इच्छित निर्माण कर सकने की क्षमता विद्यमान है।

लोक व्यवहार में पग-पग पर रचनात्मक अथवा सृजनात्मक विचार, वचन एवं कर्म की मांग होती है। यहां तक कि विरोधमूलक आलोचना भी रचनात्मकता काम्य होती है। माइकल डूरी का कहना है कि सृजनात्मक शक्ति प्रत्येक मनुष्य में जन्मजात होती है, परंतु उस सामर्थ्य का उपयोग करना साहसी, धैर्यवान और प्रयत्नशील लोगों से ही संभव हो पाता।

प्रत्येक व्यक्ति क्षमतासंपन्न है। व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी कठिनाइयों को स्वयं निरस्त करके उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसमें अद्भुत क्षमताओं का भंडार भरा पड़ा है। सृजन का न आदि होता है न अंत।

विसंगतियों के वर्तमान युग में भी व्यक्ति से सृजनधर्मिता की अपेक्षा की जाती है। वह नवनिर्माण न करे, परंतु इतना अवश्य करे कि संपर्क में आने वाली वस्तु एवं जगह को छोड़ने से पहले उसको उस रूप की अपेक्षा अधिक गुणवान बना दे, जिस रूप में उसने उस वस्तु को प्राप्त किया था। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वह न अपना भला कर सकता है और न समाज के किसी काम का रह जाता है। व्यर्थ समझकर समाज उसकी उपेक्षा कर देता है। यह आवश्यक नहीं है कि सृजन का लक्ष्य कोई महान कृति ही हो। हमारे सामने ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जब मात्र एक रचना का प्रणयन करके रचनाकार अमर हो गए।

आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक सर विलियम हर्सचेल ने जब सर्वोत्तम दूरबीन बनाने का विचार किया तो उन्हें पहले कांच पीसना और आईने पर पालिश चढ़ाने का कार्य सीखना पड़ा। इस प्रकार कई महीनों के सतत प्रयास के बाद वे पहला आईना बना पाए, वह भी त्रुटिपूर्ण। सतत परिश्रम और दीर्घकालीन एकनिष्ठ अभ्यास से दो सौ असफल प्रयत्नों के बाद ही वे संतोषप्रद दूरबीन बना सके। किसी भी कार्य में लगनशीलता आवश्यक है। विश्वविख्यात संगीतविज्ञानी मोजार्ट में तत्काल स्वर रचना करने की विलक्षण क्षमता थी, परंतु वे भी तो एक बार में एक ही रचना कर सकते थे।

सृजन न हो तो समस्त वनस्पति जगत, जीव जगत व जीव नि:शेष हो जाएं। इसी कारण फूल-फल प्रदान करने वाले लता-गुल्म ही प्रिय होते हैं। इस गुण से रहित होने पर उन्हें झाड़-झंखाड़, खरपतवार आदि कहकर उखाड़कर फेंक दिया जाता है। ऊसर भूमि किसको अच्छी लगती है। प्राणी जगत का वैज्ञानिक अध्ययन यह तथ्य उजागर करता है कि समस्त प्राणियों में अंतर्निहित शक्ति या ऊर्जा, प्रजनन एवं आत्मरक्षा इन दो मौलिक वृत्तियों की संतुष्टि में नि:शेष हो जाती है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इन दोनों मौलिक वृत्तियों के निर्वाह के उपरांत भी अतिरिक्त शक्ति एवं ऊर्जा का धनी बना रहता है। यह अवशिष्ट ऊर्जा मानव को अतिरिक्त सामर्थ्य प्रदान करती है और उसके सम्मुख पूर्ण मानव बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस सामर्थ्य को हम रचनात्मक प्रतिभा कहते हैं। मनोविज्ञान के मनीषी इसे सौंदर्यानुभूति कहते हैं। इस अतिरिक्त ऊर्जा, प्रतिभा द्वारा मानव अपने उत्थान एवं विकास का विधान करता है। इसी के द्वारा वह कलाकृतियों का सृजन, काव्य-कृतियों का प्रणयन, वैज्ञानिक शोध एवं आविष्कार एवं कल्याणकारी कार्य करने में समर्थ होता है। प्रजनन एवं आत्मरक्षा की मौलिक वृत्तियों के निर्वाह में संयम द्वारा वह अपनी उक्त सामर्थ्य में वृद्धि कर सकता है।

भारत के आर्य ऋषियों ने लोक-व्यवहारार्थ प्रणीत आचार-संहिताओं का विधान इसीलिए किया है कि मनुष्य सुखोपभोग में केवल उतनी ही ऊर्जा व्यय करे जितनी जीवन निर्वाह एवं लौकिक व्यवहार की दृष्टि से अनिवार्य है। योग, ध्यान, साधना आदि के समस्त विधान उक्त ऊर्जा के संचयन एवं उसके सृजनात्मक उपयोगार्थ ही स्थापित किए गए हैं। इस संदर्भ में यह भी इंगित किया गया है कि उपयोगी ग्रंथ के सृजन द्वारा मानव ज्ञान की परंपरा को अग्रसर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मृत्यु भय से मुक्ति प्राप्त करने का सरलतम उपाय यही है कि व्यक्ति जन्म के साथ जिन ऋणों का भार ढोता है, उनसे उऋण होने का प्रयत्न करते हुए सृजन धर्म का पालन करे और अपनी स्मृति स्वरूप कोई कृति छोड़ जाए। कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपनी एक कविता में लिखा है कि काल देवता व्यक्ति को नहीं, उसके द्वारा उत्पादित स्वर्णिम धान को अपनी नाव में स्थान देते हैं।

दार्शनिक डूरी का कहना है कि जब हम किसी बड़े कार्य को हाथ में लेते हैं, तो सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। सूर्य समय पर उगता है, पृथ्वी धीरे-धीरे घूमती है, किंतु वे अपने कार्य सुनिश्चित गति से व्यवस्थापूर्वक करते रहते हैं। यही सृजनात्मक शक्ति का स्वरूप एवं रहस्य है।

सृजन जीव का धर्म एवं जन्मजात दायित्व है। पक्षियों के घोंसले, वन्य पशुओं की मांदें और गुफायें तथा मिट्टी के बर्तनों से लेकर श्रेष्ठतम कलाकृतियां आदि समस्त वस्तुएं सृजन वृत्ति के उप लक्षण हैं, इनके प्रति अपने दायित्व निर्वाह के लिए सृजनशीलता के तीनों पक्षों, आत्मत्याग, समर्पण भावना एवं नवनिर्माण की ललक का निर्वाह अपेक्षित है।

मात्र सृजन पर्याप्त नहीं है उसकी सार्थकता यह है कि वह नव निर्माण में सहायक हो। असामाजिक संतान मात्र उत्पत्ति है, सृजन नहीं। पृष्ठों को काला करना मात्र ग्रंथ-प्रणयन नहीं है। समाजोपयोगी एवं कल्याणकारी रचनाएं ही 'सृजन' की सीमा में आती हैं। सृजन में रचनाधर्मिता अंतर्निहित है।

सृष्टि अनवरत गतिमान है। इस तथ्य को लक्ष्य करके महर्षि अरविंद ने कहा है कि यदि हम ईश्वर की सत्ता को मानते हैं तो हमें यह भी स्वीकारना होगा कि यह सृष्टि भी उसी के भीतर से निकले हुए ताने-बाने का परिणाम है।

सृजन विकास प्रक्रिया का मधुर संगीत है। यह प्रतिभा का पाथेय है। प्रत्येक सृजनात्मक कार्य विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। विश्वात्मा की विकास-योजना में भागीदार बनने के लिए यह अपरिहार्य है कि हम सृजन वृत्ति को विकसित करें। यह जीवन की आवश्यकता है। सार्थकता इसी में है कि हम सृजन रूपी उन पद चिह्नों की रचना करें जिससे जीवन में क्षमताओं, प्रतिभाओं सामर्थ्य को रचनात्मक दिशा दी जा सके।

विजेता की तरह सोच जीवन में उत्साह, उमंग एवं सृजनशीलता भर देती है। यह सोच थके-हारे एवं निराश जीवन के अंधकार को तार-तार कर आशाओं का दीप जलाती है। मानसिक चेतना असंख्य सृजन अथवा रचनात्मक क्षमताओं की स्रोत है। मनोभूमि की उर्वरता में विविध प्रकार की सृजनात्मक कुशलता अंकुरित होती है। यदि इन्हें उचित पोषण-संवर्द्धन मिल सके तो व्यावहारिक जीवन में इनका बड़ा प्रभावशाली प्राकट्य होता है। जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं, दुनिया उन्हें प्रतिभाशाली के रूप में सम्मानित करती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो अपनी प्रतिभा से गौरवान्वित होते ही हैं, संपूर्ण विश्व भी उनके अनुदानों से अपने भाग्य एवं भविष्य को संवारता है। मानव-सभ्यता के इतिहास में हम जिन प्रतिभावानों की रचनात्मक क्षमताओं से चमत्कृत कर देने वाले कथानक पढ़ते हैं उनके पीछे यही रहस्य समाया है।

संगीत, गायन, चित्रकला, नाट्य, नृत्य, अभिनय, वास्तु, शिल्प, खेल, शोध-अनुसंधान के वैज्ञानिक आयाम प्रकारांतर में मानवीय

(शेषांश पृष्ठ 67 पर)

भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इतनी अद्यतन जानकारी इतने कम मूल्य पर अन्यत्र दुर्लभ है

प्रमुख आकर्षण

• रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की नई वार्षिक ऋण एवं मौद्रिक नीति, 2005-2006 • नई विदेश व्यापार नीति 2005-2006 • केन्द्रीय बजट 2005-2006 • रेलवे बजट 2005-2006 • आर्थिक सर्वेक्षण 2004-2005 • भारत 2005 • World Economic Outlook April, 2005 • Statistical Outline of India 2004-05 • सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश • केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005 • विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2005 • अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • Statesman's Year Book 2005 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'मुद्रा एवं वित्त' रिपोर्ट 2003-2004 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'भारत में बैंकिंग एवं प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट' 2003-2004 • विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 • मानव विकास रिपोर्ट 2004 • Global Development Finance 2004 • दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 • 545 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

Book Code : 851 ◆ Pages : 248 ◆ Price : Rs. 100/-

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2853400 Fax 2851568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

YH/10/5/04

शहद के गुण बेहद

○ मंजू पाठक

दूध के बाद शहद ऐसा पदार्थ है, जो आहार अर्थात उत्तम संतुलित भोजन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्योंकि शहद में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित आहार में होने चाहिए। शहद में 50 प्रतिशत ग्लूकोज, 37 प्रतिशत फ्रुक्टोज, 2 प्रतिशत सुक्रोज, 2 प्रतिशत माल्टोस, 2 प्रतिशत डैक्सट्रिंक्स, 2 प्रतिशत गोंद, 2 प्रतिशत मोम, 2 प्रतिशत क्लोरोफिल एवं 2 प्रतिशत सुगंध के अंश होते हैं। यही नहीं शहद में 'विटामिन ए', 'विटामिन बी-6' विटामिन बी/12 एवं अल्प मात्रा में 'वटामिन सी' भी विद्यमान रहता है। साथ ही साथ लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, गंधक, मैगनीज, पोटैशियम, आयोडिन, आदि खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शहद में ऐंटिसेप्टिक तत्व, जल एवं एमिनो एसिड आदि तत्व भी पाए जाते हैं। शहद में एमिनो एसिड की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमिनो एसिड की श्रृंखला ही प्रोटीन का निर्माण करती है, और प्रोटीन भोजन का सबसे आवश्यक तत्व होता है। इसलिए किसी भी आयु वर्ग के लोग इसका सेवन करना पसंद करते हैं।

चिकित्सा के विचार से शहद का विशेष महत्व है। क्योंकि शहद में फलों में प्राप्त होने वाली शक्कर विद्यमान होती है, जो शरीर के विकास के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसके सहारे शरीर अपने कोषों की संरचना का संशोधन करता है। शहद में शरीर को क्षमता प्रदान करने एवं संशोधन करने के इतने तत्व होते हैं कि 'बैनर मेकफेडेन' शहद का सेवन कर 80 वर्ष की आयु में वायुयान से पैराशूट से जमीन पर छलांग लगा चुका है।

चूंकि शहद में ग्लूकोज भी होता है अत: शहद के सेवन से आंत के ऊपर का भाग इसे अभिशोषित करता है। अभिशोषित होने के पश्चात यह तत्काल मस्तिष्क एवं मांस पेशियों चला जाता है, जहां जाकर शहद लाइक्रोजेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे थकान दूर हो जाती है। ग्लूकोज में एक ऐसी शक्ति होती है, जो शरीर के कोषों में आक्सीजन पहुंचाता है एवं शरीर की गतिविधि के कारण जो अम्ल उत्पन्न होता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है।

शरीर में तत्काल स्फूर्ति लाने हेतु शहद का सेवन करना विशेष लाभदायक होता है। इसके लिए शहद में संतरा का रस डालकर या जल अथवा दूध में शहद डालकर पीने से तत्काल स्फूर्ति आ जाती है। शहद में प्राकृतिक रूप में शक्कर होती है, वह मस्तिष्क को तीव्रता प्रदान कर थकावट को मिटा देती है। इसलिए प्रतिदिन सिर्फ शहद का सेवन करके भी जीवित रहा जा सकता है। यदि जलपान के समय भी चाय या काफी के स्थान पर शहद का सेवन किया जाए तो दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी।

शहद में विद्यमान स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण ही खिलाड़ी शहद का सेवन अवश्य करते हैं जिससे उनके अंदर स्फूर्ति, ताकत एवं सहनशीलता विद्यमान रहती है। यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का एक मधु पालक था और भरपूर शहद का सेवन करता था। हिलेरी का कहना था कि ऐवरेस्ट पर चढ़ने का कार्य तो शहद ही किया है, मैंने नहीं यही नहीं सन् 1951 में रोथरहम का निवासी फिलिप एच्छ राइजिंग ने 16 किलोमीटर लंबी पिंडरमियर झील को मात्र 8 घंटे में ही तैर कर पार कर लिया है, जिसका श्रेय वह शहद को ही देता है।

रोटी, चावल अथवा दूध के साथ शहद का सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट एवं चिकनाई प्राप्त होती है। 'एनसाइक्लोपीडिया' रिलिजन एंड एथिक्स' में शहद लगी डबल रोटी को देवताओं का आहार बताया जाता है। अपने देश में भी शहद को दूध में मिलाकर सेवन करना उत्तम माना जाता है। दूध एवं शहद एक उत्तम यौगिक है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है एवं पेट में गैस बनती है, उन्हें दूध में शहद मिलाकर सेवन करना फायदेमंद होता है

स्त्रियों के लिए उत्तम आहार

स्त्रियों के लिए शहद एक उत्तम आहार है, क्योंकि स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान एवं स्तनपान कराने के समय अतिरिक्त शक्ति एवं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। स्त्रियों के रंग एवं यौवन को सुंदर बनाने में शहद अहम भूमिका निभाते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान स्त्रियां शहद का सेवन करती हैं तो पैदा होने वाला शिशु हृष्ट-पुष्ट, सुंदर एंव मानसिक दृष्टि से अन्य शिशुओं से श्रेष्ठ होता है। जिसका मुख्य कारण यह है कि शिशु का मां द्वारा सेवन किए गए शहद के माध्म से प्रोटीन, कैल्शियम आदि तत्व आवश्यक मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं।

शहद में कुछ ऐसे भी होते हैं, जो रंग-रूप एवं गुण-दोषों को वंशानुगत रूप में संतान तक पहुंचाते हैं। चिकित्सक इसे भी प्रोटीन की ही करामात मानते हैं। शहद में प्रोटीन नामक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है, जो स्त्रियों में पोषक के रूप में शरीर को स्वस्थ एवं सुंदर बनाता है।

हृदय रोगियों के लिए वरदान

शहद का नियमित सेवन करना हृदय रोगियों के लिए वरदान माना गया है। एडिन वर्ग के चिकित्सक डा. जी.एन. डब्ल्यू थामस हृदय रोग से पीड़ित रोगी को शहद का सेवन करने की सलाह देते हैं। डा. थामस के अनुसार शहद हृदय रोगियों के हृदय को पुनर्जीवित करके शक्ति प्रदान करता है।

शहद में कुछ ऐसे एंजाइमी अंश भी होते हैं जो भोजन के लिए पाचक का काम करते है। भारत के सुविख्यात पहलवानों ने शहद प्रयोग करने की बात स्वीकार की है। ग्रीक कवि होमर ने भी ग्रीक पहलवानों द्वारा शहद के प्रयोग की परंपरा का वर्णन किया है। आज भी खेलों में पेय पदार्थों के रूप में शहद का सेवन लोकप्रिय है। इससे स्पष्ट होता है कि शहद खोई हुई शक्ति की पूर्ति करने के साथ अतिरिक्त ऊर्जा भी प्रदान करता है।

शहद का औषधीय उपयोग

शहद औषधि का भी काम करता है। इसका सीधे सेवन तो किया ही जाता है, अनेक औषधियों के निर्माण में भी शहद का प्रयोग किया जाता है। शहद का रात में सेवन करने से अच्छी नींद आती है। यदि सोते वक्त गर्म दूध में शहद मिलाकर पीया जाए तो नींद अच्छी आती है। दूध में शहद मिलाकर पीने से पेट में गैस की शिकायत भी नहीं रहती है, जबकि दूध में शक्कर डालकर पीने से गैस बनती है।

एक विख्यात चिकित्सक डा. एच्छ ए स्कूटी के अनुसार मानव कंकाल में जितने तत्व पाए जाते हैं वो सभी शहद में मौजूद होते हैं। चूंकि शहद में लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए रक्ताल्पता से ग्रसित रोगियों के लिए शहद का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है।

शहद अपने स्वादिष्ट स्वाद के कारण बच्चों में काफी लोकप्रिय है। एक बच्चे के विकास के लिए जितनी मात्रा में कैल्शियम चाहिए, यदि बच्चा शहद खाता है, तो उसे वह कैल्शियम मिल जाती है जिससे उसके दांत एवं हड्यां मजबूत हो जाती है।

मधुमेह के रोगियों के लिए शक्कर खाना घातक माना जाता है, जबकि शहद का सेवन करना मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि शहद में जो शक्कर होती है, उसे मधुमक्खियों द्वारा पहले ही पचाकर शरीर द्वारा अभिशोषित करने योग्य बनाकर ही संग्रह किया जाता है।

शहद का सेवन करने से खांसी, निमोनिया एवं टीबी आदि रोगों में विशेष लाभ पहुंचता है। पुराने दमे, श्वासनली की बीमारियों एवं फेफड़े से संबंधित सभी तरह के रोगों में शहद का सेवन करने से लाभ पहुंचता है। वैज्ञानिकों के परीक्षण के अनुसार एक पौंड शहद में 70 अंडों के बराबर शक्ति रहती है।

फोड़े-फुंसी हो जाने की दशा में भी शहद का सेवन करना लाभदायक होता है। चूंकि शहद में एन्टीसेप्टिक गुण भी विद्यमान होता है, इसलिए इसे फोड़े-फुंसी पर मरहम के रूप में लगाने पर भी लाभ पहुंचता है।

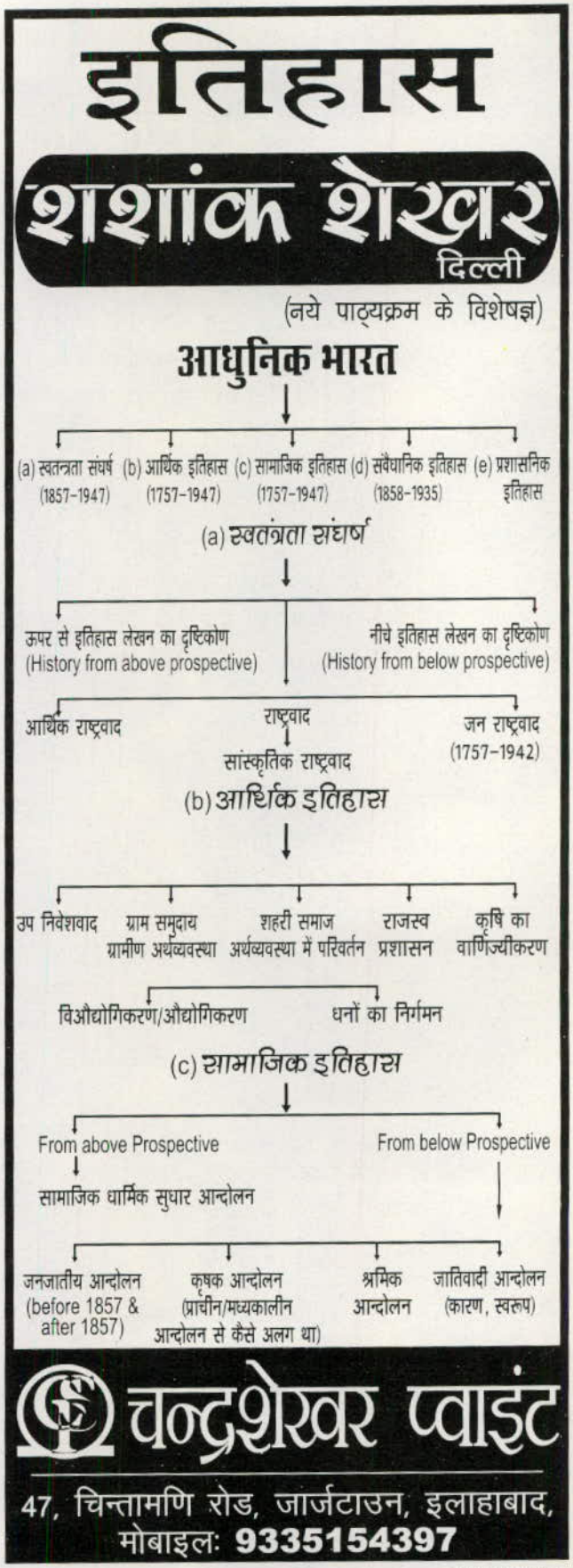

YH/10/5/06

शहद के लेप से घाव के दाग, चेहरे की झाईयां एवं कील-मुंहासे भी ठीक हो जाते हैं।

एड़ी फटने, उंगलियों की घई लगने, तलुओं में खुरूये हो जाने एवं नाखून उतर जाने पर दिन में दो-तीन बार शहद लगाने से काफी लाभ पहुंचता है। शहद की पट्टी में हड्डियों को जोड़ने की भी क्षमता होती है। इसलिए मोच लगने, घुटनों में दर्द होने एवं हड्डी के टूटने पर शहद की पट्टी बांधना काफी लाभदायक होता है।

त्वचा का प्राकृतिक निखार लाने में भी शहद उपयोगी होता है। नींबू, शहद, बेसन एवं तिल मिलाकर तैयार उबटन त्वचा पर लगाने से त्वचा में निखार आ जाता है। सोते समय आंख में सलाई से शुद्ध शहद लगाने से आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। नाक, कान एवं दांत के दर्द में एक बूंद शहद डालने से दर्द से छुटकरा मिल जाता है। यदि सोते समय दूध में शहद मिलाकर सेवन किया जाए तो पाचन दुरूस्त रहता है एवं आंत के कीड़े भी मर जाते हैं। शहद की मालिश पूरे शरीर पर करने से ताजगी आ जाती है। एवं सोते वक्त प्रजनन अंगों पर मालिश करने से एवं नाभि में शहद डालने से कामशक्ति में वृद्धि होती है।

मोटापे से छुटकारा पाने में भी शहद उपयोगी होता है। शहद के साथ नींबू मिलाकर प्रात: काल शौच जाने से पूर्व गुनगुना जल से सेवन करने से मोटापा घटता है। इसके साथ ही साथ प्याज का रस एवं शहद, नींबू एवं शहद, अदरख का रस एवं शहद बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से शरीर की अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं।

स्पष्ट है कि शहद का नियमित एवं उचित मात्रा में सेवन करने से काफी लाभ पहुंचता है। शहद न केवल स्वस्थ, बलवान, स्फूर्तिवान एवं ऊ र्जावान बनाता है, बल्कि हमारी सारे व्याधियों को मिटाकर हमें दीर्घजीवी बनाता है। ❑

जुलाई तथा अप्रैल-जुलाई तक औद्योगिक विकास (प्रतिशत में)

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन के त्वरित अनुमान के अनुसार औद्योगिक उत्पादन जुलाई 2005 के दौरान 6.7 प्रतिशत तथा अप्रैल-जुलाई 2005-06 के दौरान 9.3 प्रतिशत बढ़ गया।

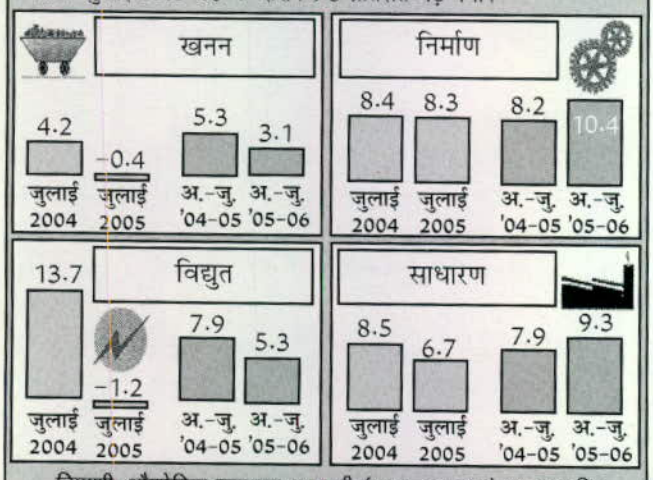

टिप्पणी: औद्योगिक उत्पादन अनुसूची (1993-94=100) पर आधारित

पीटीआई ग्राफिक्स

(पृष्ठ 64 का शेषांश)

सृजनात्मक क्षमताओं के ही बहुविध रूप हैं। इन और ऐसे अनेकों रूपों में से कोई किसी से कमतर नहीं है। बस बात विशेषज्ञता एवं विशिष्टता की है। किसी भी सृजनात्मक कुशलता का यदि आप में इस स्तर तक विकास हो सका तो समझें प्रतिभावान बनने में देर नहीं और यह जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि प्रतिभा विश्व की सभी विभूतियों का स्रोत है। विशिष्ट प्रतिभा के बल पर धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, यश सब कुछ पाया जा सकता है। प्रतिभा के अभाव में न केवल कदम-कदम पर ठोकरें खानी पड़ती हैं, बल्कि उपेक्षा, अपमान, अवहेलना, अवमानना का शिकार होना पड़ता है।

जिन्होंने सृजनात्मक क्षमताओं का अपने में विकास कर लिया है, वे मानवता के आकाश में सितारों की भांति सदा चमकते रहते हैं। उनकी अमर कृति सदा ही औरों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहती है।

प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक क्षमताओं का असीम भंडार है। विश्वास कीजिए, आप अपने में विशिष्ट हैं और यह विशिष्टता वह सृजनात्मक क्षमता है जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए सदा आप में तड़प जगाती है। यह तड़प ही हमारे जीवन की मौलिकता है। बस इसी को विकसित करना है। यही व्यक्ति की मौलिक क्षमता है। जो बार-बार अवचेतन रूप से उसे उकसाती एवं प्रेरित करती है। जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे व्यक्ति में इसके लिए प्रेरणा जगती रहती है। इसे पहचानने के लिए हमें अपने अंतर्मन में उठने वाले एहसासों को अनुभव करना चाहिए।

सृजनात्मक चिंतन की दिशा सदैव कल्याणकारी एवं शुभ होती है। इस ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदा ही मंगलमय अनुभवों से सिक्त होता है। जो इस दिशा में बढ़ रहे हैं, उन सभी का यह अनुभव है कि सृजनात्मक चिंतन का अर्थ ऐसी मानसिकता विकसित करना है, जो ईर्ष्या, क्रोध और ऐसी अन्य विध्वंसक वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती। मुदिता, शुभकामना, समता, शांति और क्षमा के स्पंदनों से पूर्ण मन ही रचनात्मक मन है क्योंकि ऐसी मन:स्थिति में सृजन संवेदनाएं अपने चरमोत्कर्ष पर विकसित होती हैं। यदि हम रचनात्मक विचार प्रेषित कर रहे हैं तो ये वैचारिक जगत में चलते हुए उन लोगों तक पहुंचते हैं, जिनकी ओर लक्षित किए गए थे। सृजनात्मक एवं रचनात्मक विचारों के तीर पुन: हमारे पास लोगों के आशीर्वाद, सद्भावना और शुभकामना लेकर लौट आते हैं और हमारा मन अधिक से अधिक प्रेरित, प्रसन्न और उत्साहयुक्त हो जाता है।

सृजनात्मक क्षमताओं की सही सार्थक अभिव्यक्ति हो सके, इसके लिए रचनात्मक चिंतन की दिशा तय होना भी जरूरी है। ध्यान रहे साधना से ही जीवन संवरता है सृजनात्मकता की कोंपलें फूटती हैं नवसृजन के अंकुर निकलते हैं। वास्तविक गौरव सृजनात्मक कार्यों में है। मनुष्य का चिंतन और प्रयास सृजनात्मक प्रयोजनों में ही निरत रहना चाहिए। जीवन की गरिमा इस कसौटी पर आंकी जाती है कि उसमें किस स्तर का कितना सृजनात्मक कार्य सफल हुआ। ❑

प्रगतिशील नारी

○ शमशेर अहमद खान

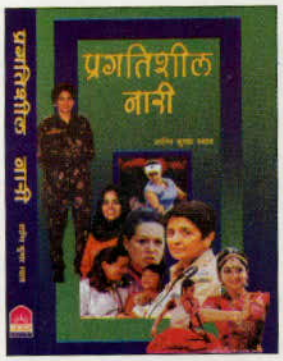

पुस्तक : प्रगतिशील नारी; **लेखक** : शान्ति कुमार स्याल; **प्रकाशक** : आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6; मूल्य : 325 रुपये

भारतीय नारी सदियों से करुणा, त्याग कोमलता एवं प्रेम की मूर्ति समझी जाती रही है, परंतु आज सभी क्षेत्रों में उनके कार्य-कौशल ने सिद्ध कर दिया है कि अपनी सृजनोन्मुखी क्षमताओं में वे किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। आज वही घर की दहलीज को पार कर अपनी जमीन तलाशती राजनीति हो या साहित्य, फिल्म हो या पत्रकारिता, व्यापार हो या समाज-सेवा, खेल हो या विज्ञान, डाक्टर हो या अभियंता, नेता हो या अभिनेता या फिर प्रकाशक, सभी क्षेत्रों में प्रमुखता से दिखाई दे रही है। जहां एक ओर वह देश के अंदर विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करती हुई समाज की सेवा कर रही है, वहीं घर से निकलकर पूरे विश्व परिदृश्य में प्रगति पथ पर बढ़ते हुए प्रगतिशील है।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने वैदिक संहिताकाल को सर्वोत्कृष्ट सभ्यता माना है। वैदिक संहिता काल में नारी को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। *शत-पथ ब्राह्मण* में तो यहां तक कहा गया है कि "नारी नर की आत्मा का आधा भाग है।" वैदिक-काल में नारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, शास्त्रों ने तो नारी को देवी आदि उपमाएं देते हुए नारायणी रूप में अलंकृत भी किया। समाज हमेशा परिवर्तनशील रहा है। कालांतर में नारी शनैःशनैः अपने पद से अवनति की ओर जाने लगी। प्राचीन काल से मध्य काल तक आते-आते जब सामंतशाही अहंकार के साथ समर्थों द्वारा दुर्बलों के शोषण का जंगली कानून चला तो उसकी चपेट में नारी भी आ गई। नारी जाति को सामूहिक रूप से हेय, पतित, त्याज्य, पातकी ठहराया गया।

लेखक के अनुसार आधुनिक काल को यदि सुधारवादी काल कहें तो अतिश्योक्ति न होगी। इस युग में ही शोषित मजदूरों के साथ-साथ पीड़ित नारी की मुक्ति का प्रयत्न सही अर्थों में शुरू हुआ तथा उसे कानून और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वह उनसे लाभ उठा रही है। आज नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हुए हर क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रयत्नशील है। लेखक का मानना है कि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब नारी जाग्रत होगी और वे अपने हित-अहित के स्वयं जानकार होंगी।

समीक्ष्य पुस्तक में कुल 17 अध्याय है। प्रथम अध्याय 'परंपरागत नारी' में लेखक ने *ऋगवेद* के आठवें मंडल के 31वें सूत में यज्ञ में महिला की सहभागिता का हवाला देते हुए कई पौराणिक नारियों का विवरण सविस्तार दिया है। आचार्य वृहस्पति द्वारा अगस्त्य ऋषि को लोपामुद्रा के विषय में दिया गया विवरण पतिव्रता स्त्री की महिला का बखान करता है। इसी प्रकार अनेक स्त्रियों के विषय में संदर्भित कथाओं के माध्यम से सद्चरित्र स्त्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है।

पुस्तक का दूसरा अध्याय 'आधुनिक नारी' है। इस अध्याय में नारी की वर्तमान दशा उनकी सोच में हो रहे परिवर्तन तथा उनकी दशा का विवरण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर दिया गया है।

तीसरा अध्याय 'राजनीति में नारी' है। इसमें लोकसभा में महिलाओं की संख्या की तालिका बताकर उनकी भागीदारी की प्रतिशतता इंगित किया गया है। इसमें श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, सुमित महाजन की जीवनी व कर्तव्य को बताया गया है। लेखक यदि राजनीतिक महिलाओं का वरिष्ठता क्रम से विवरण देते तो उपयुक्त होता।

चौथे अध्याय में 'जीवनदायिनी नारी' के रूप में लेखक ने विश्लेषण किया है। लेखक वैज्ञानिक विश्लेषण का हवाला देते हुए कहता है, नारी के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा 'इश्यूनोश्लोबुलिन एस' नामक रक्त प्रोटीन अधिक बनता है जिससे स्त्रियों में प्रतिरक्षा प्रणाली पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती है। इससे स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, सुन्दर और समर्पित दिनचर्या व्यतीत करने वाली होती हैं। इस अध्याय में लेखक ने स्वीकार किया है कि पारिवारिकता ही नहीं, सामाजिकता में भी नारी का महत्व अधिक है। समाज केवल पुरुष वर्ग से ही नहीं बना। वह स्त्री-पुरुष दोनों से ही बना है।

इसी प्रकार अन्य अध्यायों में आत्मनिर्भर नारी, जागरूक नारी, साहसी नारी, शीर्ष पर नारी, ममतामयी नारी, मुस्कान नारी की शान, फैशनपरस्त नारी, सौन्दर्य प्रतीक नारी, विज्ञापनों में नारी, सिनेमा में नारी, सशक्तीकरण, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और खेलकूद में नारी शक्ति हैं।

पुस्तक का उद्देश्य नारी स्वातंत्र्य युग की नारियों को आधुनिक दौड़ में दौड़ती हुई कहीं अंधकार में खो जाने से बचाना है। ❑

RAU'S IAS

WHERE WINNERS LEARN

Amazing Success

Our 2004 Exam Results : Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

Programme Highlights

Civil Service Exam, 2006

- Personal Guidance (English Medium) is available for -

  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.

- **पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -**

  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।

- Postal Guidance in English Medium available for -

  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.

- Postal Guidance in Hindi Medium available for **General Studies** only.

- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

New batches for 2006 Exam, start from 11th November, 2005

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नयी दिल्ली-110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830-32

संपादक : विश्व नाथ त्रिपाठी

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

एस.एस.सी. संयुक्त प्रारम्भिक परीक्षा

(स्नातक स्तर) हेतु

Code 628 मूल्य : 175/-

उपकार की पुस्तकें

गत वर्षों के हल प्रश्न–पत्रों सहित

Code 589 मूल्य : 195/-

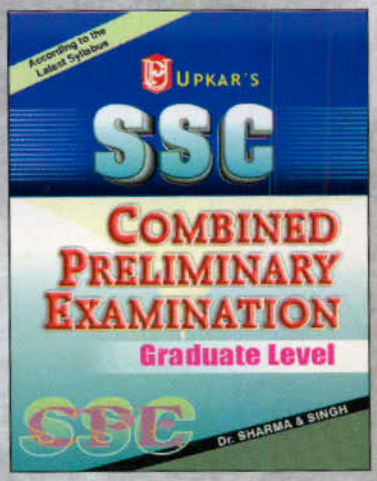

Code 490 Rs. 245/-

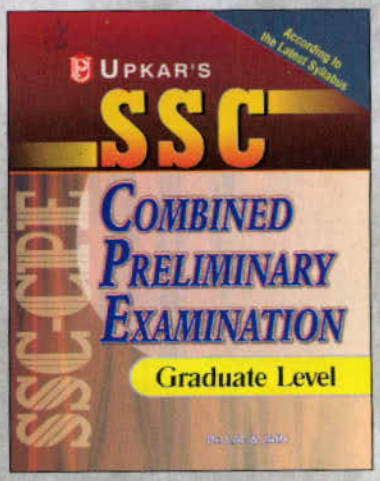

Code 489 Rs. 185/-

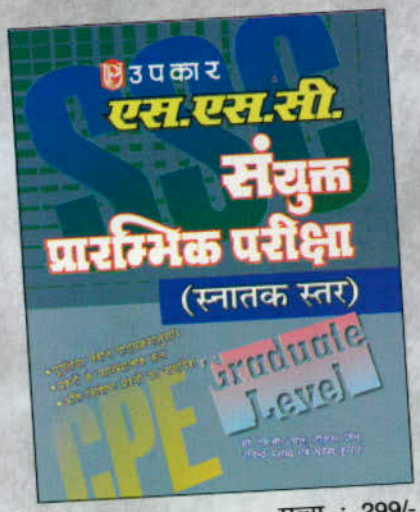

Code 590 मूल्य : 299/-

योग्य और अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषय-सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगी।

उपकार प्रकाशन 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा –2 फोन : 2531101, 2530966, 2602653; फैक्स : (0562) 2531940
• E-mail : upkar1@sancharnet.in • website : www.upkarprakashan.com
ब्रॉंच ऑफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–2 फोन : 23251844, 23251866